चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अखबार

www.chauthiduniya.com

1986 से प्रकाशित

दिल्ली, 20 दिसंबर–26 दिसंबर 2010

मूल्य 5 रुपये

देश का सरकारी तंत्र सड़ने लगा है

पेज-3

आज़ादी के बाद हक़ की लड़ाई

पेज-7

नए ज़माने की ग़ुलामी

पेज-11

साई की महिमा

पेज-12

कांग्रेस महाअधिवेशन

सभी फोटो–*प्रभात पाण्डेय*

संतोष भारतीय

फेसबुक पर राहुल गांधी को दो हज़ार चौदह में प्रधानमंत्री बनाने के लिए प्रचार चल रहा है. यह टेक्नालॉजी का जमाना है, टेलीविज़न का जमाना है, प्रचार का जमाना है, इसलिए हो सकता है कांग्रेस सोच रही हो कि उसके लिए 2014 बहुत आसान होगा. आसान हो भी सकता है, लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता चिंतित है. उसके लिए बिहार एक ऐसे अनुभव की तरह है, जिसे वह चाहकर भी नहीं भुला पा रहा. देश के हर हिस्से के कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बात करने के बाद एक ही बात सामने आ रही है कि जिस तरह उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी का मिशन 2012 इतना धुंधला गया कि ख़ुद राहुल गांधी को अमेठी में कहना पड़ा कि कैसा मिशन 2012, मेरा ऐसा कोई मिशन नहीं है. ऐसे ही कहीं मिशन 2014 भी धुंधलके में न गुम होने लगे.

बिहार की कमान राहुल गांधी ने अपने हाथ में ली थी, लेकिन कमान हाथ में लेना एक बात है, उसकी निगरानी रखना दूसरी बात है. पूरा एक साल जगदीश टाइटलर से झगड़े में प्रदेश अध्यक्ष अनिल शर्मा का गुज़र गया, लेकिन दिल्ली से न कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कोई हस्तक्षेप किया और न महामंत्री राहुल गांधी ने. चुनाव से ठीक पहले दोनों को बदल कर मुकुल वासनिक को प्रभारी और चौधरी महबूब अली कैसर को अध्यक्ष बना दिया. पार्टी खड़ी करने के नाम पर सारी सीटें तो लड़ने का फ़ैसला लिया गया, पर लड़ने वालों में उन सभी को बुला लिया, जिन्हें दूसरे दलों ने खारिज कर दिया था. एक आशा बनी थी कि राहुल गांधी के इस वचन का पालन होगा कि बिहार में नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा टिकट दिए जाएंगे, पर जैसे ही लोगों ने देखा कि नौजवानों के नाम पर जातीय अपराधी, बाहुबली और दाग़ी लोग उम्मीदवार बन रहे हैं, वैसे ही उन्होंने कांग्रेस से अपनी दूरी बना ली. कांग्रेस ने पिछले दो सालों में, विशेषकर लोकसभा के चुनाव के बाद बिहार में न वैचारिक संघर्ष किया और न पार्टी को खड़ा करने की गंभीर कोशिश की. उन्हें लगा कि सभी सीट लड़ेंगे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी प्रचार करेंगे तो कम से कम तीस सीटें तो मिल ही जाएंगी, बिना जामन के दूध दही में नहीं बदलता, लेकिन सिर्फ़ जामन हो और दूध न हो तो? पार्टी संगठन रूपी दूध बिहार में था ही नहीं, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के रूप में जामन घूम रहा था. भीड़ आ रही थी, पर जितनी बड़ी भीड़ आ रही थी, कांग्रेस का उतना ही वोट कम हो रहा था. दो सौ करोड़ रुपये से ज़्यादा का ख़र्च और सीटें सिर्फ़ चार. कार्यकर्ताओं को अफसोस है कि इतने बड़े धक्के के बाद भी पार्टी ने बिहार की हार की न तो समीक्षा की, न कारण तलाशे और न ही कोई सीख ली.

उत्तर प्रदेश की कहानी भी कुछ–कुछ बिहार जैसी ही है. पिछले लोकसभा चुनावों में पार्टी के इक्कीस सांसद उत्तर प्रदेश से आए. कांग्रेस को लगा कि अब यहां नए सिरे से पार्टी को खड़ा किया जा सकता है. राहुल गांधी ने इसकी योजना बनाई. बाबा साहब अंबेडकर के जन्मदिन 14 अप्रैल को अंबेडकर नगर में एक बड़ी सभा हुई, जिसमें राहुल गांधी गए और उन्होंने संदेश यात्राओं की शुरुआत की. दस संदेश यात्राओं को उन्होंने झंडी दिखाई, इनके नेता थे राजेंद्र शर्मा, प्रदीप माथुर, प्रवीण एरन, अब्दुल मन्नान, पी एल पूनिया, जगदंबिका पाल, भोला पांडे, राजेश पति त्रिपाठी, शेखर बहुगुणा तथा रंजीत सिंह जू देव. इन्हें चालीस से पैंतालिस विधानसभा क्षेत्रों में जाना था तथा कांग्रेस का, या सोनिया गांधी और राहुल गांधी का संदेश देकर संगठन बनाना था. अधिकांश नेता केवल आधा लक्ष्य ही पूरा कर पाए. सबसे ज़्यादा भोला पांडे और प्रदीप माथुर ने विधानसभा क्षेत्रों में सभाएं कीं.

इन यात्राओं का काफी स्वागत हुआ. सालों के बाद चुनाव के अलावा कांग्रेस नेताओं की बातें जनता ने सुनीं. बड़ी संख्या में कार्यकर्ता कांग्रेस की ओर आकर्षित हुए. लगा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस फिर से जीवित होने जा रही है. तब तक आ गए पंचायत चुनाव. डेढ़ महीने से चल रही यात्राओं को रोकना पड़ा. इन यात्राओं से उपजे उत्साह और उपजी ताक़त का आकलन राहुल गांधी ने करना उचित नहीं समझा. उन्होंने एक नया कार्यक्रम दे दिया कि सदस्य बनाए जाएं और दल में सभी स्तर पर चुने हुए लोग ही जाएं.

सारे देश में सदस्य बनाए गए. उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश को लेते हैं. ज़िलों–ज़िलों में कांग्रेस के सदस्य बनाने में लोग जुट गए. ऐसा लगा कि संगठन एक बार फिर ज़िंदा होने जा रहा है. लेकिन जब चुनावों की बारी आई तो ऐसे लोग चुने गए, जिन्होंने सदस्य बनाने में कोई खास योगदान नहीं दिया था. कहीं से कोई सूची आई और अध्यक्ष वैसे ही बने. ऐसे ही प्रदेश कांग्रेस समिति जिसे पीसीसी कहते हैं, बनी और ऐसे ही एआईसीसी बनी. कार्यकर्ता समझ ही नहीं पाया कि क्या हो गया. उसे लगा कि राहुल गांधी ने सदस्य बनाने और सही कार्यकर्ताओं को संगठन में आगे आने का सपना दिखाया था, वह सही नहीं था, क्योंकि उन्होंने ख़ुद इस प्रक्रिया पर निगरानी नहीं रखी. ज़्यादातर वे दोबारा काबिज हो गए, जिन्होंने पिछले सालों में निष्क्रियता का रिकार्ड बना लिया था. कांग्रेस के प्रति पैदा होता रुझान ठंडा हो गया. इसीलिए 19 दिसंबर से शुरू हुआ संदेश यात्राओं का दूसरा चरण काफी फीका है. इसमें न उत्साह है और न उत्साही कार्यकर्ता. अफसोस की बात है कि कांग्रेस नेतृत्व इसके पीछे की मानसिकता को अब भी समझना नहीं चाहता.

पर सबसे बड़ा सवाल तो दिल्ली से चल रहे कांग्रेस के केंद्रीय संगठन पर है. कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी हैं. उन्हें सलाह उनके महासचिव देते हैं, उनकी कार्यकारिणी जिसे वर्किंग कमेटी कहते हैं, देती है या कोर ग्रुप देता है या फिर कोई और देता है. कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लगता है कि फ़ैसले ऐसे क्यों होते हैं, जो संगठन को बढ़ाते नहीं, बल्कि संगठन को छोटा करते हैं. दरअसल कांग्रेस में किसी को पता नहीं कि फ़ैसले कौन करता है, जो कांग्रेस अध्यक्ष के नाम से सामने आते हैं.

चाहे संसद का सेंट्रल हॉल हो, जिसमें कांग्रेस के वर्तमान व भूतपूर्व सांसद मिल जाते हैं या सामान्य कार्यकर्ता, जो अनाथों की तरह कहीं भी मिल जाते हैं, एक ही बात कहते हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष को ज़मीनी हक़ीक़त का पता ही नहीं चलता. वे इंदिरा जी के समय को याद करते हैं, जब उन्हें बेहिचक अपने नेता से मिलने का समय मिल जाता था. जिन्हें समय नहीं मिल पाता था, वे जनता दरबार में मिल लेते थे. इंदिरा जी जनता दरबार को बहुत महत्व देती थीं, क्योंकि यह जनता दरबार ही था, जो उन्हें देश की नब्ज़ और पार्टी की कमज़ोरी या मज़बूती की जानकारी देता था. इंदिरा जी इसीलिए अपने साथियों के ऊपर बीस पड़ती थीं और उनके सलाहकार भी उन्हें ग़लत जानकारी नहीं दे पाते थे. कार्यकर्ताओं के पास जनता दरबार एक अचूक अवसर था, जिसमें वे अपनी तकलीफ, अपने सुझाव अपने नेता तक पहुंचा देते थे.

कांग्रेस के लोगों को लगता है कि यदि सोनिया गांधी भी जनता दरबार शुरू करें तो उन्हें भी न केवल देश की नब्ज़, बल्कि पार्टी को मज़बूत करने में आने वाली अड़चन का पता चल सकता है. वह क्यों ऐसा नहीं करतीं, यह कार्यकर्ताओं को तो छोड़ दीजिए, नेताओं तक की समझ में नहीं आता. कांग्रेस कार्यकर्ता बेताबी से उस दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जब जनता दरबार शुरू होगा, वे सीधे अपने नेता से मिल पाएंगे. उनका साफ कहना है कि उसी दिन से कांग्रेस संगठन का फिर से नया जन्म होगा. यही कांग्रेस की संस्कृति है, जिसे कांग्रेस ने छोड़ दिया है.

सोनिया गांधी की नकल करते हुए पार्टी के नेता भी कार्यकर्ताओं से नहीं मिलते, न उनकी राय सुनना चाहते हैं. यही वजह है कि उन्हें ज़मीनी हक़ीक़त की जानकारी नहीं मिल पाती. कांग्रेस की नई संस्कृति यही है, जिसका उदाहरण कांग्रेस के केंद्रीय मंत्री हैं, जो कार्यकर्ताओं से मिलना तो दूर, अपने सांसदों तक से नहीं मिलते.

कांग्रेस में तीन तरह की कार्यशैलियां हैं. कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की कार्यशैली कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह नहीं पैदा कर रही. महासचिव राहुल गांधी की कार्यशैली युवाओं में उत्साह जगाने वाली तो है, पर वह बिना किसी सार्थक परिणाम के शून्य बन जाती है. राहुल गांधी का अपना अलग सचिवालय है, सलाहकार हैं और घूमने की योजनाएं हैं. वह बुद्धिमान और प्रतिभावान लोगों की देश में तलाश कर रहे हैं, जिसे कांग्रेस के लोग टैलेंट हंट कहते हैं. पूरे देश में युवा कांग्रेस का उन्होंने पुनर्गठन किया, नए लोग लिए, लेकिन युवा कांग्रेस और छात्र कांग्रेस देश में पहले से भी ज़्यादा अनजान बन गई है. राहुल गांधी की दो कमज़ोरियां हैं, पहली, वह कभी अपने द्वारा शुरू किए कार्यक्रमों की निगरानी नहीं कर पाते या करना नहीं चाहते और दूसरी, उन्हें समझ में नहीं आता कि समाज का नेता वही हो सकता है, जिसके

(शेष पृष्ठ 2 पर)

यदि सोनिया गांधी भी जनता दरबार शुरू करें तो उन्हें भी न केवल देश की नब्ज़, बल्कि पार्टी को मज़बूत करने में आने वाली अड़चन का पता चल सकता है. वह क्यों ऐसा नहीं करतीं, यह कार्यकर्ताओं को तो छोड़ दीजिए, नेताओं तक की समझ में नहीं आता. कांग्रेस कार्यकर्ता बेताबी से उस दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जब जनता दरबार शुरू होगा, वे सीधे अपने नेता से मिल पाएंगे.

भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अहमद पटेल, सलमान ख़ुर्शीद, प्रणव मुखर्जी, अशोक गहलोत, कनिष्क सिंह, सी.पी. जोशी, मोतीलाल वोरा, परवेज़ हाशमी, जनार्दन द्विवेदी, ग़ुलाम नबी आज़ाद

मुख्यमंत्री राइट टू सर्विस एक्ट के जरिए भ्रष्ट बाबुओं को सबक सिखाना चाहते हैं.

दिल्ली का बाबू

दिलीप चेरियन

थॉमस के समर्थक

परेशानी से जूझ रहे मुख्य सतर्कता आयुक्त पी जे थॉमस को अगले महीने तक के लिए फौरी राहत तो मिल गई, लेकिन अपने अतीत की दागदार छवि के आरोप से वह मुक्त नहीं हो पा रहे हैं. वह खुद को अलग-थलग महसूस कर रहे हैं. बावजूद इसके अपने गृह राज्य केरल के कुछ बाबुओं का समर्थन तो उन्हें मिल ही रहा है. केरल आईएएस ऑफिसर्स एसोसिएशन थॉमस के समर्थन में उतर आया है. एसोसिएशन का यह मानना है कि उनके पूर्व राज्य मुख्य सचिव एक गंदे अभियान का शिकार बन गए हैं. लेकिन दिल्ली में बैठे ऐसे लोग, जो बाबुओं की हर खबर पर नजर रखते हैं, का मानना है कि इस समर्थन से भी थॉमस को कोई खास फायदा नहीं होने वाला है. सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह उनके दागदार करियर का अवलोकन किया और उस पर टिप्पणी की, उससे थॉमस की स्थिति काफी कमजोर हुई है. इसके अलावा दूरसंचार सचिव के रूप में थॉमस का 2-जी स्पेक्ट्रम मामले में जो रोल रहा है, वह भी जांच के दायरे में है. लोग अचंभे में हैं कि आखिर थॉमस अपनी कुर्सी छोड़ क्यों नहीं रहे हैं.

नीतीश कुमार की योजना

नीतीश कुमार के पहले कार्यकाल के दौरान बिहार के सरकारी कार्यालयों में गुणात्मक परिवर्तन लोगों ने महसूस किया. नीतीश ने स्पेशल कोर्ट विधेयक लाकर भ्रष्ट नौकरशाहों की संपत्ति कुर्क करने की व्यवस्था की. सूत्रों के मुताबिक, दो आईएएस अधिकारियों सहित 14 बाबुओं को इस एक्ट के तहत दंडित किया गया. एस एस वर्मा और के पी सिंह को इस कानून के तहत सजा मिली. इस बार भारी बहुमत मिलने के बाद नीतीश प्रशासनिक सुधार के अगले चरण के लिए उत्सुक हैं. मुख्यमंत्री राइट टू सर्विस एक्ट के जरिए भ्रष्ट बाबुओं को सबक सिखाना चाहते हैं. यदि कोई सरकारी अधिकारी समय पर लोगों को सुविधाएं नहीं दे पाता है तो उसे इसके लिए दंडित किए जाने का प्रावधान इस एक्ट में है. जानकारों का कहना है कि इस छोटी सी सफलता के बावजूद नीतीश कुमार की पहचान एक ग्रासरूट सुधारक के रूप में होने लगेगी.

dilipcherian@gmail.com

साउथ ब्लॉक

अभी और इंतजार

1977 बैच के आईएएस अधिकारियों को अपने प्रमोशन यानी सचिव पद पाने के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा. वजह, सरकार अभी 1976 बैच के अधिकारियों का मामला सुलझाने में लगी हुई है. उक्त सभी अधिकारी अभी अतिरिक्त सचिव के पद पर तैनात हैं.

पैनल गठित

टेलीकॉम विभाग में डीडीजी पद को भरने के लिए एक पैनल का गठन कर दिया गया है. यह पद कीर्ति कुमार द्वारा अगस्त 2010 में अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद से खाली है और संयुक्त सचिव के समकक्ष है.

चोपड़ा की जगह रोली

राजस्थान कैडर और 1994 बैच की आईएएस अधिकारी रोली सिंह लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी, मसूरी में उप निदेशक बनकर जा सकती हैं. वह संजीव चोपड़ा की जगह लेंगी. रोली अभी कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में निदेशक पद पर हैं.

आईआईएस बनेंगे जेएस

1984 बैच के आईआईएस अधिकारियों का प्रमोशन होना तय हो गया है. उन्हें जल्द ही भारत सरकार में संयुक्त सचिव बनाया जा सकता है.

सुरेखा बनीं निदेशक

सुरेखा साहू 1996 बैच की आईआरएसईई अधिकारी हैं. उन्हें सामाजिक न्याय मंत्रालय में निदेशक के रूप में नियुक्त कर दिया गया है. यह पद नवसृजित है.

कांग्रेस महाअधिवेशन

पृष्ठ 1 का शेष

मन में समाज के लिए, ग़रीबों के लिए दर्द हो. उनकी रणनीति है कि सरकारी या विदेशी पैसे से चल रहे सामाजिक सेवा के संगठन जिन्हें प्रचलित भाषा में एनजीओ कहते हैं, कांग्रेस की ताक़त बनें. राहुल गांधी को समझना चाहिए कि कांग्रेस की ताक़त उसकी परंपरा में, इंदिरा गांधी की भाषा में और जवाहर लाल नेहरू तथा लाल बहादुर शास्त्री द्वारा देखे गए सपनों में है. इससे अलग यदि कांग्रेस जाती है तो उसमें और भारतीय जनता पार्टी में दफ्तर के पते के अलावा कोई अंतर नहीं रह जाएगा.

सरकार की कार्यशैली इन दोनों से अलग है. सोनिया गांधी की भाषा देश में ग़रीबी के प्रति चिंता दिखाती है. राहुल गांधी की भाषा विकास के उस रास्ते की ओर नज़र डालती है, जिसमें ग़रीब और आदिवासी भी खड़े दिखाई देते हैं. पर सरकार के क़दम इससे बिल्कुल अलग चलते हैं. कैसे मानें कि सरकार सोनिया गांधी और राहुल गांधी की राय के बिना चल रही है. या फिर सरकार ऐसे चल रही है, जिस पर मनमोहन सिंह का प्रधानमंत्री होते हुए भी कोई नियंत्रण नहीं है. कम से कम 2-जी स्पेक्ट्रम प्रकरण और दयानिधि मारन तथा ए राजा का व्यवहार तो यही बताता है.

प्रधानमंत्री और सोनिया गांधी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है. प्रधानमंत्री ने सोनिया गांधी द्वारा दिए कई सुझाव नहीं माने हैं. सोनिया गांधी को भी अब अपने सुझाव लिखकर देने पड़ रहे हैं. जिस तरह ए राजा के सवाल को पीएमओ ने हैंडल किया, वह सोनिया गांधी को बहुत समझ में नहीं आया. पर पी जे थॉमस को सीवीसी बनाने का सुझाव दस जनपथ का था, जिनके ऊपर सर्वोच्च न्यायालय टिप्पणियां किए जा रहा है. सरकार की कार्यशैली की वजह से देश में जो समस्याएं पैदा हो रही हैं, वे लक्षण हैं, लेकिन सोनिया गांधी को समझना चाहिए कि देश के 260 ज़िले इस समय भूख, बेकारी और ग़रीबी से कराह रहे हैं तथा सरकार के ख़िलाफ नक्सलवादियों का साथ दे रहे हैं. जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने थे तो यह संख्या 80 ज़िलों तक सीमित थी. न केवल इस स्थिति को और बिगड़ने नहीं देना है, बल्कि बिगड़ी स्थिति को सुधारने के लिए आर्थिक और राजनैतिक पहल भी करनी आवश्यक है. सरकार की कार्यशैली ने भ्रष्टाचार को एक बार फिर केंद्रीय मुद्दा बना दिया है. सरकार की कार्यशैली की वजह से कांग्रेस कार्यकर्ता का उत्साह इन दिनों ठंडा पड़ा है. इसलिए ज़रूरी है कि नीतियों को सुधारा जाए और जनाभिमुख बनाया जाए. कांग्रेस की सरकार ने सूचना का अधिकार और सौ दिन के रोज़गार की गारंटी जैसे अद्भुत काम किए, लेकिन इन कामों का कोई राजनैतिक फायदा उसे नहीं मिल पा रहा है. क्यों, इसका कारण सोनिया गांधी को तलाशना चाहिए.

फोटो–प्रभात पाण्डेय

बिहार में चार विधायकों का जीतना इसका जीता जागता उदाहरण है.

राहुल गांधी के मुख्य सलाहकारों में कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह हैं, जिनकी रणनीति को क्रियान्वित करने का ज़िम्मा परवेज़ हाशमी पर है. दोनों की जोड़ी ने पहले बिहार में काम किया, बाद में इन्हें आसाम दिया गया, फिर आंध्र. इसके बाद इन्हें उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी के मिशन 2012 को सफल बनाने की ज़िम्मेदारी सौंपी गई. पर अब अचानक इन्हें आसाम भी सौंप दिया गया, जहां अगले वर्ष के शुरू में चुनाव होने वाले हैं. राहुल गांधी के बयानों में राजनैतिक तेवर दिग्विजय सिंह की सलाह पर तीखा या हल्का दिखाई देता है. परवेज़ हाशमी राहुल गांधी को मुस्लिम सवालों पर भी राय देते हैं. इसके अलावा राहुल गांधी का मुख्य काम कनिष्क सिंह संभालते हैं. कांग्रेस के अधिकतर नेता जिन्हें राहुल गांधी से मिलने का वक्त नहीं मिलता, वे कनिष्क सिंह से ही मिलकर गदगद हो जाते हैं.

सोनिया गांधी इन दिनों अहमद पटेल, प्रणव मुखर्जी और ए के एंटनी की सलाह पर फैसले लेती हैं. जनार्दन द्विवेदी के ऊपर मुख्यतया जनता में बोली जाने वाली भाषा के शब्द तैयार करने का काम है. मोतीलाल वोरा जी कोषाध्यक्ष हैं, पर उनकी राय को सोनिया गांधी महत्व देती हैं. इसमें कोई दो राय नहीं कि अहमद पटेल से वह फैसला लेने से पहले मशविरा अवश्य करती हैं. अहमद पटेल इस लिहाज़ से देश के सबसे ताकतवर व्यक्ति हैं, लेकिन इन दिनों उनके ऊपर कुछ आरोप भी लगे हैं और कुछ नाराज़गी भी है. आरोप मुस्लिम समाज लगा रहा है कि अहमद पटेल उसके सवालों को सोनिया गांधी के सामने मज़बूती से नहीं उठाते. नाराज़ उनसे प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि सोनिया गांधी की अलग भाषा के लिए अहमद पटेल ज़िम्मेदार हैं. यह नाराज़गी ओबामा के सम्मान में दिए गए भोज में झलकी, जब सभी को उन्होंने बुलाया, लेकिन अहमद पटेल को नहीं बुलाया. बिहार की हार का ठीकरा या ग़लत रणनीति बनाने का इल्ज़ाम भी अहमद पटेल पर डाला जा रहा है. सबूत के रूप में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद पर महबूब अली कैसर की नियुक्ति और केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर मुकुल वासनिक का नाम लिया जा रहा है.

अहमद पटेल का स्वभाव विनम्र है तथा वह रात दो बजे तक जागकर काम करते हैं. वह सिर्फ़ और सिर्फ़ सोनिया गांधी को सामने रखकर सोचते हैं. यह उनकी ताकत भी है और उनसे बहुत से लोगों की नाराज़गी की वजह भी. दूसरी ओर दिग्विजय सिंह हैं, जो राहुल गांधी के यहां अकेले राजनैतिक सोच वाले व्यक्ति हैं. राहुल गांधी के किसी भी बयान के पक्ष में सबसे पहले वही खड़े होते हैं.

आज कांग्रेस के पास कोई मुस्लिम चेहरा नहीं है. सलमान खुर्शीद और गुलाम नबी आज़ाद हैं, पर इन्हें स्वीकृति नहीं है. परवेज़ हाशमी को कांग्रेस आगे नहीं बढ़ा रही. बिहार में एक कांग्रेस अध्यक्ष बनाया, पर वह बेदम और उच्चवर्गीय मानसिकता वाला निकला. उसने तो चुनाव के फैसले आने से पहले ही हार की सफाई देनी शुरू कर दी. कांग्रेस को सबसे पहले मुस्लिम चेहरा लाना होगा.

कांग्रेस के पास उत्तर में केवल दो राज्य हैं. पहला हरियाणा और दूसरा राजस्थान, जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं. अगर ये दोनों असाधारण काम करें तो इसका फ़ायदा कांग्रेस को दूसरे राज्यों में मिल सकता है. पर अभी तक कोई असाधारण काम नज़र नहीं आया है. अशोक गहलोत की परेशानी है कि उन्हें ज़्यादातर नए लोगों के साथ काम करना पड़ रहा है. साथ ही वहां हर तीसरे महीने अफवाह फैलती है कि डॉ. सी पी जोशी को राहुल गांधी मुख्यमंत्री बनाकर भेज सकते हैं. अशोक गहलोत और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर सोनिया गांधी को नज़र भी रखनी चाहिए और उन्हें सलाह देनी चाहिए कि वे कौन से काम करें, जिससे कांग्रेस को गुजरात, आसाम, तमिलनाडु तथा उत्तर प्रदेश में फ़ायदा मिले.

कांग्रेस कार्यकर्ताओं की चिंता की सीमा नहीं दिखाई देती. उन्हें बंगाल, आसाम, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा गुजरात में पार्टी के चुनावों में संभावित प्रदर्शन को लेकर चिंता है. क्या कांग्रेस यहां गठबंधन बनाएगी या अकेले चुनाव लड़ेगी? बंगाल में राहुल गांधी बयान दे चुके हैं कि उन्हें सम्मानजनक सीटें मिलेंगी, तभी वह ममता बनर्जी का साथ देंगे. उत्तर प्रदेश में क्या कांग्रेस मुलायम सिंह के साथ जाएगी या अकेले या फिर मायावती के साथ समझौता करेगी कि वह राज्य संभालें, केंद्र में कांग्रेस के सांसद जाएं. कार्यकर्ता अंधेरे में हैं, उन्हें यह भी समझ में नहीं आ रहा कि प्रदेश अध्यक्षों की घोषणा हुई, लेकिन घोषणा से पहले माहौल बन गया कि अध्यक्ष बदले जाएंगे. पर ज़्यादातर अध्यक्ष बदले नहीं गए. जिन अध्यक्षों के रहते कांग्रेस की यह हालत है, अब उन्हें ही पुन: बना दिया गया है. कोई योजना संगठन को खड़ा करने की किसी भी प्रदेश अध्यक्ष के पास नहीं है. इन राज्यों के अलावा आंध्र का संकट संकेत दे रहा है कि कांग्रेस वहां कमज़ोर हो रही है. मध्य प्रदेश के बारे में क्या कहें, संगठन लुंज-पुंज हो गया है. अगर कांग्रेस को अकेले चुनाव लड़ना है तो क्यों सांसदों का इस्तेमाल संगठन बनाने में नहीं हो रहा, क्यों उन कार्यकर्ताओं को महत्व नहीं दिया जा रहा है, जो सदस्य बनाने में जी जान लगा चुके हैं. बिहार में ऐसा हो चुका है और उत्तर प्रदेश में यह हो रहा है. कार्यकर्ताओं का मानना है कि 19 सांसदों को सारे विधानसभा क्षेत्र बांट देने चाहिए तथा उन्हें संसद के सत्र के अलावा क्षेत्र में ही रहने का निर्देश देना चाहिए. लेकिन मज़े की बात है कि बिहार में कांग्रेस ने 243 में 20 से 22 सीटें जीतने का लक्ष्य बनाया था और अब वह उत्तर प्रदेश की चार सौ तीन सीटों में से पैंतालिस सीटें जीतने का लक्ष्य बना रही है.

कांग्रेस के सामने संकट है. सरकार की बुद्धिमानी की वजह से भ्रष्टाचार देश के सामने मुद्दा बनके उभर गया है और दूसरी ओर कांग्रेस कार्यकर्ता उत्साहित नहीं हैं. राहुल गांधी का युवा संवाद अर्थ खो रहा है, क्योंकि वह बिहार में युवाओं को चुनाव नहीं लड़ा पाए. इन सबमें अभी भी एक पत्ता कांग्रेस के पास है. वह है प्रियंका गांधी. कांग्रेस कार्यकर्ता अभी भी इस आशा भरे भ्रम में हैं कि यदि प्रियंका गांधी ज़िम्मेदारी लेकर कैंपेन करती हैं तो बंगाल, आसाम, गुजरात, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की किस्मत बदल सकती है. प्रियंका गांधी से कांग्रेस कार्यकर्ता पता नहीं क्यों ज़्यादा सहज संबंध बना लेता है. शायद इसलिए कि वह महिला हैं, या इसलिए कि उनमें समझ ज़्यादा है, पता नहीं, पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का यह भी मानना है कि सोनिया गांधी परंपरागत माओं की तरह पुत्र राहुल पर ही दांव खेल रही हैं, बेटी पर नहीं. हमारा कांग्रेस कार्यकर्ताओं से कहना है कि प्रियंका गांधी भी शायद कुछ न कर पाएं, क्योंकि पूरे कुएं में भांग पड़ी है. और यही चुनौती सोनिया गांधी के सामने है कि कैसे कांग्रेस संगठन को, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को इस भांग के कुएं से दूर ले जाएं.

editor@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
देश का पहला साप्ताहिक अखबार

वर्ष 2 अंक 41
दिल्ली, 20 दिसंबर–26 दिसंबर 2010
RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210-211 सेक्टर 63, नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के- 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय

के-2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग
कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ-2, सेक्टर -11, नोएडा
गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश-201301

फोन न.

संपादकीय 0120-4783999/11-23418962
विज्ञापन + 91 9810017924
प्रसार + 91 9013478398
फैक्स न. 0120-4783950

पृष्ठ-16+4 (बिहार-झारखंड एवं उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड)

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुन: प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

मनमोहन सिंह की नीतियों ने उदारीकरण का मंत्र दिया था. सरकार के कामकाज को कम करने के साथ-साथ निजी कंपनियों को सामाजिक विकास का दायित्व दिया था.

भ्रष्टाचार

देश का सरकारी तंत्र सड़ने लगा है

देश के सरकारी तंत्र में फैला भ्रष्टाचार अपने अंतर्विरोध की वजह से एक्सपोज हो रहा है. आज उद्योगपति के ख़िलाफ़ उद्योगपति, नेता के ख़िलाफ़ नेता, अधिकारी के ख़िलाफ़ अधिकारी, मीडिया के ख़िलाफ़ मीडिया, कोर्ट के ख़िलाफ़ कोर्ट, सब लड़ रहे हैं. जो अब तक देश को लूट रहे थे, अब आपस में लड़ रहे हैं. सवाल यह है कि देश चलाने वालों को जब भ्रष्टाचार के इस राक्षस के बारे में सब कुछ पता था तो वे अब तक चुप क्यों थे. सरकार को यह जवाब देना चाहिए कि भ्रष्टाचार की वजह से देश में जो ग़रीबी, अशिक्षा, बेरोज़गारी और पिछड़ापन है, उसे ख़त्म करने की कार्रवाई क्यों नहीं हुई. या फिर यह मान लिया जाए कि सरकारी कुर्सी पर बैठे सभी लोगों ने देश को सिर्फ़ लूटने का काम किया है. हमारा सरकारी तंत्र भ्रष्टाचार की वजह से सड़ चुका है.

मनीष कुमार

आम बड़ा स्वादिष्ट फल है. यह जब कच्चा होता है तो हम इसे नमक के साथ बड़े चाव से खाते हैं और जब पक जाता है तो यह मीठा हो जाता है, तो और भी खाने लायक हो जाता है. कहने का मतलब यह है कि आम प्राकृतिक तरीक़े से बढ़ता है. अब यह हम पर निर्भर करता है कि हम इसे कच्चा खाएं, अचार बनाएं या फिर पकने का इंतज़ार करें. आम हर हाल में स्वादिष्ट होता है. अगर इसी आम को हम छोड़ दें तो यह सड़ने लग जाएगा. इसका स्वाद ख़त्म हो जाएगा. बीमारी फैलाने वाला फल बन जाएगा. कोई भी तंत्र इसी थ्योरी पर चलता है. किसी तंत्र के सड़ने का मतलब है आंतरिक विरोधाभास पैदा होना. देश में फैले भ्रष्टाचार के साम्राज्य में अंतर्विरोध पैदा होने लगा है. अब यह पूरा तंत्र सड़ने लगा है, इसलिए यह टूटने और बिखरने लगा है. जो लोग पहले मिल-जुलकर देश को लूट रहे थे, आज आपस में लड़ रहे हैं. यही वजह है कि एक अदालत दूसरी अदालत को भ्रष्ट बता रही है, एक राजनीतिक दल दूसरे को घोटालेबाज़ बता रहा है, उद्योगपति एक-दूसरे को जालसाज बता रहे हैं, एक अधिकारी दूसरे अधिकारी के बारे में ख़ुलासा कर रहा है. मीडिया भी इस सड़न से बदबूदार हो रहा है. राजनीतिक दल, सरकारें, अदालतें, ब्यूरोक्रेसी, मीडिया, उद्योगजगत या फिर फिल्मी सितारे सब सड़ चुके हैं. आम का रसास्वादन करने वाले, सरकारी तंत्र से नाजायज फ़ायदा उठाने वाले अब एक-दूसरे पर वार कर रहे हैं. हर तरफ चाकू निकल रहे हैं. यही वजह है कि पिछले पांच महीने में एक के बाद एक घोटाले सामने आ रहे हैं.

हमारा सरकारी तंत्र कैसे चल रहा है, दिल्ली के सत्ता केंद्र में राजकाज कैसे चलता है, यह किसी कैबिनेट सचिव से बेहतर कौन बता सकता है. कैबिनेट सचिव को सरकार की हर गतिविधियों और सरकार के हर फैसले की जानकारी होती है. केंद्र सरकार के ऐसे ही एक कैबिनेट सचिव टी एस आर सुब्रमण्यम रहे हैं. उनका कहना है कि 1970 से ही हमारे सरकारी तंत्र पर उद्योगपतियों का क़ब्ज़ा हो गया था. पूर्व कैबिनेट सचिव कहते हैं कि उन्होंने उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, पेट्रोलियम मंत्रालय, स्टील मंत्रालय और दूरसंचार मंत्रालय को काफी नज़दीक से देखा है. इन मंत्रालयों में पैसे का बड़ा खेल होता है, इसलिए उद्योगपति मधुमक्खी की तरह पैसे कमाने वाले मंत्रालयों में घूमते नज़र आते हैं. सुब्रमण्यम कहते हैं कि जो लोग राज सत्ता से जुड़े हैं, उनके लिए यह बात छुपी नहीं है कि उद्योगपतियों की कमाई न कारखानों, न रिसर्च लेबोरेटरी और न ही बाज़ार से होती है. उद्योगपति दिल्ली के मंत्रालय में अपना पैसा बनाते हैं और यह कोई आज की बात नहीं है, पिछले पांच साल की बात नहीं है, बल्कि यह पिछले तीस से ज़्यादा सालों से चल रहा है. सुब्रमण्यम आगे कहते हैं कि जब भी घोटाला होता है तो राजनेता और नौकरशाह का नाम उजागर होता है, लेकिन ताली बजाने के लिए दूसरे हाथ की ज़रूरत होती है. यह दूसरा हाथ हमेशा बड़े-बड़े उद्योगपतियों का होता है. यह हमेशा अदृश्य रहता है. सुब्रमण्यम कहते हैं कि ज़्यादातर सांसदों का रिश्ता देश के बड़े-बड़े उद्योगपतियों से है, जो उनके फ़ायदे के लिए नियम-क़ानून में फेरबदल करते हैं या फिर उनके लिए लॉबिंग करते हैं. यह कौन नहीं जानता है कि मंत्रालयों में सचिवों की नियुक्ति उद्योगपतियों द्वारा तय की जाती है. यह बात हर इनसाइडर को पता होती है कि जब भी कोई नया पेट्रोलियम सेक्रेटरी आता है तो उसे कौन बनवाता है. किसके कहने पर टेक्सटाइल सेक्रेटरी बनाया जाता है. सब लोग मिल-जुलकर पूरे देश को लूट रहे हैं.

2-जी स्पेक्ट्रम घोटाला एक संकेत मात्र है. इस घोटाले ने पहली बार सरकार एवं उद्योगपतियों के गठजोड़ के बीच के अंतर्विरोध को लोगों के सामने रखा है. देश को 1 लाख 76 हज़ार करोड़ रुपये का घाटा तो हुआ, लेकिन इस घोटाले से देश को यह फ़ायदा हुआ है कि हमारा सरकारी तंत्र कितना सड़ चुका है, यह सामने आ गया. दो उद्योगपति आपस में भिड़ गए. एक टाटा ग्रुप के रतन टाटा और दूसरे राजीव चंद्रशेखर जो एक उद्योगपति हैं, साथ ही राज्यसभा के सदस्य भी हैं. दोनों की लड़ाई से यह बात सामने आई कि किस तरह उद्योगपतियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए सरकार की नीतियां बनती और बिगड़ती हैं. चंद्रशेखर ने यह आरोप लगाया कि ए राजा के घोटाले से रतन टाटा को फ़ायदा हुआ तो रतन टाटा ने कहा कि एनडीए शासन के दौरान सबसे ज़्यादा गड़बड़ियां हुईं. दोनों ने एक-दूसरे पर सरकारी नीतियों को बदलने या उससे फ़ायदा उठाने का आरोप लगाया. देश की जनता के सामने सच्चाई आ गई कि न तो रतन टाटा संत हैं और न ही चंद्रशेखर. हर उद्योगपति जिसे जहां मौक़ा मिलता है, नेता और अधिकारियों के साथ मिलकर नियमों में फेरबदल करता है और मुनाफ़ा कमाता है. चौथी दुनिया में हमने चार महीने पहले ही यह छापा था कि रतन टाटा, अंबानी, ए राजा, नीरा राडिया और देश के बड़े-बड़े पत्रकारों के बीच क्या रिश्ता है. मंत्रालयों में चल रहे भ्रष्टाचार का मायाजाल अपने विरोधाभास में जब फंस जाता है तो बात सामने आ जाती है. भ्रष्टाचार का यह ऐसा स्वरूप है, जिसमें उद्योगपति मुनाफ़ा कमाने के लिए ग्राहकों के पास नहीं, बल्कि मंत्रालय में बैठे मंत्रियों और अधिकारियों के पास जाते हैं. नियम व क़ानून को बदलते हैं और बैठे-बैठाए करोड़ों कमा लेते हैं. यह एक ऐसी लूट है, जहां घर में डाका भी पड़ जाता है और घरवाले को पता भी नहीं चलता. भ्रष्टाचार का यह सुनियोजित तंत्र कई सालों से हमारे देश को खोखला कर रहा है. 2-जी घोटाला या अन्य घोटालों के सामने आने से जनता को इस सवाल का जवाब मिल गया है कि क्यों सरकारी नीतियों का फ़ायदा सिर्फ़ गिने-चुने एक फीसदी लोगों को ही होता है और बाकी के 99 फीसदी लोग इन नीतियों की परिधि से बाहर रहते हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने यह कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में गंदगी आ गई है, कुछ सड़ चुका है. यह टिप्पणी बीते 26 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के बहराइच ज़िले में वक़्फ़ की एक ज़मीन के मामले में सुनवाई के दौरान की. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में कुछ गड़बड़ है और वहां अंकल जज की समस्या और गंभीर हुई है, जिसे रोका जाना ज़रूरी है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, *कुछ जजों के परिवार के सदस्य और नजदीकी रिश्तेदार वहीं पर वकालत कर रहे हैं और वकालत शुरू करने के कुछ ही सालों में जजों के बेटे और रिश्तेदार वकील करोड़पति बन जाते हैं. उनके पास बड़ा बैंक बैलेंस, लग्जरी कार, बंगला आ जाता है. वे विलासितापूर्ण जीवन जीने लगते हैं. हमें खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के कुछ जजों की निष्ठा पर सवाल खड़े हो रहे हैं और हमें उसकी शिकायतें मिल रही हैं.*

सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में दो तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आईं. बार एसोसिएशन ने इसका स्वागत किया और सुप्रीम कोर्ट से इसे रोकने के लिए आगे आने को कहा. वहीं हाईकोर्ट के जजों ने इस मसले पर रजिस्ट्रार के जरिए उस टिप्पणी को हटाने की सुप्रीम कोर्ट से अपील की. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की प्रतिक्रिया और भी तीखी नज़र आई. सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की पैरवी कर रहे वकील से कहा, *यह समय प्रतिक्रिया जाहिर करने का नहीं है, बल्कि अपने अंदर झांकने का भी है.* जस्टिस काटजू ने कहा, *आप यह सब मत बताइए. मैं और मेरा परिवार पिछले कई सालों से इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ा हुआ है. लोग जानते हैं कि कौन भ्रष्ट है और कौन ईमानदार, इसलिए आप यह सब मत बताइए.* जस्टिस काटजू इतने पर ही नहीं रुके. उन्होंने कहा, *कल अगर मार्कंडेय काटजू घूस लेना शुरू कर दें तो सारा देश यह जान जाएगा, इसलिए आप मुझे मत बताइए कि कौन ईमानदार है और कौन भ्रष्ट.* सुप्रीम कोर्ट ने जो सबसे महत्वपूर्ण बयान दिया, वह यह था, *आम लोगों के बारे में यह सब मत बताइए. वे बहुत समझदार हैं. भारत के लोगों को बेवकूफ़ मत समझिए.* यहां भी व्यवस्था में फैले अंतर्विरोध सामने आने लगे हैं. आम सड़ने लगा है. यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट एक हाईकोर्ट के ख़िलाफ़ ऐसी टिप्पणी कर रहा है. अगर यह नहीं रुका तो सुप्रीम कोर्ट के जज भी एक-दूसरे के ख़िलाफ़ बोलने लगेंगे. नोट करने वाली बात यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से यह साफ-साफ कह दिया कि जो लोग सरकारी कुर्सी पर बैठकर भ्रष्टाचार फैलाते हैं, वे देश की जनता को मूर्ख समझते हैं.

हाल के घोटालों से यह भी साबित हुआ है कि भारतीय संसद भ्रष्टाचारियों और घोटालेबाजों की पनाहगार बन चुकी है. हर घोटाले में मंत्री और सांसद का नाम आ जाता है. पहले आदर्श घोटाला, फिर 2-जी स्पेक्ट्रम मामले में भारतीय जनता पार्टी ने जेपीसी की मांग की, लेकिन ख़ुद ही विरोधाभास में फंस गई, जब कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदुरप्पा का नाम ज़मीन घोटाले में सामने आया. 2-जी स्पेक्ट्रम घोटाले पर सरकार की स्थिति नाजुक होने लगी तो 2001 से जांच का ऐलान कर दिया गया. भाजपा बैकफुट पर आ गई. संसद में जो हो रहा है, राजनीतिक दलों के नुमाइंदे जो कुछ कर रहे हैं, वह राजनीति है. देश की जनता तो यह चाहती है कि आज़ादी के बाद जितने भी घोटाले हुए हैं, उन सबकी जांच हो. सभी गुनहगारों को जेल भेजा जाए. लेकिन राजनीति और भ्रष्टाचार के इस अनोखे गठजोड़ में जनता की चाहत की किसे परवाह है. अच्छी बात यह है कि सभी राजनीतिक दल एक-दूसरे को घोटालेबाज साबित करने में लगे हैं. यह संस्थागत भ्रष्टाचार में उभरे अंतर्विरोध का नतीजा है. सब बेनकाब हो रहे हैं.

मनमोहन सिंह की नीतियों ने उदारीकरण का मंत्र दिया था. सरकार के कामकाज को कम करने के साथ-साथ निजी कंपनियों को सामाजिक विकास का दायित्व दिया था. इसे हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहते हैं. हाल के दिनों में हुए घोटाले चाहे वह आईपीएल हो, कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला हो या फिर 2-जी स्पेक्ट्रम, सरकारी अधिकारियों के साथ मिल कर निजी कंपनियों ने इन्हें अंजाम दिया. उदारीकरण के वे समर्थक कहां हैं, जो यह कहते थे कि सरकार के कामों में निजी कंपनियों के आने से देश से भ्रष्टाचार कम हो जाएगा. उदारीकरण के सारे मसीहा इन घोटालों पर चुप हैं. अब देश की जनता के सामने एक ही सवाल है कि भरोसा करने लायक कौन बचा है. ऐसे माहौल में सरकार के सभी अंगों का पहला दायित्व यह है कि वे सबसे पहले जनता का भरोसा जीतें. हर राजनीतिक दल को यह याद रखना चाहिए कि भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ देश के लोगों में गुस्सा है. यह गुस्सा अगर सड़क पर प्रदर्शित होने लगा तो यह देश किसी के संभाले नहीं संभलेगा. देश की जनता ने बोफोर्स घोटाले की वजह से कांग्रेस की सरकार को सज़ा दी थी. आज जिस स्तर पर घोटाले हो रहे हैं, उसके सामने बोफोर्स घोटाला बहुत ही छोटा है.

जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह वक्त आत्ममंथन करने का है. हाल में तीन बड़े घोटाले हुए हैं- कॉमनवेल्थ गेम्स, आदर्श सोसाइटी और 2-जी स्पेक्ट्रम. देश की सरकार, संसद, सुप्रीम कोर्ट के सामने चुनौती है. इन तीनों घोटालों में जो भी अधिकारी, नेता, उद्योगपति या मंत्री शामिल हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो. हमारे देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है, जो दूध का दूध पानी का पानी कर सकें. ऐसे ईमानदार लोगों को सारी फाइलें, सारे अधिकार दिए जाएं. इन मामलों पर सुप्रीम कोर्ट दिन-रात सुनवाई करे, ताकि तीन महीने के भीतर देश की जनता को यह पता चल सके कि इन घोटालों के पीछे कौन-कौन लोग थे. गुनहगारों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, उन्हें जेल भेजा जाए, तभी यह सरकारी तंत्र देश की जनता का भरोसा हासिल कर पाएगा और भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ लड़ाई शुरू हो सकेगी.

manish@chauthiduniya.com

दिल्ली के सत्ता केंद्र में राजकाज कैसे चलता है, यह किसी कैबिनेट सचिव से बेहतर कौन बता सकता है. कैबिनेट सचिव को सरकार की हर गतिविधियों और सरकार के हर फैसले की जानकारी होती है. केंद्र सरकार के ऐसे ही एक कैबिनेट सचिव टी एस आर सुब्रमण्यम रहे हैं. उनका कहना है कि 1970 से ही हमारे सरकारी तंत्र पर उद्योगपतियों का क़ब्ज़ा हो गया था.

- **सुप्रीम कोर्ट ने कहा- यह समय प्रतिक्रिया जाहिर करने का नहीं है, बल्कि अपने अंदर झांकने का भी है.**
- **सुप्रीम कोर्ट ने कहा- आम लोगों के बारे में यह सब मत बताइए. वे बहुत समझदार हैं. भारत के लोगों को बेवकूफ़ मत समझिए.**
- **जस्टिस काटजू ने कहा- आप यह सब मत बताइए. मैं और मेरा परिवार पिछले कई सालों से इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ा हुआ है. लोग जानते हैं कि कौन भ्रष्ट है.**

हाल के दिनों में हुए घोटाले चाहे वह आईपीएल हो, कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला हो या फिर 2-जी स्पेक्ट्रम, सरकारी अधिकारियों के साथ मिल कर निजी कंपनियों ने इन्हें अंजाम दिया. उदारीकरण के वे समर्थक कहां हैं, जो यह कहते थे कि सरकार के कामों में निजी कंपनियों के आने से देश से भ्रष्टाचार कम हो जाएगा.

कबरई सहित निकटवर्ती डेढ़ दर्जन गांवों के खेत आज इसकी खुली गवाही दे रहे हैं. इस काम से जुड़े मजदूर भी इससे ख़ुश नहीं हैं.

क्रशरों का क़हर

लोगों का जीना दूभर

यूं तो बुंदेलखंड के वीरों की गाथाएं एवं दंतकथाएं विश्वविख्यात हैं, लेकिन यहां के मौजूदा हालात मरता क्या न करता जैसे हैं. गड्ढों में तब्दील हो चुके पहाड़ और अंधाधुंध खनन बुंदेलखंड की सबसे बड़ी त्रासदी है. कभी चंदेलकालीन सरोवरों एवं देशावरी पान के लिए प्रसिद्ध बुंदेलखंड आज अपनी पहचान के लिए खनिज उद्योग का मोहताज है. जब-जब बुंदेलखंड की बदहाली का शोर उठा तो शासन-प्रशासन ने खनिज उद्योग का हवाला देकर उसे दबा दिया. बुंदेलखंड सदियों से विंध्य पर्वत श्रंखला का गढ़ माना जाता है, लेकिन अब न केवल पर्वतों का अस्तित्व संकट में है, बल्कि उनकी मौजूदगी ने यहां के किसानों एवं मजदूर तबके की मुश्किलें भी बढ़ा दी हैं. क्रशर उद्योग को काल मानने वालों की संख्या अकेले महोबा जनपद में 20 से 25 हज़ार है.

किसी क्षेत्र की बदहाली दूर करने की बात उठे और उद्योगों का जिक्र न हो, यह मुमकिन नहीं, लेकिन जब कोई कहे कि उद्योग ही उस क्षेत्र की बदहाली का कारण है तो यह हजम करना मुश्किल होगा, पर बुंदेलखंड की ज़मीनी हक़ीक़त कुछ ऐसी ही है. झांसी, हमीरपुर, चित्रकूट, बांदा और महोबा में उद्योग की शक्ल अख्तियार कर चुके क्रशर लोगों के लिए जी का जंजाल बन गए हैं. क्रशरों से उड़ने वाली धूल के चलते हज़ारों बीघा कृषि भूमि बंजर हो चुकी है. विस्फोट के समय पत्थर टूटकर खेतों पर गिरते हैं, नतीजा मुंह का निवाला भी छिन जाता है. रही-सही कसर क्रशरों को कच्चे माल की आपूर्ति करने वाले वाहन फसल रौंद कर पूरी कर देते हैं. कुछ लोगों ने धूल से खेती को होने वाले नुक़सान के बारे में ज़िला कृषि अधिकारी से जन सूचना अधिकार के तहत जानकारी मांगी तो उन्होंने यह तो माना कि पत्थरों की धूल उत्पादन क्षमता पर प्रतिकूल असर डालती है, लेकिन वह इससे भूमि के बंजर होने संबंधी सवाल का कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे सके.

कबरई सहित निकटवर्ती डेढ़ दर्जन गांवों के खेत आज इसकी खुली गवाही दे रहे हैं. इस काम से जुड़े मजदूर भी इससे ख़ुश नहीं हैं. वर्ष 2008 में इस कारोबार की भेंट चढ़ चुके भोजा का परिवार हो या फिर अपने हाथ-पैर गंवाने वाले तुलाराम, पिंटू, शिव नारायण एवं बलवंत, सभी का मानना है कि कबरई अब मौत की मंडी बन गया है. व्यापारी भी इस उद्योग से परेशान हैं. क्रशर उद्योग में लगे ओवर लोड वाहनों के आवागमन के चलते यहां सड़कों का नामोनिशान मिट गया है. लोगों को 185 किलोमीटर के सफर में पांच-सात घंटे बर्बाद करने पड़ते हैं. कपड़ा व्यापारी शंकर सिंधी हों या किराना व्यापारी सलीम, सब्जी का कारोबार करने वाले इसराइल हों या दवा विक्रेता अतुल शर्मा, सभी यही कहते हैं कि सड़कों की दुर्दशा के लिए क्रशर उद्योग ज़िम्मेदार है. ऐसा नहीं है कि प्रशासन इससे अनभिज्ञ है, पर निजी स्वार्थों और उद्योग से जुड़े लोगों की ऊंची पहुंच के चलते वह मजबूर है. तत्कालीन मंडलायुक्त विजय शंकर पांडेय एवं महोबा के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक अजय मिश्रा को स्थानांतरण और अपमान का दंश झेलना पड़ा, क्योंकि उन्होंने क्रशर स्वामियों पर शिकंजा कसने की हिमाकत की थी. इन अधिकारियों की जनता के प्रति सकारात्मक सोच ही इनकी दुश्मन बन गई थी.

माननीयों की हुकूमत

क्रशर उद्योग भारी मुनाफ़ा कमाने का एक शॉर्टकट रास्ता है. जहां बात सरल तरीक़े से अधिक लाभ कमाने की हो तो वहां गरीब या छोटी पूंजी वाले लोग कैसे टिक सकते हैं. इसलिए यहां राजनीतिक पहुंच रखने वालों अथवा पैसे वालों की तूती बोल रही है. कबरई के क्रशर उद्योग पर वही लोग काबिज़ हैं, जो इस समय सत्ता में हैं या पहले सत्ता में रह चुके हैं. कबरई सहित ज़िले के विभिन्न हिस्सों में आबाद इन मौत की दुकानों पर अधिकांशत: सफेदपोशों का ही क़ब्ज़ा है. आज यहां पूर्व एमएलसी जयवंत सिंह, पूर्व विधायक अरिमर्दन सिंह, कुंवर बहादुर मिश्रा एवं पूर्व मंत्री सिद्ध गोपाल साहू की तूती बोलती है. वर्तमान सरकार में कैबिनेट मंत्री बादशाह सिंह, ददू प्रसाद एवं बसपा सांसद विजय बहादुर सिंह सरीखे लोग इस कारोबार से जुड़े हैं. मुख्यमंत्री मायावती के खासमखास एवं खनिज विभाग के मुखिया बाबू सिंह कुशवाहा भी इस उद्योग का अहम हिस्सा हैं. परोक्ष न सही, पर अपरोक्ष रूप से माननीय के कई क्रेशर आबाद हैं. दर्जनों पहाड़ों पर इनके नाते-रिश्तेदार वैध-अवैध खदानें चला रहे हैं. नियमों को रौंदकर चलते इनके क्रशरों पर हाथ डालने का साहस प्रशासन के वश की बात नहीं है. अजय मिश्रा एवं आलोक कुमार जैसे ईमानदार अधिकारियों ने यह गलती की तो उनका तबादला कराकर माननीयों ने अपनी ताक़त का एहसास करा दिया. यही वजह है कि अब कोई अधिकारी इस ओर देखने की जुर्रत भी नहीं करता. इस कारोबार में सपा के चौधरी छत्रपाल यादव, कबरई नगर पंचायत के अध्यक्ष शिवपाल तिवारी, भाजपा के पूर्व ज़िलाध्यक्ष दीप प्रकाश द्विवेदी, भाजपा नेता डॉ. ज्ञानेश अवस्थी एवं कबरई ब्लॉक के पूर्व प्रमुख जीतेंद्र शुक्ल का जलवा भी देखने लायक़ है. खनिज अधिकारी मुइनुद्दीन को दो जनपदों का प्रभार सौंपा जाना उनकी वफादारी का ईनाम है. इसी प्रकार विजय विश्वास पंत की डीएम के रूप में खेली गई त्रिवार्षिक पारी को भी लोग माननीयों को ख़ुश रखने का नतीजा बता रहे हैं. इन अधिकारियों ने अपने इष्ट मित्रों-रिश्तेदारों की भी क़िस्मत चमका दी है. भटीपुरा निवासी एक कथित नंबरदार के पास कभी एक पहाड़ का पट्टा हुआ करता था, लेकिन आज उसके पास दो पहाड़ों के पट्टे हैं. इसकी वजह ज़िलाधिकारी और खनिज अधिकारी से उसकी निकटता बताई जाती है.

यहां न नियम हैं, न क़ानून

कबरई में चल रहे खनन कार्य में जिस प्रकार भारी क्षमता वाली विस्फोटक सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है, वह बेहद चिंताजनक है. सुरक्षा के लिहाज़ से यह और भी संवेदनशील है, क्योंकि यह काम अप्रशिक्षित लोगों के हाथ में है. नियमों के मुताबिक़, विस्फोट दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच होना चाहिए, लेकिन यहां तो जब खदान मालिक का मन होता है, डायनामाइट बिछाकर आग लगा दी जाती है. भारी क्षमता के विस्फोटक का इस्तेमाल होने से पहाड़ों के इर्द-गिर्द स्थित मकानों में दरारें पड़ गई हैं. क़स्बे में बना विद्यालय इस कथन की पुष्टि करता है. खदान और क्रशर मालिक मजदूरों की सुरक्षा से जुड़े नियमों को लेकर भी उदासीन हैं. हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी के दो क्रेशरों को छोड़कर शेष कहीं भी डॉक्टर तैनात नहीं है. मजदूर प्राथमिक उपचार के अभाव में मर जाते हैं या फिर अपाहिज हो जाते हैं. यहां मजदूरों को काम करते समय मास्क और हेलमेट आदि भी नहीं उपलब्ध कराए जाते. कबरई में सर्व शिक्षा अभियान दम तोड़ रहा है. यहां बच्चों के हाथों में हथौड़ी नज़र आना कोई नई बात नहीं है.

सांसों में घुलता ज़हर

झांसी से लेकर चित्रकूट तक फैली विंध्य पर्वत श्रंखला का अस्तित्व ख़तरे में है. जिस रफ्तार से पहाड़ों का खनन किया जा रहा है, उससे लगता है कि कुछ समय बाद सारे पर्वत जमींदोज हो जाएंगे. अकेले महोबा में विलुप्त हो चुके पहाड़ों की संख्या काफी है. कबरई के लौंडा एवं रमकुंडा पहाड़ों को ही लें, आज वहां जगह-जगह तीन-तीन सौ फुट गहरी खाई दिखाई पड़ती है. यही हाल पचपहरा, डहर्रा, जमाला, कुम्हरौड़ा एवं गौरहारी के पहाड़ों का है. पानी की कमी का सामना कर रहे महोबा-बुंदेलखंड की स्थिति और अधिक बिगड़ने के संकेत मिलने लगे हैं. पहाड़ों के ख़त्म होने का सीधा अर्थ है भूजल स्तर में गिरावट. क्रशर उद्योग पर्यावरण संतुलन को भी नुक़सान पहुंचा रहा है. कबरई के आसपास क़रीब 20 किलोमीटर की परिधि में बसे गांवों के लोग टीबी जैसी घातक बीमारी की चपेट में हैं. दो दर्जन गांवों की लगभग 90 हजार आबादी आंशिक रूप से बीमार है. पिछले साल कबरई के सामाजिक कार्यकर्ता मंगल सिंह ने जब जिला अस्पताल से जानकारी मांगी तो बताया गया कि उड़ती धूल का स्वास्थ्य पर ज़्यादा प्रतिकूल असर नहीं पड़ता. हालांकि इससे सिलीकोसिस, क्रानिक एवं ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी जैसी बीमारियां हो सकती हैं. दूसरी ओर कबरई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों की एक लंबी कतार देखने को मिली. इनमें नाक, कान एवं गले के रोगियों की संख्या ख़ासी थी. इलाज के इंतजार में बैठे रमसुखा, घुटइया, परसू एवं विमला देवी ने बताया कि यह रोग यहां आम बात है. कबरई में क्रशर उद्योग के असर को लेकर सरकारी मशीनरी और स्वास्थ्य विभाग का रवैया गुमराह करने वाला है. एक निजी चिकित्सक कहते हैं कि यहां की आबोहवा

सेहत के लिहाज़ से बेहद घातक है. हवा में हमेशा 4-5 माइक्रोन के कण मौजूद रहते हैं, जो श्वांस नली की एल्वोलाई में फंसकर उसे चोक कर देते हैं, जिससे सांस की बीमारी हो जाती है और शरीर की रक्त शोधन क्षमता कम होने के साथ-साथ पाचन तंत्र भी गड़बड़ा जाता है. परिणामस्वरूप लोग धीरे-धीरे अस्थमा के मरीज बन जाते हैं.

पिछले साल ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के मंडल अध्यक्ष दिनेश खरे ने कई बार धरना-प्रदर्शन किया. इसके बाद बांदा के तत्कालीन मंडलायुक्त एस सी सक्सेना ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सभी क्रशरों का निरीक्षण कराया. 11 क्रशरों को बंद करने के आदेश दिए गए. महोबा के तत्कालीन जिलाधिकारी आलोक कुमार ने भी कबरई के वातावरण में प्रदूषण की जांच कराई. जांच परिणाम न केवल चौंकाने वाले थे, बल्कि बेहद डरावने थे. जांच रिपोर्ट के अनुसार, हवा में छोटे-छोटे कणों की मात्रा जहां 200 माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर होनी चाहिए, वहीं कबरई में यह मात्रा 1800 माइक्रोग्राम पाई गई, जो सामान्य से नौ गुना ज़्यादा है. आलोक कुमार ने सभी क्रशरों को पर्यावरण सुरक्षा संबंधी उपाय अपनाने के निर्देश जारी किए, पर इससे पहले कि क्रशर मालिकों की मनमानी पर लगाम लग पाती, इन दोनों अधिकारियों को चलता कर दिया गया. खनिज विभाग के अनुसार, वर्तमान में यहां 225 पहाड़ों पर करीब 300 पट्टाधारक काबिज हैं, जबकि पिछले एक दशक में क्रशरों की संख्या दो सौ से अधिक हो चुकी है. अभी हाल में राजधानी से आए अधिकारियों की एक टीम ने जांच-पड़ताल के बाद कई पट्टों के निरस्तीकरण और कई क्रशरों को बंद किए जाने की घोषणा की थी, लेकिन थोड़े समय बाद यह घोषणा भी ठंडे बस्ते में चली गई.

इसरार पठान
feedback@chauthiduniya.com

मीडिया रिपोर्टों से पता चलता है कि परेश बरुआ को छोड़कर उल्फा के ज़्यादातर नेता गिरफ़्तार हो चुके हैं या हथियार डाल चुके हैं. कुछ नेताओं को सेफ पैसेज दिया गया है.

बिहार

नरसंहार की आशंका से सहमी ज़िंदगी

राजेश सिन्हा

खगड़िया–मुंगेर सीमा स्थित बरियारपुर बहियार में अपराधी मुरारी सिंह ने दर्जनों नक्सलियों को मौत के घाट उतार कर उनके अत्याधुनिक हथियार लूट लिए. उसने पहले नक्सलियों को आमंत्रित किया और फिर भोजन में ज़हर मिला दिया. इसके बाद मुरारी सिंह एवं उसके साथियों ने अचेत नक्सलियों को काट डाला और उनके शव के टुकड़े नदी में फेंक दिए. नदियों के गर्भ से निकली ज़मीन पर मालिकाना हक़ जताने और जल कर विवाद के कारण दियारा इलाक़े में वर्षों से ख़ून की होली खेली जाती रही है, लेकिन इस बार बरियारपुर बहियार में दर्जनों नक्सलियों को मौत के घाट उतार कर अपराधियों ने नरसंहार की नई पृष्ठभूमि तैयार कर दी है. यह सोचकर न केवल गांव वाले ख़ौफ़ज़दा हैं, बल्कि पुलिस–प्रशासन के भी हाथ–पांव फूलने लगे हैं. ग्रामीणों का दिन जहां पुलिस कैम्प में कटता है, वहीं शाम होते ही वे घरों में दुबक जाते हैं. घर में दुबकने के बाद भी उन्हें रतजगा करना पड़ता है. बताते हैं कि कोसी के कुख्यात अपराधी मुरारी सिंह की नज़र पिछले काफ़ी समय से नक्सलियों के अत्याधुनिक हथियारों पर थी. इसलिए उसने योजनाबद्ध तरीक़े से उन्हें खाने पर बुलाया और ज़हरीला भोजन खिलाकर हथियार लूट लिए. इसके बाद उसने नक्सलियों के शवों को टुकड़ों में विभक्त कर नदी में बहा दिया. अभी तक केवल चार शव बरामद हो सके हैं. इस घटना में मुरारी सिंह भी मार गिराया गया. अन्य शवों की बरामदगी के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है.

घटना के एक प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार, गंगा और गंडक के बीच बरियारपुर दियारे के जलकर को लेकर अपराधी मुरारी सिंह एवं धरनीधर यादव गिरोह के बीच रंजिश चल रही थी. मुरारी सिंह हथियारों और आदमियों के मामले में जब धरनीधर के सामने कमज़ोर पड़ने लगा तो उसने इलाक़े में सक्रिय नक्सलियों से हाथ मिलाना शुरू कर दिया. नक्सलियों का मुरारी सिंह गिरोह से लगाव धीरे–धीरे बढ़ता चला गया. जब दोस्ती प्रगाढ़ हो गई, तब मुरारी ने नक्सलियों को भोजन पर आमंत्रित किया. इस मौक़े पर लिट्टी और मछली के साथ–साथ शराब का भी प्रबंध किया गया. पड़ोस की एक महिला ने नक्सलियों को परोसे जाने के दौरान ही भोजन में ज़हर मिला दिया. पहले नक्सलियों ने जमकर शराब पी, इसके बाद जैसे ही भोजन शुरू किया, उनकी हालत ख़राब होने लगी. तभी मौक़ा देख मुरारी सिंह ने नक्सलियों की सुरक्षा में खड़े उनके साथियों पर गोली चला दी. अपने साथी नक्सलियों को ढेर होता देख अन्य नक्सलियों ने मुरारी सिंह एवं उसके भतीजे को मौक़े पर ही मार गिराया. जवाबी गोलीबारी में कई नक्सली मारे गए.

बताया जाता है कि नक्सलियों के पास दो कारबाइनों सहित दस हथियार थे. घटना की जानकारी मिलते ही एसपी खगड़िया सुधांशु कुमार एवं एसपी मुंगेर के आदेश पर पुलिस वहां पहुंच गई. खगड़िया, मुंगेर, लक्खी सराय एवं बांका पुलिस ने कांबिंग तेज़ कर दी है. एक पुलिस पदाधिकारी ने बताया कि खगड़िया और मुंगेर पुलिस को मामले की जांच का आदेश दिया गया है. अब जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि इस घटना को अंजाम देने के पीछे असली मक़सद क्या था और इसका मुख्य सूत्रधार कौन है, लेकिन इतना तय है कि पुलिस अगर थोड़ी भी सुस्त पड़ी तो एक बड़े नरसंहार की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता.

feedback@chauthiduniya.com

दर्जनों गांव दहशत में

खगड़िया–मुंगेर सीमा क्षेत्र अंतर्गत बरियारपुर दियारा के लगभग दर्जन भर गांव के लोग नरसंहार की आशंका से ज़िंदा लाश बन चुके हैं. विकास के मामले में बेहद पिछड़े हिरणमार, लक्ष्मीपुर, रेता, भेलवा एवं हंसु सिंह टोला सहित दर्जनों गांव के लोगों की ज़िंदगी ख़तरे में है. ग्रामीणों का कहना है कि अपराधियों ने अपने स्वार्थ के लिए नक्सलियों को मार डाला, लेकिन अब वे लोग नक्सलियों द्वारा जवाबी कार्रवाई के भय से खेती–बारी करने के बजाय दिन में पुलिस कैम्प में शरण लिए रहते हैं और रात में घर में जागते रहते हैं. हंसु सिंह टोला के कामदेव सिंह का कहना है कि अपराधियों ने हमारी ज़िंदगी से खिलवाड़ किया है. नक्सली बार–बार कह रहे हैं कि उनके साथियों से लूटे गए हथियार अगर वापस नहीं मिले तो जन अदालत लगाकर सभी गांवों के लोगों को सज़ा दी जाएगी. उमा यादव का कहना है कि नक्सली इलाक़े में विचरण ज़रूर करते थे, लेकिन हमें कोई हानि नहीं पहुंचाते थे. ग्रामीणों का ख़ौफ़ कम करने और नक्सलियों–अपराधियों के विरुद्ध कांबिंग के लिए दियारे में घुड़सवार पुलिस तैनात कर दी गई है.

असम

शांति वार्ता के लिए तैयार हो रही ज़मीन

दिनकर कुमार

प्रतिबंधित संगठन उल्फा और केंद्र सरकार के बीच शांति वार्ता के लिए सकारात्मक माहौल तैयार हो रहा है. राजनीतिक प्रेक्षकों का मानना है कि तमाम अनिश्चितता, असुविधा, मंथर गति, क़ानूनी अड़चनों के बावजूद 2011 में होने वाले असम विधानसभा चुनाव से पहले उल्फा और सरकार की बातचीत शुरू हो सकती है. बांग्लादेश में शेख हसीना की सत्ता में वापसी, केंद्रीय गृहमंत्री पी चिदंबरम की विशेष तत्परता और बांग्लादेश में रह रहे उल्फा नेताओं पर बढ़ते दबाव के चलते उनके असम आगमन के बाद संकेत मिलने लगा था कि उल्फा और सरकार के बीच शांति वार्ता का मार्ग प्रशस्त हो सकता है. पिछले महीने असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने कहा कि बांग्लादेश में रहने वाले उल्फा के अधिकांश नेता असम लौट चुके हैं और असम सरकार म्यांमार में रहने वाले उल्फा कैडरों एवं नेताओं को सेफ पैसेज देने के लिए तैयार है. गोगोई ने कहा कि अगर उल्फा या एनडीएफबी के 80 फ़ीसदी सदस्य शांति वार्ता में शामिल होने के लिए तैयार हैं तो हमें परेश बरुआ या रंजन दैमारी की सहमति का इंतज़ार करने की कोई ज़रूरत नहीं है. केंद्रीय गृहमंत्री शांति वार्ता के लिए शर्त रख चुके हैं कि उग्रवादियों को हिंसा रोकनी होगी, हथियार डालने होंगे और संप्रभुता की मांग छोड़नी होगी.

मीडिया रिपोर्टों से पता चलता है कि परेश बरुआ को छोड़कर उल्फा के ज़्यादातर नेता गिरफ़्तार हो चुके हैं या हथियार डाल चुके हैं. कुछ नेताओं को सेफ पैसेज दिया गया है. भीमकांत बूढ़ागोहाईं, प्रदीप गोगोई, मिथिंगा दैमारी एवं राजू बरुआ आदि नेताओं को जमानत पर रिहा कर दिया गया है. सरकार की तरफ़ से वार्ता के लिए अनुकूल माहौल तैयार करने की कोशिश चल रही है. केंद्र और राज्य सरकार उल्फा के सेनाध्यक्ष परेश बरुआ को छोड़कर बाक़ी तमाम नेताओं को शांति वार्ता के लिए राजी कर चुकी है और ऐसा लगता है कि वार्ता की राह की सबसे बड़ी रुकावट संप्रभुता की मांग छोड़ने के लिए उल्फा के नेता सहमत हो चुके हैं. अपने नौ साल के कार्यकाल में मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने शांति प्रक्रिया शुरू करने के लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं किया. विधानसभा चुनाव सामने देखकर वह इसके लिए सक्रिय हुए. उनके राजनीतिक विरोधी कहते हैं कि चुनावी फ़ायदे को ध्यान में रखकर ही गोगोई सरकार इस मसले पर गंभीरता दिखा रही है. जेल से रिहा होने के बाद उल्फा के सलाहकार 84 वर्षीय भीमकांत बूढ़ागोहाईं ने उल्फा अध्यक्ष अरविंद राजखोवा समेत तमाम नेताओं को रिहा करने की मांग की, ताकि संगठन की केंद्रीय समिति और साधारण परिषद की बैठक आयोजित कर संप्रभुता की मांग के बग़ैर शांति वार्ता के पक्ष में निर्णय लिया जा सके. उस स्थिति में परेश बरुआ को बहुमत का निर्णय स्वीकार करना पड़ेगा या अपनी जिद पर अड़े रहने के कारण अलग–थलग रहना होगा. तीन दशकों से असम में हिंसा का दौर जारी है और जनता हिंसामुक्त माहौल तैयार करने के लिए बातचीत पर जोर देती रही है. जाने–माने बुद्धिजीवी डॉ. हीरेन गोहाईं जेल में बंद उल्फा नेताओं से मिलकर वार्ता के लिए ज़मीन तैयार करते रहे हैं. उनके नेतृत्व में ही वार्ता के पक्ष में एक सम्मेलन आयोजित हो चुका है. दूसरी तरफ़ इंटेलिजेंस ब्यूरो के पूर्व प्रमुख पी सी हालदार को केंद्र की तरफ़ से मध्यस्थ बनाया गया है. हालदार कई बार जेल में बंद उल्फा नेताओं से बातचीत कर चुके हैं. वार्ता के समर्थन में गठित संस्था जातीय अभिवर्तन के मुख्य संयोजक डॉ. हीरेन गोहाईं सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं कि शांति प्रक्रिया की रुकावटें दूर हो गई हैं और वार्ता शुरू होने की संभावना नज़र आने लगी है.

मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे हालदार को जहां वार्ता की शर्तों का निर्धारण करना होगा, वहीं जेल में बंद उल्फा नेताओं की रिहाई का रास्ता भी सुगम बनाना होगा. परेश बरुआ के बिना वार्ता को सही अंजाम तक पहुंचा पाना कितना आसान होगा, यह तो वक़्त ही बताएगा, लेकिन सरकार को यक़ीन हो चला है कि उल्फा सेनाध्यक्ष अपने संगठन के अधिकतर नेताओं से अलग–थलग पड़ गए हैं और उनकी स्थिति कमज़ोर हो चुकी है. मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, परेश बरुआ चीन और म्यांमार के बीच आवाजाही कर रहे हैं और कहीं भी निश्चित ठिकाना बना पाने में सफल नहीं हो पा रहे हैं. उन्हें पाकिस्तान या बांग्लादेश में भी ठिकाना नहीं मिल पा रहा है. राजनीतिक प्रेक्षकों का मानना है कि अगर उल्फा संप्रभुता की मांग छोड़ देता है तो उसकी अन्य मांगों पर बातचीत करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए. कश्मीर में मध्यस्थों के ज़रिए बातचीत चल रही है और अलगाववादियों की हर मांग पर वार्ता की नीति अपनाई जा रही है. नगा उग्रवादियों के संगठन एनएससीएन के साथ भी मध्यस्थों के ज़रिए कई वर्षों से बातचीत चल रही है. असम की जनता उल्फा समेत तमाम उग्रवादी संगठनों के साथ शांति वार्ता शुरू करने के पक्ष में है, ताकि राज्य में अमन–चैन क़ायम हो सके और रक्तपात का सिलसिला बंद हो.

feedback@chauthiduniya.com

चिकित्सा संबंधी सरकारी सहायता के सवाल पर एक युवक कुष्ठ रोगी कहता है कि सरकारी डॉक्टर हर शुक्रवार को जांच के लिए आश्रम आते हैं.

कुष्ठ रोगी

कोई हमारी भी सुनो

जीवनदीप कुष्ठ आश्रम में क़रीब 80 परिवार रहते हैं. इन परिवारों में बच्चे और बड़े समेत लगभग 210 सदस्य हैं. हमने आश्रम की एक महिला से बातचीत करनी चाही तो उसने कहा कि मेरा बच्चा सुबह से भूखा है.

कुमार सुशांत

राजेश्वर की उम्र 55 साल है. उसके तीन बेटे हैं और एक बेटी. राजेश्वर की आर्थिक हालत काफी दयनीय है. थोड़ी-बहुत सरकारी सहायता मिलती है, बाक़ी वह भीख मांगकर परिवार का गुज़ारा करता है, लेकिन लोग उसे भीख देने के लिए भी हाथ आगे नहीं बढ़ाते, क्योंकि उसे कुष्ठ है. राजेश्वर दिल्ली के आर के पुरम स्थित जीवनदीप कुष्ठ आश्रम में रहता है. यही हालत आश्रम में रहने वाले हर परिवार की है. ये लोग अनपढ़ हैं, लाचार हैं. राजेश्वर का कहना है कि हम लोग सरकार से केवल इतना चाहते हैं कि वह हमारे लिए सिर्फ़ दो वक़्त की रोटी का बंदोबस्त कर दे, सही ढंग से इलाज करा दे. राजेश्वर के आसपास क़रीब दस-बारह की संख्या में अन्य कुष्ठ रोगी भी बैठे थे. उनमें से हुसैन नामक एक कुष्ठ रोगी अचानक फूट-फूटकर रोने लगता है. वह कहता है कि हम इतने बदनसीब हैं कि कोई हमें भीख देने के लिए भी हाथ आगे नहीं बढ़ाता, अगर सरकार मुंह मोड़ लेगी तो हम कहां जाएंगे.

जीवनदीप कुष्ठ आश्रम में क़रीब 80 परिवार रहते हैं. इन परिवारों में बच्चे और बड़े समेत लगभग 210 सदस्य हैं. हमने आश्रम की एक महिला से बातचीत करनी चाही तो उसने कहा कि मेरा बच्चा सुबह से भूखा है. पहले कुछ खाने को लाओ, फिर बात करेंगे. हमने ऐसा किया. इसके बाद उसने बताया कि कुछ सरकारी सहायता तो ज़रूर मिलती है, लेकिन वह परिवार के भरण-पोषण के लिए नाकाफी है. महिला बताती है कि यहां के 80 परिवारों में से केवल 25 परिवारों को ही सरकार ने पंजीकृत किया है, जिन्हें हर महीने 1800 रुपये मिलते हैं. महिला के पति बताते हैं कि हम पिछले 10 सालों से शेष परिवारों को भी पेंशन देने की मांग कर रहे हैं, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई.

आश्रम के बीच में एक बड़ा सा साई मंदिर है, जहां बाहर से भी श्रद्धालु पूजा-अर्चना के लिए आते हैं. मंदिर के पास बैठे एक बुजुर्ग कुष्ठ रोगी अवध किशोर पाल से भी हमने बात की. वह बताते हैं कि कभीकभार बड़े बाबू लोग इस मंदिर में पूजा करने और हमें खाना बांटने आते हैं, उस दिन का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है और हम उस दिन जी भरकर खाते हैं.

आश्रम के बीच में एक बड़ा सा साई मंदिर है, जहां बाहर से भी श्रद्धालु पूजा-अर्चना के लिए आते हैं. मंदिर के पास बैठे एक बुजुर्ग कुष्ठ रोगी अवध किशोर पाल से भी हमने बात की. वह बताते हैं कि कभीकभार बड़े बाबू लोग इस मंदिर में पूजा करने और हमें खाना बांटने आते हैं, उस दिन का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है और हम उस दिन जी भरकर खाते हैं. अवध किशोर कहते हैं कि सरकार की ओर से हर परिवार को हर पंद्रह दिन में राशन मिलता है, लेकिन खाने वाले लोग ज़्यादा हैं, इसलिए मजबूरन सड़क पर भीख मांगनी पड़ती है. बच्चों के बारे में पूछने पर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं. वह कहते हैं कि उनके 20 वर्षीय बेटे को कोई नौकरी नहीं देता. बेटे को कुष्ठ भी नहीं है, लेकिन नौकरी लग जाने के बाद जब यह जानकारी मिलती है कि वह कुष्ठ आश्रम में रहता है तो कंपनी वाले उसे निकाल देते हैं.

चिकित्सा संबंधी सरकारी सहायता के सवाल पर एक युवक कुष्ठ रोगी कहता है कि सरकारी डॉक्टर हर शुक्रवार को जांच के लिए आश्रम आते हैं. वे मरहम-पट्टी करते हैं, दवाइयां भी देते हैं, लेकिन बड़े इलाज और महंगी दवाओं के लिए सरकारी डॉक्टर बड़े अस्पतालों का पता बता देते हैं. युवक बताता है कि उसके पिता को आंख में तकलीफ थी. डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया. वह विभिन्न सरकारी अस्पतालों में इधर से उधर भटकता रहा. आख़िर में कुछ समाजसेवियों की सहायता से उनका एक निजी अस्पताल में इलाज हुआ. युवक कहता है कि उसके इलाज न हो पाने की वजह से दो भाइयों की मौत हो गई.

जीवनदीप आश्रम में रहने वाले कुष्ठ रोगी एक मामले में ख़ुशनसीब हैं कि उनके पास छत है. भारत में जहां एक ओर कुष्ठ रोगियों की संख्या लगातार बढ़ रही है, वहीं सरकार की बेरुख़ी की वजह से हज़ारों कुष्ठ रोगियों को रहने के लिए जगह तक नसीब नहीं है. ऐसे में इनकी अव्यवस्थित बस्तियों की संख्या दिनोंदिन बढ़ रही है. भारत पिछले बीस सालों में कुष्ठ रोगियों की संख्या में लगाम लगाने में सफल रहा है. एक अनुमान के मुताबिक़, भारत में कुष्ठ रोगियों की संख्या में 95 फ़ीसदी की कमी आई है. यानी बीस साल पहले जहां भारत में यह संख्या 14 लाख थी, वहीं अब यह डेढ़ लाख के क़रीब है. इसके बावजूद दुनिया के नए कुष्ठ रोगियों में 54 फ़ीसदी कुष्ठ रोगी अभी भी भारत के हैं. भारत में कुष्ठ रोगियों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि यहां उन्हें एवं उनके परिवारीजनों को सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ता है. यही वजह है कि वे शहर में या शहर से बाहर अनियमित बस्तियां बनाकर रहने को मजबूर हैं. एक रिपोर्ट के अनुसार, देश में ऐसी अनियमित बस्तियों की संख्या क़रीब 700 है. दिल्ली, कर्नाटक और गुजरात जैसे कुछ राज्य कुष्ठ से निजात पा चुके हैं और वहां आंशिक तौर पर पीड़ित लोगों के लिए रोज़गार संबंधी नीतियां भी बनाई गई हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर कुष्ठ रोगियों के पुनर्वास के लिए अभी तक कोई नीति नहीं बन सकी. सवाल यह है कि अगर सरकार ही इन कुष्ठ रोगियों की अनदेखी करेगी तो आम लोग समाज के इस तबके की मदद करने के लिए आगे कैसे आएंगे.

आंकड़ों में कुष्ठ रोगी

वैश्विक स्तर पर भारत में कुष्ठ रोगियों की संख्या सबसे अधिक है. साल 2008 में जारी एक रिपोर्ट की मानें तो पूरे विश्व में ढाई लाख कुष्ठ रोगी थे, जिसमें केवल भारत से 1 लाख 37 हज़ार कुष्ठ रोगी शामिल थे. डब्ल्यूएचओ द्वारा हाल में लगाए गए एक अनुमान के मुताबिक़, भारत में कुष्ठ रोगियों की संख्या में क़रीब 35 फ़ीसदी की बढ़ोत्तरी हुई है. इनमें महिलाओं की संख्या क़रीब 48 हज़ार बताई गई है. वहीं तक़रीबन 14 हज़ार बच्चे भी इस रोग से ग्रस्त हैं. भारत में क़रीब सात सौ कुष्ठ आश्रम हैं. कुष्ठ रोग का इलाज भी है, लेकिन निजात पाने के बाद फिर से इसकी चपेट में आने की शिक़ायतें आम हैं. क़रीब 325 कुष्ठ रोगी ठीक होने के बाद फिर से इसकी चपेट में आ चुके हैं.

कुष्ठ रोग के कारण

कुष्ठ रोग वंशानुगत नहीं, बल्कि एक संक्रामक रोग है, जो दूसरे संक्रामक रोगों की तरह एक जीवाणु माइक्रोबैक्टेरियम लेप्री की वजह से फैलता है. यह खासकर त्वचा, पेरिफेरल नर्व्स, श्वांस और आंखों को प्रभावित करता है. प्रारंभिक स्तर पर इसका इलाज आसानी से हो जाता है, लेकिन देर हो जाने के बाद यह जीवाणु पीड़ित व्यक्ति के शरीर में कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करना शुरू कर देता है. सही समय पर इसका इलाज न हो तो पीड़ित मनुष्य असमर्थ भी हो सकता है. इस रोग का ख़तरा वयस्कों की अपेक्षा बच्चों में अधिक होता है. इसीलिए बच्चों को खासकर कुष्ठ रोगियों से परहेज़ करने के लिए कहा जाता है. यह बीमारी धीरे-धीरे बढ़ती है और पांच साल तक शरीर में फैलती रहती है. इसके लक्षण उभरने में 20 साल तक लग सकते हैं. ऐसे में सावधानी और सही समय पर इलाज ही एकमात्र उपाय है.

kumarsushant@chauthiduniya.com

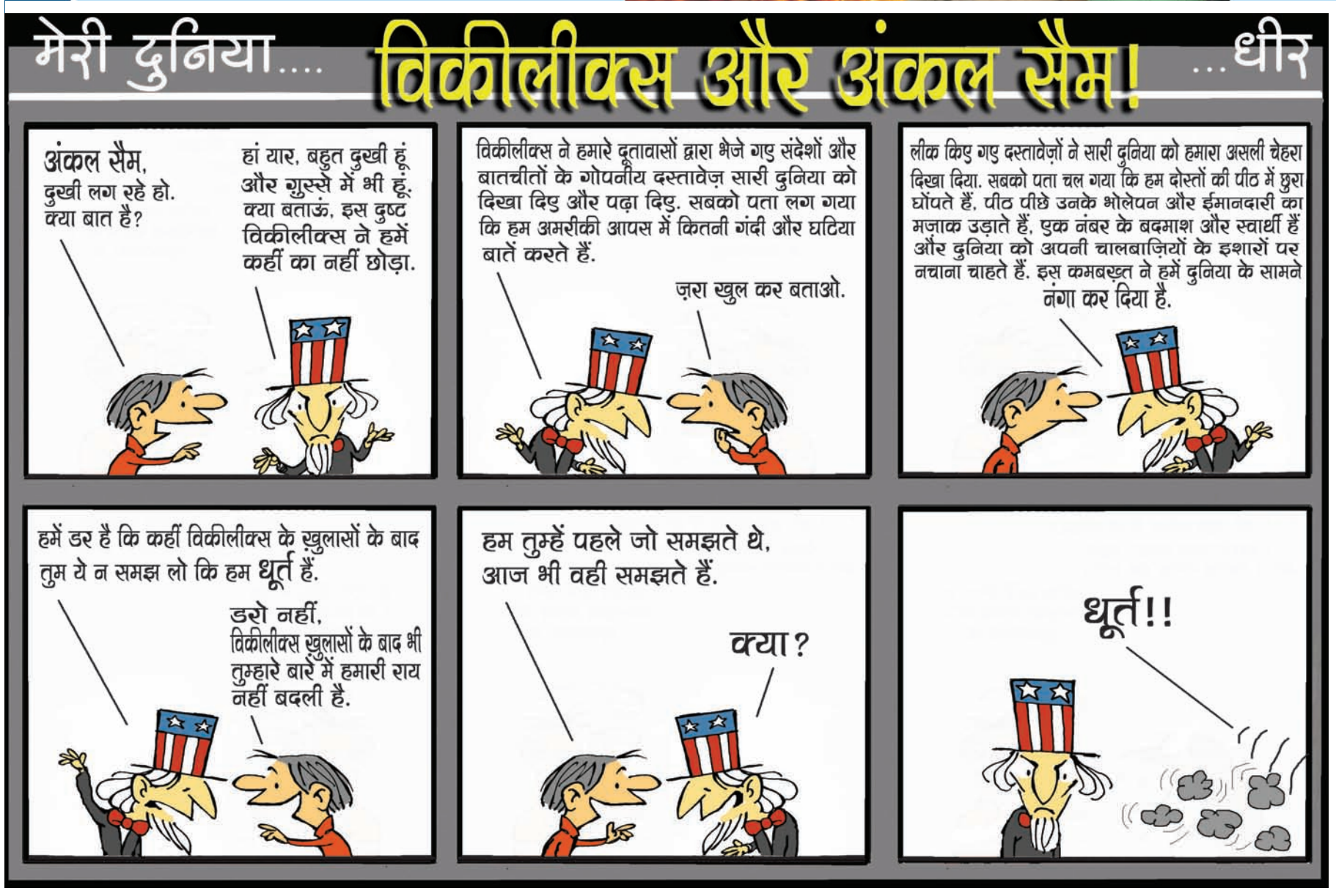

सरकार की तरफ से स्वतंत्रता सेनानियों के लिए कई तरह की योजनाएं हैं. हैरानी की बात यह है कि उन्हें खुद को स्वतंत्रता सेनानी साबित करने के लिए कई तरह सबूत पेश करने पड़ते हैं.

स्वतंत्रता सेनानी

आज़ादी के बाद हक़ की लड़ाई

आज हम ख़ुद को सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कहते हैं, लेकिन क्या कभी हमने सोचा कि जिन लोगों ने देश को आज़ादी दिलाई, उनके साथ हमारा बर्ताव कैसा है? स्वतंत्रता सेनानी आज सरकारी दफ़्तरों के बाहर ठोकरें खा रहे हैं. अस्पताल के बाहर घंटों लाइन में खड़े होकर इलाज कराने को मजबूर हैं. ज़िंदगी के आख़िरी पड़ाव में हमने उन्हें अकेला छोड़ दिया है. स्वतंत्रता संग्राम के दीवानों को काग़जात देकर साबित करना पड़ रहा है कि उन्होंने अंग्रेजों के ख़िलाफ़ लड़ाई की थी. विदेशियों से लड़ना उनके लिए आसान था, अपनों से लड़ना उन्हें भारी पड़ रहा है.

राजेश एस कुमार

ऋषिकेश की घटना है. एक दिन सड़क के किनारे एक महिला की लाश मिली. लाश आधी सड़ चुकी थी. लोग लाश को देखकर नाक बंद कर बगल से गुज़र जा रहे थे. किसी ने पुलिस को ख़बर दी. पुलिस आई और लाश को ले गई. इस लाश का क्या हुआ यह पता नहीं लेकिन ये लाश किसकी है, यह पता करने में पुलिस को एक महीने से ज़्यादा का वक़्त लग गया. पता चला कि ये लाश बीना भौमिक की है. आज शायद ही किसी को मालूम हो कि बीना भौमिक कौन है. यह नाम उस लड़की का है जिसे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अग्नि कन्या के नाम से जाना जाता था. इस लड़की ने ही 1932 में कोलकाता यूनिवर्सिटी में बीए केकोनवोकेशन केदौरान गवर्नर स्टेनली जैक्सन पर जानलेवा हमला किया था. स्टेनली तो बच गया लेकिन इस घटना से पूरे देश में तहलका मच गया था कि एक लड़की ने गवर्नर पर हमला कर दिया. पहली बार लोगों को लगा कि नौजवानों के साथ-साथ लड़कियां भी स्वतंत्रता संग्राम में अपने साहस का परिचय दे रही हैं. गवर्नर पर हमला करने केलिए बीना भौमिक को 9 साल की सज़ा हुई. जेल से निकलने के बाद वह क्रांतिकारी बन गई. जुगांतर रेव-ोल्यूशनरी क्लब की सदस्य बन गईं. 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बीना भौमिक को फिर तीन साल जेल में रहना पड़ा. उस दौरान वह कोलकाता कांग्रेस कमेटी की सचिव थी. बीना भौमिक स्वतंत्रता संग्राम का जीता-जागता इतिहास थी, देश की धरोहर थी. हमने किसी अंजान शहर में इन धरोहरों को मरने छोड़ दिया है.

यही हमारा दुर्भाग्य है. यही आज़ाद भारत है, जिसकेलिए बीना भौमिक जैसी हज़ारों नौजवानों और युवतियों ने अपना जीवन न्योछावर कर दिया था. उनका सपना तो न जाने कहां गुम हो गया लेकिन स्वतंत्रता के वे सेनानी, हमारे बुज़ुर्ग, जो हमारे आस-पास हैं, जिंदा हैं, सांस ले रहे हैं, उन्हें हमने ज़िंदगी के आख़िरी मोड़ पर अकेला छोड़ दिया है. स्वतंत्रता सेनानी बूढ़े हो गए हैं. हालात यह हैं कि समाज और सरकार की तरफ़ से उन्हें कोई सहूलियत नहीं मिल रही है. ज़्यादातर सेनानियों को घर वालों ने भी छोड़ दिया है. बेटा साथ नहीं रहता है. समाज और सरकार ने उनका तिरस्कार कर दिया है. वे पैसे-पैसे केलिए मोहताज हो गए हैं. सरकार की तरफ़ से उन्हें पेंशन मिलती है. शर्मनाक़ बात यह है कि पेंशन की राशि इतनी कम है कि बताने में भी शर्म आती है. आज़ादी की लड़ाई में शामिल होने वाले इन देशभक्तों को हम किसी फोर्थ क्लास कर्मचारी केवेतन से भी कम पैसे देते हैं.

आजादी के 63 सालों बाद भी हम देश के प्रति उनके त्याग और यो-गदान का महत्व समझ नहीं पा रहे हैं. हम उन्हें सम्मान देने और उनका हक़ दिलाने के बजाए उन्हें अपमानित कर रहे हैं. मई, 2010 में केंद्र सरकार द्वारा अदालत को बताया गया कि देश भर में क़रीब एक लाख सत्तर हज़ार स्वतंत्रता सेनानी हैं. हालांकि यह आंकड़ा सरकारी दस्तावेजों पर आधारित है. हर महीने यह संख्या बदलती रहती है, क्योंकि इन सेनानियों की उम्र इतनी हो चुकी है कि लगभग हर महीने कुछ की मौत हो जाती है. इनमें से क़रीब साठ हज़ार स्वतंत्रता सेनानियों को केंद्र सरकार द्वारा पेंशन मिल रही है, बाक़ी को राज्यों द्वारा पेंशन की व्यवस्था है. पेंशन वितरण के मामले में हर राज्य का अपना नियम है, पेंशन राशि भी अलग अलग है. केंद्र सरकार स्वतंत्रता सेनानियों को 12400 रुपये देती है. वह स्वतंत्रता सेनानी योजना के तहत कुल सात सौ पचासी करोड़ रुपये ख़र्च करती है. उधर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने पिछले 15 अगस्त को स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन राशि छह हज़ार से बढ़ाकर ग्यारह हज़ार रुपये कर दी. इसी तरह कर्नाटक सरकार ने यह पेंशन तीन हज़ार से बढ़ाकर चार हज़ार रुपये कर दी है. दिल्ली में स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन साढ़े तीन हज़ार से बढ़ाकर साढ़े चार हज़ार रुपये कर दी गई है. हैरानी की बात यह है कि दिल्ली में 1998 से ही स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन देने की योजना शुरू की गई थी, लेकिन आज भी यहां पेंशन राशि अन्य राज्यों के मुक़ाबले काफ़ी कम है. तमिलनाडु में पिछले साल मुख्यमंत्री ने सेनानियों को मिलने वाली पेंशन चार हज़ार से बढ़ाकर पांच हज़ार रुपये कर दी. सरकार स्वतंत्रता सेनानियों की मदद के बड़े-बड़े दावे करती है. उन्हें आर्थिक सहायता के तौर पर पेंशन और विभिन्न क्षेत्रों में आरक्षण देने की बात करती है, लेकिन सच तो यह है कि न जाने कितने स्वतंत्रता सेनानी आज भी गुमनामी और ग़रीबी की ज़िंदगी जी रहे हैं. कई तो अपने हक़ की लड़ाई लड़ते-लड़ते इस दुनिया से ही विदा हो गए. सबसे ज़्यादा शर्मनाक़ बात तो यह है कि कई स्वतंत्रता सेनानियों ने ख़ुद को स्वतंत्रता सेनानी साबित करने में अपनी शेष ज़िंदगी गुज़ार दी. अधिकारियों की मनमानी और व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार की वजह से कई फ़र्ज़ी लोग ख़ुद को स्वतंत्रता सेनानी घोषित कर सरकारी सुविधाओं का फ़ायदा उठा रहे हैं और असली स्वतंत्रता सेनानी दस्तावेजों में अपना नाम दर्ज कराने के लिए तरस रहे हैं. ताज्जुब की बात तो यह है कि फ़र्ज़ी लोगों में कई तो ऐसे हैं, जो आज़ादी के समय पैदा ही नहीं हुए थे या फिर उनकी उम्र चार-पांच साल के आसपास रही होगी. ऐसे मामलों में जो लोग पकड़े जाते हैं, उनकी पेंशन रोक दी जाती है. लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि जो अधिकारी बिना जांच-पड़ताल किए फ़र्ज़ी प्रमाणपत्र पर दस्तखत करके असली स्वतंत्रता सेनानियों का हक़ मारते हैं, उन्हें कोई सज़ा क्यों नहीं मिलती? सुप्रीम कोर्ट स्वतंत्रता सेनानियों की बदहाली पर अफ़सोस जताता है और इसके लिए सरकार की लालफीताशाही को ज़िम्मेदार बताता है, लेकिन क्या इतना काफ़ी है? ग़ौर करने वाली बात है कि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि देश के ज़्यादातर स्वतंत्रता सेनानी ग़रीबी और भुखमरी की ज़िंदगी बिताने पर मजबूर हैं, सरकार की तरफ से दी जाने वाली पेंशन उनके लिए किसी ख़ैरात से कम नहीं है. इस बात से साबित हो जाता है कि देश का सर्वोच्च न्यायालय भी जानता है कि सरकार स्वतंत्रता सेनानियों की अनदेखी कर रही है.

बात सिर्फ़ पेंशन और आरक्षण की नहीं है, बात है उनके त्याग और संघर्ष के महत्व को समझने की. स्वतंत्रता संग्राम के जो सिपाही आज ज़िंदा हैं, उन्हें क्या वही भारत नज़र आता है, जिसके लिए वे लड़े थे?

भारत का स्वतंत्रता संग्राम इतिहास का ऐसा पन्ना है, जो कई मायनों में बेमिसाल है. आज़ादी के सिपाहियों की बहादुरी और त्याग की वजह से ही आज हम आज़ाद भारत में सांस ले पा रहे हैं. 1857 से शुरू हुआ स्वतंत्रता संग्राम 1947 तक चला. इसमें कई पीढ़ियों का संघर्ष और बलिदान शामिल है. देश को आज़ाद कराने के लिए इस लड़ाई में जिन लोगों ने हिस्सा लिया, वे आज ख़ुद को कोस रहे हैं. आएदिन भ्रष्टाचार, किसानों द्वारा आत्महत्या, नक्सलियों का बढ़ता प्रभाव, ग़रीब और अमीर में बढ़ता फ़ासला, सांप्रदायिक दंगे, हिंसा और नेताओं के नित नए फ़रेब देखकर उनका कलेजा बैठ जाता है. उन्होंने जिस आज़ादी के लिए अंग्रेजों से लड़ाई की, वह तो कहीं नज़र नहीं आती. जिस देश को आज़ाद कराने के लिए इन सिपाहियों ने लाठियां और गोलियां खाईं, वह देश आज गांधी, नेहरू और सुभाष चंद्र बोस को सिर्फ़ उनके जन्मदिन पर याद करता है. नई पीढ़ी तो आज़ादी के दीवानों के बलिदान के साथ-साथ आज़ादी के मायने भी भूल चुकी है. जिन लोगों की वजह से आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, उन्हें हमने सम्मानित करना तो दूर, बदहाली के दलदल में छोड़ दिया है. उनके अनुभव से सीखना तो दूर, समारोहों में उन्हें बोलने का भी मौक़ा नहीं दिया जाता. हम शायद भूल रहे हैं कि ये साधारण लोग नहीं हैं, जीते-जागते इतिहास हैं. लेकिन हम इतने निष्ठुर और संवेदनहीन हो गए हैं कि इनकी अहमियत को समझने की अक्ल हमारे अंदर नहीं बची. वरना हम इन्हें दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर न होने देते. जिन लोगों ने देश को आज़ाद कराने में अपनी जवानी लुटा दी, आज हालत यह है कि उन्हें सचिवालयों में प्रवेश के लिए घंटों लाइन में खड़े होकर पास बनवाना पड़ता है. सबसे बड़ी समस्या इलाज कराने की है. अब इनकी वो उम्र नहीं है कि अस्पतालों में लाइन लग कर अपना इलाज करवा सकें. जो स्वतंत्रता सेनानी गांव में रहते हैं उनकी हालत और भी ख़राब है. सरकार कम से कम इतना तो कर सकती थी कि डाक्टरों को उनके घर भेज कर उनका हालचाल पूछ सकती थी.

सरकार की तरफ़ से स्वतंत्रता सेनानियों के लिए कई तरह की योजनाएं हैं. लेकिन ये योजना सबके लिए नहीं है. हर राज्यों के अलग नियम हैं. हैरानी की बात यह है कि उन्हें ख़ुद को स्वतंत्रता सेनानी साबित करने के लिए कई तरह सबूत पेश करने पड़ते हैं. सरकार सिर्फ़ उन्हें ही स्वतंत्रता सेनानी मानती है, जो आज़ादी की लड़ाई के दौरान जेल गए, छह महीने से ज़्यादा भूमिगत रहे या उन्हें छह महीने अथवा उससे ज़्यादा समय के लिए ज़िला बदर किया गया हो. स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन लेने के लिए यह भी साबित करना पड़ता है कि स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने की वजह से अंग्रेजी हुकूमत ने उनकी संपत्ति की कुर्की कर ली या फिर उनकी नौकरी चली गई या फिर उन्हें सज़ा मिली. जो स्वतंत्रता सेनानी इससे संबंधित पर्याप्त काग़जात उपलब्ध नहीं करा पाते, उन्हें सरकार स्वतंत्रता सेनानी नहीं मानती. अगर चंद्रशेखर आज़ाद जीवित होते तो सरकार उन्हें स्वतंत्रता सेनानी नहीं मानती, क्योंकि वह अंग्रेजों से लड़े तो थे, लेकिन कभी जेल नहीं गए, कभी नौकरी से निकाले नहीं गए.

आंध्र प्रदेश के उदूपी के एक स्वतंत्रता सेनानी बाबू मास्टर के बारे में आपको बताता हूं. चौरानवे साल के बाबू मास्टर ने आज़ादी की लडाई में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया. स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वे कांग्रेस केजाने माने कार्यकर्ता रहे. गांधी की विचारधारा पर चलते हुए पूरा जीवन बिता दिया. स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वो पूरे ज़िले में घूम-घूम कर चरखा बांटते थे. नमक सत्याग्रह आंदोलन में हिस्सा लेने वे मैंगलोर गए. आज भी वो गांधी केबताए रास्ते पर चल रहे हैं. शायद यही उनकी बदकिस्मती रही. आज़ादी के बाद कुछ समय केलिए उन्हें पेंशन ज़रूर मिली लेकिन अचानक अधिकारियों ने कहा कि उनकी पेंशन बंद हो गई है. वजह बाबू मास्टर स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने केबावजूद कभी जेल नहीं गए. उनकी पेंशन रुक गई. बाबू मास्टर दाने-दाने केलिए तरस रहे हैं. उन्हें देखने वाला कोई नहीं है.

जेल जाने वाले स्वतंत्रता सेनानी और जेल नहीं जाने वाले स्वतंत्रता सेनानी में सरकार इतना भेद क्यों करती है. अधिकारियों को यह समझ मेंक्यों नहीं आता है कि जो लोग जेल नहीं गए उन्होंने ज़्यादा कष्ट उठाए हैं. जो लोग स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जेल गए वे तो जेल के अंदर बी केटेगरी के बंदी बनकर रहते थे. लेकिन जो लोग जेल नहीं गए उन्हें घर परिवार छोड़ कर अंडरग्राउंड होकर आंदोलन का काम करना पड़ता था. स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कांग्रेस सारे लोगों को जेल जाने से मना करती थी, क्योंकि अगर सारे लोग जेल चले जाएंगे तो जनता के बीच आज़ादी के आंदोलन को कौन चलाएगा. ऐसे ही लोगों के कंधों पर आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम होता था. ये छुप कर काम करते थे. उनके पास न रहने का ठिकाना था न ही खाने-पीने की व्यवस्था. उनके पीछे पुलिस लगी रहती थी. वे महीनों घर से बाहर दर दर की ठोकरें खाते थे.

ख़बरें आती हैं कि स्वतंत्रता सेनानी बदहाली से तंग आकर आत्महत्या कर रहे हैं और कुछ आशावान लोग कभी न ख़त्म होने वाले धरने पर बैठे हैं. इससे ज़्यादा बदतर हालात और क्या हो सकते हैं कि आज स्वतंत्रता सेनानी सार्वजनिक स्थानों पर ख़ुद को स्वतंत्रता सेनानी बताने से भी सकुचाते हैं. अगर हमें उनकी हालत पर थोड़ी भी शर्म आती है और उनके लिए वास्तव में कुछ करने की इच्छा है तो हमें उनकी ओर एक बार फिर से ध्यान देना होगा. जिनके पास कृषि योग्य भूमि नहीं है, उन्हें सरकार विशेष दरों पर ज़मीन मुहैय्या कराए. व्यवसायिक तौर पर मज़बूत बनाने के लिए उन्हें गैस एजेंसियां और पेट्रोल पंप आदि आवंटित हों. लेकिन आज यह सब होता नहीं दिख रहा. अगर हालात ऐसे ही रहे तो अगले दस सालों में देशभक्तों की ये पीढ़ी ख़त्म हो जाएगी.

ये तो स्वंय इतिहास हैं. अगर हम इन्हें वो इज़्ज़त देते, जिसके वो हक़दार हैं. अगर इन्हें हर स्कूलों में बुलाया जाता, बच्चों से मिलवाया जाता तो देश के बच्चे-बच्चे की रगों में देशभक्ति का लहू बहता. वे स्वतंत्रता संग्राम से वाक़िफ़ होते. आज़ादी की लड़ाई में दिए गए बलिदान को जानता और आज़ादी के मायने को समझ पाता. अफ़सोस की बात यह है कि हमने हाशिए पर डाल दिया है, उन्हें हम समाज के एक वेस्टीजियल ऑर्गन की तरह ट्रीट करते हैं.

rajesh@chauthiduniya.com

स्वतंत्रता सेनानियों की संख्या

आंध्र प्रदेश	14,573	मध्य प्रदेश	3,468	त्रिपुरा	887
असम	4,438	महाराष्ट्र	17,732	उत्तर प्रदेश	17,990
बिहार एवं झारखंड	24,870	मणिपुर	62	पश्चिम बंगाल	22,484
गोवा	1,436	मेघालय	86	अंडमान निकोबार	03
गुजरात	3,596	मिजोरम	04	चंडीगढ़	89
हरियाणा	1,685	नागालैंड	03	दादर नगर हवेली	83
हिमाचल प्रदेश	624	उड़ीसा	4,189	दमन और दीव	33
जम्मू कश्मीर	1,806	पंजाब	7,008	दिल्ली	2,044
कर्नाटक	10,084	राजस्थान	811	पांडिचेरी	317
केरल	3,228	तमिलनाडु	4,099		

मिलने वाली सुविधाएं

हरियाणा सरकार 1980 से सरकारी सेवाओं में प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर स्वतंत्रता सेनानियों के पुत्रों-पुत्रियों, पौत्रों- पौत्रियों को 2 प्रतिशत आरक्षण प्रदान कर रही है. 1985 से सीधी भर्तियों में भी आरक्षण की सुविधा दी जा रही है. तमिलनाडु, हिमाचल और कुछ अन्य राज्य सरकारें भी इनके आश्रितों को शिक्षण संस्थानों में आरक्षण देती हैं. आंध्र प्रदेश सरकार के नई दिल्ली स्थित आंध्रा भवन में स्वतंत्रता सेनानियों को रुकने की सुविधा है, हिमाचल सरकार भी नई दिल्ली स्थित हिमाचल भवन में यह सुविधा प्रदान करती है, लेकिन राजस्थान सरकार ने ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं की. कर्नाटक सरकार मैसूर लैंड रेवेन्यू रूल 1960 के अंतर्गत सरकारी भूमि के आवंटन में स्वतंत्रता सेनानियों को प्रथम वरीयता प्रदान करती है. यही नहीं, मध्य प्रदेश सरकार भी भूमि आवंटन में उन्हें प्रथम वरीयता प्रदान करती है.

अधिकांश माता-पिता गर्भस्थ शिशु के स्वास्थ्य की चिंता छोड़कर भ्रूण परीक्षण केंद्रों में यह पता लगाते हैं कि वह लड़का है अथवा लड़की.

मेघनाद देसाई

विकीलीक्स के ख़ुलासे भारत के लिए सबक़

बिस्मार्क ने कहा था कि कोई भी सच तब तक सच नहीं है, जब तक आधिकारिक तौर पर उसका खंडन न कर दिया जाए. आज यही बात हम थोड़े अलग अंदाज़ में कह सकते हैं. मसलन, कोई भी सच तब तक सच नहीं है, जब तक वह लीक न हो जाए और खासकर इंटरनेट पर. अभी हमारे पास विकीलीक्स है, राडिया के टेप हैं, कुछ और सच भी हो सकते हैं, जो ऑनलाइन लीक किए जाएंगे या मीडिया के हाथों में दे दिए जाएं. आधिकारिक तौर पर शासन हमेशा ऐसे खुलासों की भर्त्सना ही करता है, लेकिन ऑनलाइन खुलासे को नकार पाना बहुत कठिन काम है. ऐसे खुलासे को संदर्भहीन बता पाना भी मुश्किल है. यही कारण है कि ये खुलासे लगातार हो पा रहे हैं. कुछ खुलासे, जैसे कि अमेरिका ईरान को परमाणु ताक़त बनने से रोकना चाहता है और उसके इस काम में सउदी अरब, इजरायल और जॉर्डन सहायता करने को लालायित हैं, शायद ही चौंकाएं, लेकिन उत्तरी कोरिया की रक्षा करते-करते अब चीन उब गया है, यह आश्चर्य पैदा करने वाला खुलासा है.

वैसे उन सभी लोगों को, जो यह सोचते हैं कि चीन की अधिनायकवादी व्यवस्था भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था के मुक़ाबले चीन में ज़्यादा विकास कर सकी है, यह साफ करना चाहिए कि दक्षिण कोरिया के मुक़ाबले उत्तरी कोरिया क्यों इतना ग़रीब है. कैसे उत्तरी कोरिया एक लड़ाकू देश बनता जा रहा है. मुझे लगता है कि इनके राजनयिकों को पहले से इस खुलासे का अंदेशा था. उत्तरी कोरिया जल्दी से ऐसे हालात पैदा करना चाहता था, जो चीन को उसकी मदद करने के लिए बाध्य करें. अगर कोरियाई युद्ध पूर्वी एशिया में फैलता है तो चीन एक छोर और अमेरिका दूसरे छोर पर होगा. और भारत को सावधानीपूर्वक अपनी सीमा देखनी होगी. विकीलीक्स से एक और मजेदार कहानी का खुलासा हुआ है. वह यह कि अमेरिका लगातार पाकिस्तान से त्रस्त होता जा रहा है. उसे पाकिस्तान से सीमित फ़ायदा ही है. चाहे वह आतंक के ख़िलाफ़ उसकी ज़मीन का इस्तेमाल हो या नाभिकीय ईंधन की सुरक्षित आपूर्ति. हम देखते हैं कि अमेरिका पाकिस्तानी कट्टरता और उसे दी जाने वाली विशाल आर्थिक सहायता जिसका इस्तेमाल वह हथियार ख़रीदने में करता है, के आगे असहाय है. अमेरिका ने ख़ुद को एक गड़बड़ झाले में फंसा लिया है. पहले पाकिस्तान की ज़मीन का इस्तेमाल तालिबानियों को सहायता देने में, ताकि अफ़ग़ानिस्तान से सोवियत सेना को भगाया जा सके और एक बार फिर उन्हीं तालिबानियों को अफ़ग़ानिस्तान से निकालने में. ये दोनों काम ही अमेरिका के लिए फांस बन गए. ओसामा बिन लादेन तो उतना ही शुद्ध है, जितना अमेरिकी उत्पाद सुपर मैक.

भारत के लिए यह व्यर्थ है कि वह पाकिस्तान को आरोपित करने के लिए अमेरिका पर निर्भर रहे. अमेरिका जब अफ़ग़ानिस्तान में फंसा तो उसे ब्लैकमेल करने के लिए पाकिस्तान को एक सुनहरा अवसर हाथ लग गया. जोसेफ बिडेन की वह बात जो उन्होंने गॉर्डन ब्राउन को बताई, यह साबित करती है कि अमेरिकी कितने सहमे हुए हैं. ज़रदारी ने बिडेन को कहा था कि उन्हें चिंता है कि पाक सेना प्रमुख जनरल कियानी उनकी हत्या करा सकते हैं. वह जानते हैं कि वह एक शेर की सवारी कर रहे हैं और इस सवारी से उतरने में उन्हें डर लग रहा है. ओबामा शायद भारत की पीठ थपथपा सकते हैं, लेकिन जब आपने इस्लामाबाद में अमेरिकी राजदूत द्वारा भेजे गए ई-मेल को देख लिया है, तब ऐसे में अमेरिकी समर्थन का क्या महत्व है. किसी भी हालत में भारत अमेरिका से यह उम्मीद नहीं कर सकता कि वह उसके हित में कुछ करे. इसके लिए भारत को ख़ुद पर ही निर्भर होना पड़ेगा. अगली बार हो सकता है कि अमेरिका कुछ नीतियां थोपने की कोशिश करे. मसलन, परमाण्विक नागरिक जवाबदेयता बिल. भारत को तब इसे सिरे से खारिज कर देना चाहिए.

राडिया के टेप भी कुछ यही कहानी कहते हैं. इस बात में कोई आश्चर्य नहीं है कि औद्योगिक घराने अपने स्वार्थ के लिए जन संपर्क एजेंसियों की सेवाएं लेते हैं, जो उनकी ओर से लोगों से संपर्क करें. असल आश्चर्य की बात तो यह है कि भारतीय राजनीति में पनप रहे भ्रष्टाचार के बारे में हमारी जो आशंकाएं थीं, वे सही साबित हो रही हैं. दिक्कत सिर्फ़ इस बात की है कि जिस मीडिया के बारे में हम यह मानते थे कि वह राजनीतिक भ्रष्टाचार को उजागर करने के मामले में निष्पक्ष रहता है, वह मीडिया भी दूषित हो गया. राजनीतिज्ञों ने उन सबको भ्रष्ट बना दिया, जो उनके संपर्क में आए. दुनिया भर के लोगों ने इस भ्रष्टाचार पर ध्यान दिया है. अब यह सवाल उठने लगा है कि क्या भारत व्यापार के लिए सही जगह रह गया है. भारत भ्रष्टाचार के मसले पर अपनी नग्नता छुपा पाने में असफल रहा है. आज हम 2-जी, सीवीसी और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों द्वारा रियल एस्टेट कंपनियों को ग़ैर क़ानूनी तरीक़े से लोन देने जैसे घोटालों से दो-चार हो रहे हैं. कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की स्थिति के बारे में क्या कहा जाए. कांग्रेस के पास अपना बचाव करने का अजीब नुस्खा है. वह कहती है कि भाजपा भी भ्रष्ट है. क्या इस तरह अपने बचाव के तरीक़े को गंभीर कहा जा सकता है? क्या भारतीयों को इस बात से ख़ुश होना चाहिए कि दोनों राष्ट्रीय पार्टियां भ्रष्ट हैं और खुलेआम ऐसा बोल रही हैं? क्या मतदाताओं के पास सिर्फ़ यही एक लोकतांत्रिक विकल्प बचा है कि वे कम या ज़्यादा भ्रष्ट पार्टियों में से किसी एक को चुनें?

feedback@chauthiduniya.com

भारत के लिए यह व्यर्थ है कि वह पाकिस्तान को आरोपित करने के लिए अमेरिका पर निर्भर रहे. अमेरिका जब अफ़ग़ानिस्तान में फंसा तो उसे ब्लैकमेल करने के लिए पाकिस्तान को एक सुनहरा अवसर हाथ लग गया. जोसेफ बिडेन की वह बात जो उन्होंने गॉर्डन ब्राउन को बताई, यह साबित करती है कि अमेरिकी कितने सहमे हुए हैं.

कन्या भ्रूण हत्या एक बड़ी समस्या

आज समाज में अपराध बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं. इनमें एक जघन्य अपराध भ्रूण हत्या भी है. इस अपराध के पीछे इच्छित संतान है. इसे अंजाम देने के लिए वैज्ञानिक आविष्कार सहयोगी बने हैं. परिणामस्वरूप गर्भस्थ शिशु का लिंग परीक्षण कराना और अनचाही संतान से छुटकारा पाना सहज हो गया है. जनसंख्या नियंत्रण को प्राथमिकता देने वाली सरकार ने जबसे भ्रूण हत्या को क़ानूनी वैधता प्रदान की है, तबसे विश्व में भ्रूण हत्याओं का क्रूर व्यापार निर्बाध गति से बढ़ रहा है. भगवान महावीर, बुद्ध एवं गांधी जैसे प्रेरकों के इस अहिंसा प्रधान देश में हिंसा का नया रूप भारतीय संस्कृति का उपहास है. भारत में क़रीब ढाई दशक पूर्व भ्रूण परीक्षण पद्धति की शुरुआत हुई, जिसे एमिनो सिंथेसिस नाम दिया गया. एमिनो सिंथेसिस का उद्देश्य है, गर्भस्थ शिशु के क्रोमोसोम्स के संबंध में जानकारी हासिल करना. यदि उनमें किसी भी तरह की विकृति हो, जिससे शिशु की मानसिक-शारीरिक स्थिति बिगड़ सकती हो तो उसका उपचार करना. लेकिन पिछले क़रीब दस-पंद्रह वर्षों से एमिनो सिंथेसिस राह भटक गया है. आज अधिकांश माता-पिता गर्भस्थ शिशु के स्वास्थ्य की चिंता छोड़कर भ्रूण परीक्षण केंद्रों में यह पता लगाते हैं कि वह लड़का है अथवा लड़की.

यह कटु सत्य है कि लड़का होने पर उस भ्रूण के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होती, किंतु लड़की की इच्छा न होने पर उस भ्रूण से छुटकारा पाने की प्रक्रिया अपनाई जाती है. अब सवाल यह उठता है कि देवी स्वरूप, निस्वार्थ भाव से सुख-सुविधाओं का बलिदान करने वाली मां उस अजन्मे शिशु को मारने की स्वीकृति कैसे दे देती है? क्या उस बच्ची को जीने का अधिकार नहीं है? उस बेचारी ने कौन सा अपराध किया है? यह कृत्य मानवीय दृष्टि से भी उचित नहीं है. प्रत्येक प्राणी जीना चाहता है. किसी को जीने के अधिकार से वंचित करना पाप है. वैदिक धर्म में भ्रूण हत्या को ब्रह्म हत्या से भी बड़ा पाप बताया गया है. कहा गया है कि ब्रह्म हत्या से जो पाप लगता है, उससे दोगुना पाप गर्भपात से लगता है. इसका कोई प्रायश्चित नहीं है. जैन दर्शन में भी इसे नरक की गति पाने का कारण माना गया है. आश्चर्य है कि धार्मिक कहलाने वाला और चींटी की हत्या से भी कांपने वाला समाज आंख मूंद कर कैसे भ्रूण हत्या कराता है! यह मानव जाति को कलंकित करने वाला अपराध है.

अमेरिका में 1994 में एक सम्मेलन हुआ, जिसमें डॉ. निथनसन ने एक अल्ट्रासाउंड फिल्म (साइलेंट स्क्रीन) दिखाई. उसमें बताया गया कि 10-12 सप्ताह की कन्या की धड़कन जब 120 की गति में चलती है, तब बड़ी चुस्त होती है, लेकिन जैसे ही पहला औज़ार गर्भाशय की दीवार को छूता है तो बच्ची डर से कांपने लगती है और अपने आप में सिकुड़ने लगती है. औज़ार के स्पर्श करने से पहले ही उसे पता लग जाता है कि हमला होने वाला है. वह अपने बचाव के लिए प्रयत्न करती है. औज़ार का पहला हमला कमर और पैर पर होता है. गाजर-मूली की भांति उसे काट दिया जाता है.

कन्या तड़पने लगती है. फिर जब उसकी खोपड़ी को तोड़ा जाता है तो एक मूक चीख के साथ उसका प्राणांत हो जाता है. यह दृश्य हृदय को दहला देता है. इस निर्मम कृत्य से ऐसा लगता है, मानों कलियुग की क्रूर हवा से मां के दिल में करुणा का दरिया सूख गया है. तभी तो दिन-प्रतिदिन कन्या भ्रूण हत्याओं की संख्या बढ़ रही है. यह भ्रूण हत्या का सिलसिला इसी रूप में चलता रहा तो भारतीय जनगणना में कन्याओं की घटती संख्या से भारी असंतुलन पैदा हो जाएगा. यदि बदलाव नहीं आया तो आने वाले कुछ वर्षों में ऐसी स्थिति आ जाएगी कि विवाह योग्य लड़कों के लिए लड़कियां नहीं मिलेंगी.

आंकड़े बताते हैं कि 2001 की जनगणना के अनुसार, 1000 लड़कों पर पंजाब में 793, गुजरात में 878, दिल्ली में 865, हरियाणा में 820, हिमाचल में 897, राजस्थान में 909, महाराष्ट्र में 913, बंगाल में 963 लड़कियां हैं. ईसाइयों में लिंगानुपात की स्थिति काफी अच्छी है. इस समुदाय में 2001 की जनगणना के अनुसार, 1.19 करोड़ लड़कों की तुलना में 1.29 लड़कियां हैं. मौजूदा हालात को देखते हुए आवश्यकता इस बात की है कि सामाजिक सोच बदली जाए, मानदंड बदले जाएं, लड़कों और लड़कियों के बीच भेदभाव समाप्त किया जाए. आज की परिस्थिति में लड़का हो या लड़की, उसके अंदर शिक्षा एवं संस्कार भरने की ज़रूरत है. लड़कियों के जन्म से घबराने की अपेक्षा उनके जीवन के निर्माण की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए. यही समाज के लिए श्रेयस्कर होगा. संस्कारी और सुयोग्य कन्याओं से परिवार भी सुरभित बनेगा, जो समाज एवं राष्ट्र के लिए उपयोगी सिद्ध होगा. हालांकि कुछ राज्यों में सरकार द्वारा कन्या भ्रूण हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया है. इस प्रतिबंध का कोई असर तब तक नहीं होगा, जब तक मनुष्य की मनोवृत्ति नहीं बदलेगी और भोगवृत्ति सीमित नहीं होगी.

इसी क्रम में यह सुखद संदेश देना भी ज़रूरी है कि आज कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए, देश का एक ज़िला ऐसा भी है, जहां के युवा वर्ग ने एक खास अभियान चला रखा है. सोनभद्र ज़िले के राबर्ट्सगंज ब्लॉक के तीन गांवों मझुवी, भवानीपुर एवं गइर्डगढ़ के 60 युवाओं ने एक मंडली तैयार की है, जो अपने गांव में होने वाली किसी भी धर्म-जाति की कन्या की शादी में टेंट से लेकर बर्तन तक का काम ख़ुद संभालती है. इस मंडली ने बड़े-बड़े दानियों से दान लेकर नहीं, बल्कि ख़ुद अपने संसाधनों से शादी- विवाह में काम आने वाले तमाम छोटे-बड़े साजोसामान जुटाए हैं. मंडली से जुड़े युवा लड़की के घर वालों को आर्थिक मदद देने के साथ-साथ मिनटों में हर सामान की व्यवस्था कर देते हैं. 2002 में बने इस संगठन से लाभांवित होने के बाद लोगों की भावनाएं बदली हैं. यूं तो बेटी का विवाह एक सामाजिक परंपरा है, लेकिन अगर ऐसे ही बेटी वालों की मदद की जाने लगे तो कन्या भ्रूण हत्या जैसी विकृत सोच रखने वाले लोगों के भी विचार बदलेंगे. बहरहाल, यह समझ में नहीं आता कि आज हम इंसान बनना क्यों भूलते जा रहे हैं. जो लोग भ्रूण हत्या के बारे में सोचते हैं, उन्हें यह भी सोचना चाहिए कि बेटियों से घर-आंगन में रौनक है. ममता, प्रेम, त्याग, रक्षाबंधन और न जाने कितनी परंपराएं उन्हीं बेटियों के चलते जीवित हैं. इस स्थिति को देखकर कह सकते हैं कि कन्या भ्रूण हत्या पाप ही नहीं, देश और समाज के लिए अभिशाप भी है. इसे कड़ाई के साथ रोकने की ज़रूरत है.

आशा त्रिपाठी
feedback@chauthiduniya.com

देश का एक ज़िला ऐसा भी है, जहां केयुवा वर्ग ने एक खास अभियान चला रखा है. सोनभद्र ज़िले के राबर्ट्सगंज ब्लॉक के तीन गांवों मझुवी, भवानीपुर एवं गइर्डगढ़ के60 युवाओं ने एक मंडली तैयार की है, जो अपने गांव में होने वाली किसी भी धर्म-जाति की कन्या की शादी में टेंट से लेकर बर्तन तक का काम ख़ुद संभालती है.

मिथिला का महत्व

आपने मिथिला के लोकप्रिय पर्व शमा चकेबा के बारे में लिखा, बहुत अच्छा लगा. ख़ुशी का एहसास हुआ कि चलो सारे संसार को भी तो मालूम हो कि मिथिला का महत्व क्या है. हम चाहते हैं कि आप इसी तरह मिथिला के लोकपर्व चौथी दुनिया में प्रकाशित करते रहें और दुनिया को मिथिला के बारे में अवगत कराएं.

-जयंती चरण झा, *ई-मेल से.*

इतिहास गवाह है

आवरण कथा-प्रधानमंत्री जी इस्तीफा मत दीजिए पढ़ा. इतिहास को देखा जाए तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का पद कभी इतना शर्मिंदा नहीं हुआ, जितना प्रतिभा पाटिल और मनमोहन सिंह के इन पदों पर बैठने से हुआ.

-जय कुमार, *ई-मेल से.*

कॉमरेड का सच

अनंत विजय ने अपने लेख में तानाशाही साम्यवादी विचारधारा को जिस प्रकार उजागर किया, मैं उससे काफी हद तक सहमत हूं. इसमें कभी भी दोराय की गुंजाइश नहीं कि साम्यवादी विचारधारा सिर्फ़ मतलबपरस्तों की दुनिया है. यह बात का तो इतिहास साक्षी है. रूस से लेकर चीन और फिर भारत पर अगर नज़र डालें तो इस विचारधारा के मानने वालों ने सिवाय जुल्म के और कुछ नहीं किया. अगर यह विचारधारा ग़रीबों, बेबसों एवं किसानों की हितैषी होती तो रूस के 15 टुकड़े क्यों होते और चीन में लोग क्यों अपने हक की लड़ाई इस विचारधारा के ख़िलाफ़ लड़ते? जहां तक भारत का सवाल है तो यह विचारधारा पूरी तरह लोगों को गुमराह कर रही है. लोगों को मारना, धमकाना, उनका पैसा छीनना इस विचारधारा के मुख्य कार्य रहे हैं. ये सिर्फ अपना फ़ायदा सोचते हैं, किसी और की परवाह करने का इनके पास वक़्त नहीं है. लेख में शौकत आज़मी और उनके शौहर कैफी आज़मी का उदाहरण बिल्कुल सही है. इनके पास किसी का दु:ख, किसी की तकलीफ सुनने-देखने का वक़्त नहीं होता और कहते हैं कि हम दुखी लोगों के लिए काम करते हैं. मैंने ऐसे कई कॉमरेड देखे हैं, जो फैब इंडिया के कुरते पहनते हैं, फोर स्क्वायर सिगरेट पीते हैं और खुद को फटेहाल लोगों का मसीहा मानते हैं. जनता को ऐसे नेताओं से सतर्क रहना चाहिए.

-खादिजा सिद्दीकी, *ई-मेल से.*

भ्रष्टाचार यानी देशद्रोह

देश में जब भी कोई बड़ी घटना होती है, तभी सरकार जागती है, फिर चल पड़ता है जांच-पड़ताल का सिलसिला. सभी क्षेत्रों में भ्रष्टाचार बढ़ा और नैतिकता का ह्रास हुआ है. न्यायपालिका, शिक्षा, चिकित्सा, सेना एवं विदेश सेवा कोई भी क्षेत्र भ्रष्टाचार से अछूता नहीं है. भ्रष्टाचार देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती है, यह देशद्रोह से कम नहीं है. भ्रष्ट लोगों को वैसी कठोर सज़ा दी जानी चाहिए, जैसी किसी देशद्रोही को दी जाती है.

-आकाश, *ई-मेल से.*

बाप नेता, बच्चे अभिनेता

चौथी दुनिया के 8-14 नवंबर अंक में छपा लेख-बाप नेता, बच्चे अभिनेता बहुत अच्छा लगा. वास्तव में नेता और अभिनेता ही धन के भंडार भर सकते हैं. ये दोनों उधर ही दौड़ते हैं, जिधर धन बरसता है. राजनीति, सिनेमा और खेल में धन की वर्षा होती रहती है, जिसे बटोरना सिर्फ़ नेता, अभिनेता ही जानते हैं. नेता और अभिनेताओं के बच्चे वही सीखेंगे, जो उन्हें सिखाया जाएगा. राजनेताओं ने अपने परिवार के सदस्यों को राजनीति में प्रवेश कराना शुरू किया. राजनीति में परिवारवाद चल पड़ा. जो राजनीति में वर्षों तक छाए रहे, उनकी संतानें भी राजनीति करने लगीं. जब वहां भीड़ और स्पर्धा बढ़ने लगी तो उन्होंने धन कमाने के दूसरे रास्ते तलाशने शुरू किए और नेताओं के बेटे-बेटियां अभिनेता और खिलाड़ी बनकर धन बटोरने में जुट गए.

-सीताराम शर्मा, *सीकर, राजस्थान.*

कंपनी संचालक की मनमानी

मैंने एक पी-5, पेंटियम-4 कंप्यूटर नवगांव से 8 मई, 2006 को खरीदा था. उस पर 3 वर्ष की वारंटी दी गई थी. कंप्यूटर में ख़राबी आने पर कंपनी के संचालक ने उसे मंगाकर दो दिनों बाद मरम्मत करके वापस देने की बात कहकर बिना रसीद दिए रख लिया. सिस्टम वापस लेने जाने पर हर बार संचालक उसके चेन्नई से मरम्मत होकर न आने की बात कहकर परेशान करता रहा. मैंने नवगांव थाने में शिक़ायत दर्ज कराई, पर कोई कार्रवाई न होने पर वकील से परामर्श लेकर फोरम की शरण ली, पर वहां भी न्याय नहीं मिला. ज़िला छतरपुर (मध्य प्रदेश) से मेरा मुकदमा ख़ारिज कर दिया गया. मजबूर होकर मैंने राज्य आयोग भोपाल में मामला दर्ज कराया है, पर यहां से भी इंसाफ मिलने की उम्मीद कम है. उधर मामला वापस लेने के लिए मुझे धमकाया जा रहा है.

-आकाश राय, *हरपालपुर, मध्य प्रदेश.*

आप अपने स्वतंत्र विचार तथा प्रतिक्रियाएं हमें इसी पते पर भेजें. संपादक, चौथी दुनिया, एफ-2, सेक्टर-11 नोएडा, (उत्तर प्रदेश) पिन-201301

ई-मेल पता : feedback@chauthiduniya.com

जब तोप मुक़ाबिल हो

यह कांग्रेस के इम्तहान का समय है

संतोष भारतीय

चौहत्तर में लिखी लाइनें, जिन्हें बुंदेलखंड के जनकवि राम गोपाल दीक्षित ने लिखा था, कौन चलेगा आज देश से भ्रष्टाचार मिटाने को, बर्बरता से लोहा लेने सत्ता से टकराने को, आज देख लें कौन रचाता मौत के संग सगाई है, उठो जवानों तुम्हें जगाने क्रांति द्वार पर आई है, याद आती हैं. संयोग है कि उन दिनों सत्ता में इंदिरा गांधी थीं और उनके ख़िलाफ़ छात्र आंदोलन चल रहा था, जिसका मुख्य मुद्दा भ्रष्टाचार था. छात्र युवा उठ खड़े हुए, इंदिरा जी चुनाव हार गईं, लेकिन जो सत्ता में आए, न उसे संभाल सके और न जनता की आशाएं पूरा कर सके.

फिर आया अस्सी का दशक. राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे. एक साफ बोलने वाला चेहरा था, जिस पर देश ने भरोसा किया और लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार चार सौ बारह सीटों पर उन्हें जीत दिलाई. तीन साल बीतते-बीतते भ्रष्टाचार का मुद्दा ऐसा बना कि उनकी सरकार चली गई. वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने, लेकिन कहानी पुरानी दोहराई गई. वह भी न सत्ता संभाल पाए, न जनता के लिए भ्रष्टाचार से लड़ते शख्स की आकांक्षा पूरी कर पाए. सरकार गिरी, पर सबसे दु:खद रहा राजीव गांधी का शहीद होना. और अब फिर मनमोहन सिंह की सरकार है, यानी कांग्रेस की सरकार है. भ्रष्टाचार का मुद्दा एक बार फिर केंद्रीय मुद्दा बनता जा रहा है. संयोग कह सकते हैं या चिंताजनक हालात कह सकते हैं कि इस बार लोकतांत्रिक संस्थाओं से ज्यादा सुप्रीम कोर्ट चिंतित है. उसकी टिप्पणियां आंख खोलने वाली हैं. सुप्रीम कोर्ट ने एक नायाब काम और किया है. उसने न केवल 2-जी स्पेक्ट्रम घोटाले पर सख्त टिप्पणियां की हैं, बल्कि इलाहाबाद हाईकोर्ट पर भी सख्त टिप्पणियां की हैं. जब सर्वोच्च न्यायालय हाईकोर्ट में चल रही गंदगी से परेशान हो जाए तो गंभीरता सभी को समझ लेनी चाहिए.

कांग्रेस के सामने कोई चुनौती नहीं थी. न प्रधानमंत्री या सोनिया गांधी का स्पेक्ट्रम घोटाले में नाम आ रहा है, पर खामोश रहने और खुली आंखों भ्रष्टाचार देखने के गुनहगार तो ये हैं ही. पर सबसे ज़्यादा आश्चर्य तब होता है, जब कांग्रेस के सहयोगी संगठन राष्ट्रवादी कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस भी कह दें कि जेपीसी बना देनी चाहिए तो क्यों कांग्रेस इसे नहीं मान रही. इतना ही नहीं, सिर से पैर तक सनी डीएमके भी जब कह दे कि उसे कोई एतराज नहीं है तो कांग्रेस का न मानना विरोधियों को नए हथियार दे देगा.

दो तर्क हो सकते हैं कि यदि जेपीसी की जांच चलती है तो वह कांग्रेस के कुछ नेताओं के दरवाज़े पर भी पहुंच सकती है और दूसरा कि यदि जेपीसी बनती है तो अगले तीन साल झूठी सच्ची ख़बरें अख़बारों में आती रहेंगी. दोनों तर्क सही नहीं हैं. कांग्रेस के लिए सुनहरा मौक़ा है कि वह अपने को बिल्कुल पाक साफ साबित कर सकती है और अगर उसका कोई सदस्य इस जांच में आता भी है तो उसे चिंता नहीं करनी चाहिए, उससे पीछा छुड़ाना चाहिए. दूसरा अख़बारों में ख़बरें छपने से वोट नहीं घटते हैं और न बढ़ते हैं. इसका उदाहरण बिहार है, जहां कांग्रेस ने प्रचार पर कितना खर्च किया, टेलीविजन, अख़बार विज्ञापनों से, ख़बरों से भरे थे, लेकिन कितने वोट मिले, दो सौ तैंतालिस सीटों में चार पर जीत मिली, दो सौ में जमानत ज़ब्त हुई.

कांग्रेस को अपनी रणनीति पर, अपनी दिशा पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है. अगर भाजपा की कमजोरियों को भुनाकर ही जीतने की योजना बनानी है तो बिहार की हार को फिर याद करना चाहिए, जहां मुसलमानों तक ने नीतीश को पसंद किया, कांग्रेस को नहीं. वक्त बदल रहा है, नए लोग मतदाता बन रहे हैं. पुराने लोग वायदों का, सपनों का टूटना देख रहे हैं. एक नई सोच आ रही है जो जाति व धर्म से थोड़ी सी अलग है. इसे कांग्रेस को पहचानना चाहिए.

कांग्रेस का एआईसीसी का अधिवेशन हुआ, पर उसमें से कोई उत्साह नहीं निकला, सिर्फ़ सोनिया गांधी को अगला अध्यक्ष बनाने की पुष्टि हुई. अब कांग्रेस का महाअधिवेशन होने जा रहा है. कांग्रेस नेतृत्व की परीक्षा है कि वह कैसा कार्यक्रम कांग्रेस के लोगों के सामने रखता है. यह कार्यक्रम ही संकेत देगा कि बंगाल, आसाम, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और गुजरात के कांग्रेस कार्यकर्ता उत्साह में आते हैं, जी जान से पार्टी को जिताने की कोशिश करते हैं या उसे अपने हाल पर छोड़ देते हैं. कांग्रेस एक गलती कर चुकी है कि उसने एआईसीसी में उन्हें ज़्यादा तरजीह नहीं दी, जिन्होंने काम किया है. अगर ऐसी ही गलती उम्मीदवार चुनने में भी हुई तो फिर कांग्रेस का ईश्वर ही मालिक है.

कांग्रेस के लिए सुनहरा मौक़ा है कि वह अपने को बिल्कुल पाक साफ साबित कर सकती है और अगर उसका कोई सदस्य इस जांच में आता भी है तो उसे चिंता नहीं करनी चाहिए, उससे पीछा छुड़ाना चाहिए. दूसरा, अख़बारों में ख़बरें छपने से वोट नहीं घटते हैं और न बढ़ते हैं. इसका उदाहरण बिहार है, जहां कांग्रेस ने प्रचार पर कितना ख़र्च किया, टेलीविजन, अख़बार विज्ञापनों से, ख़बरों से भरे थे, लेकिन कितने वोट मिले, दो सौ तैंतालिस सीटों में चार पर जीत मिली, दो सौ में ज़मानत ज़ब्त हुई. कांग्रेस को अपनी रणनीति पर, अपनी दिशा पर गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है.

उत्तर प्रदेश में संगठन खड़ा करने का काम रीता बहुगुणा नहीं कर रही हैं, बल्कि कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह कर रहे हैं. उनकी रणनीति है कि जल्दी से जल्दी उम्मीदवारों की घोषणा कर दो, फिर इन उम्मीदवारों के इर्द-गिर्द ही संगठन का ढांचा बनाओ. उम्मीदवार अवश्य बूथ स्तर की कमेटियां बनाएगा, इससे कांग्रेस का गांव तक का नया ढांचा खड़ा हो जाएगा. राहुल गांधी ने इस योजना को सहमति दे दी है. आशा है कि जनवरी तक शायद उत्तर प्रदेश में कांग्रेस विधानसभा के लिए उम्मीदवारों की एक बड़ी सूची जारी कर दे.

बिहार के बाद यह दूसरा प्रयोग होगा. इस प्रयोग में एक ही ख़तरा है कि कांग्रेस ने यदि तीस प्रतिशत भी ग़लत उम्मीदवारों को टिकट दिए तो पूरा संगठन ही भविष्यहीन हो जाएगा. इन सारे राज्यों में विशेषकर उत्तर प्रदेश में अगर किसी की प्रतिभा की परीक्षा होनी है तो वह राहुल गांधी की होनी है. राहुल गांधी कांग्रेस के अघोषित सर्वमान्य भावी प्रधानमंत्री हैं. उनके विचार, उनका दिमाग, उनकी भाषा और उनकी समझ के साथ संगठन क्षमता की भी परीक्षा इन चुनावों में होगी. सभाओं में आने वाली भीड़ को वोट में बदलने की कुशलता भी राहुल गांधी को दिखानी होगी. इसमें वह अकेले होंगे, उनकी मदद उनकी मां नहीं कर पाएंगी, क्योंकि जब सवाल होंगे तो केवल वही सामने होंगे. राहुल गांधी पिछली बंगाल यात्रा में शांति निकेतन गए थे. वहां छात्रों ने उनसे पूछा कि जब वह प्रधानमंत्री बनेंगे तो शिक्षा में बदलाव का उनका खाका क्या होगा. राहुल गांधी ने जवाब दिया कि उनके पास प्रधानमंत्री बनने से ज़रूरी काम हैं. सवाल यह नहीं था, सवाल था शिक्षा में बदलाव का कोई नक्शा उनके पास है या नहीं, वह सवाल टाल गए. शांति निकेतन के छात्र निराश हुए. देश के प्रधानमंत्री पद पर जाने वाले को बहुत से सवालों के जवाब आने चाहिए और यही इम्तहान राहुल गांधी का आने वाले राज्यों के विधानसभाओं के चुनावों में होने वाला है, जिसकी शुरुआत कांग्रेस महाअधिवेशन में होनी है.

देश के कांग्रेसजन जानना चाहेंगे, देश के लोग जानना चाहेंगे कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी देश की समस्याओं पर क्या बोलते हैं. पिछली एआईसीसी में भ्रष्टाचार के सवाल पर किसी ने मुंह नहीं खोला और आज भ्रष्टाचार का सवाल देश में चारों ओर खड़ा हो गया है. इस महाअधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष और उसके महासचिवगण भ्रष्टाचार पर कोई बात कहते भी हैं या नहीं, यह देखना दिलचस्प होगा. ग़ैर भाजपा दलों की अनुपस्थिति ने कांग्रेस की प्रासंगिकता बढ़ा दी है. लेकिन इस प्रासंगिकता को तार्किक साबित करना ख़ुद कांग्रेस के हाथ में है. कांग्रेस अगर संतुलित दिमाग़ से नहीं चली तो यह अपने आप मुसीबत बुलाने वाली पार्टी बन जाएगी. जैसे उसने राजा के भ्रष्टाचार की मुसीबत अपने सिर ले ली. इसलिए कांग्रेस के लिए इम्तहान तो है ही.

संपादक
editor@chauthiduniya.com

कोरियाई जंग के मायने

राजीव रंजन तिवारी

उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच प्रत्यक्षत: भले ही जंग जारी हो, लेकिन परोक्षत: इसके कई खास मायने हैं. एक तरफ जहां उत्तर कोरिया की मदद के लिए चीन लाठी लिए खड़ा है तो दक्षिण कोरिया का बाल बांका न होने देने के लिए अमेरिका बेचैन है. इसके अलावा उत्तर कोरिया के पीछे रूस है तो दक्षिण कोरिया के पीछे जापान. इस तरह इन दोनों छोटे देशों के बीच छिड़ी लड़ाई का दुष्प्रभाव अमेरिका और चीन पर पड़ सकता है. यानी परदे के पीछे दोनों देशों के रिश्ते में पहले से अधिक खटास बढ़ सकती है. हाल में अमेरिका और दक्षिण कोरिया की सेनाओं द्वारा संयुक्त सैन्य अभ्यास किया गया था. इससे चिंतित और परेशान उत्तर कोरिया ने एक संदेश भेजकर दक्षिण कोरिया से जानना चाहा कि क्या यह सैन्य अभ्यास उस पर हमले की तैयारी है? इसका कोई जवाब आता, इसके पहले ही उत्तर कोरिया ने बमबारी शुरू कर दी. तबसे तकरार ज़्यादा बढ़ गई है. समझा जा रहा है कि उत्तर कोरिया द्वारा दक्षिण कोरिया पर की गई बमबारी के बाद दुनिया के अन्य देश भी चिंतित हैं. दरअसल, उत्तर और दक्षिण कोरिया की लड़ाई अब सिर्फ़ इन दो देशों तक ही सीमित नहीं रही है,

बल्कि अब यह चीन और अमेरिका के बीच वर्चस्व की लड़ाई में बदलने लगी है. यही कारण है कि दक्षिण कोरिया पर हमला होते ही अमेरिका ने अपना विमान वाहक युद्धपोत यूएसएस जार्ज वाशिंगटन रवाना कर दिया. इस पोत पर 75 लड़ाकू विमान और 6000 सैनिक तैनात हैं. ऐसे में माना जा रहा है कि अगर उत्तर कोरिया पर किसी भी तरह का कोई हमला होता है तो चीन भी मैदान में कूद सकता है, क्योंकि वह पिछले छह दशकों से उत्तर कोरिया की मदद करता आ रहा है. इसकी पुष्टि इसी से हो जाती है कि 1950 में दक्षिण कोरिया के ख़िलाफ़ हुए युद्ध में चीन ने उत्तर कोरिया के समर्थन में अपनी सेना तक भेज दी थी. हालांकि मौजूदा स्थिति में अभी चीन चुप्पी साधे हुए है. फिर भी यह आशंका जताई जा रही है कि अगर अमेरिका उत्तर कोरिया के ख़िलाफ़ किसी भी सैन्य कार्रवाई को अंजाम देता है तो चीन भी चुप नहीं बैठेगा. उत्तर कोरिया और चीन के बीच आपसी तालमेल बनाए रखने के लिए 1961 में एक समझौता भी हुआ था, जिसमें कहा गया था कि चीन या उत्तर कोरिया में से किसी पर भी हमला होने की स्थिति में दोनों देश मिलकर लड़ेंगे.

माना जा रहा है कि अगर उत्तर कोरिया पर किसी भी तरह का कोई हमला होता है तो चीन भी मैदान में कूद सकता है, क्योंकि वह पिछले छह दशकों से उत्तर कोरिया की मदद करता आ रहा है. इसकी पुष्टि इसी से हो जाती है कि 1950 में दक्षिण कोरिया के ख़िलाफ़ हुए युद्ध में चीन ने उत्तर कोरिया के समर्थन में अपनी सेना तक भेज दी थी.

दरअसल अमेरिका चाहता है कि उत्तर कोरिया परमाणु हथियार न बनाए. इसके लिए उसके राजनयिक अंतरराष्ट्रीय समुदाय को उत्तर कोरिया के ख़िलाफ़ लामबंद कर रहे हैं. जबकि उत्तर कोरिया चाहता है कि इस दिशा में कोई भी क़दम छह पक्षीय (उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, चीन, अमेरिका, जापान एवं रूस) बातचीत के बाद ही उठाया जाए. इस संबंध में दो वर्ष पहले चर्चा भी शुरू हुई थी, जो अपरिहार्य कारणों से बंद हो गई. अब बदले हालात में दक्षिण कोरिया पर हमला कर उत्तर कोरिया यह बताना चाहता है कि वह किसी के दबाव में नहीं आएगा. यहां यह भी उल्लेखनीय है कि चीन की मदद से ही उत्तर कोरिया परमाणु हथियारों का जखीरा एकत्र कर चुका है. इसी के चलते अमेरिका ने उस पर प्रतिबंध भी लगाए हैं. यह बात भी चीन को खटकती है. नतीजतन वह खुलकर उत्तर कोरिया का साथ दे रहा है. बताते हैं कि कम्युनिस्ट शासन वाले उत्तर कोरिया का दुनिया में एकमात्र साथी चीन है. वहां की सेना और अर्थ व्यवस्था पूरी तरह चीन के बल पर काम करती है. बताते हैं कि 1953 में युद्ध विराम के बावजूद दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच किसी भी संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए गए. यही वजह है कि दोनों देशों के बीच शीत युद्ध हमेशा चलता रहता है. इसी क्रम में दक्षिण कोरिया ने 25-28 जुलाई 2010 तक चार दिवसीय युद्धाभ्यास शुरू किया था. इससे नाराज़ होकर उत्तर कोरिया ने कठोर चेतावनी दी थी कि युद्धाभ्यास होने पर वह परमाणु हमला भी कर सकता है. दरअसल उत्तर कोरिया ने मार्च में टॉरपीडो हमला कर दक्षिण कोरिया का एक पोत डुबो दिया था. उस हमले में दक्षिण कोरिया के 46 लोगों की मौत भी हुई थी. दोनों देशों की मौजूदा स्थिति यह है कि दक्षिण कोरिया पूंजीवाद का दामन थाम विकास की बुलंदियों को छू रहा है, वहीं उत्तर कोरिया में साम्यवाद की बयार बह रही है. विदेशी मामलों के जानकार बताते हैं कि चीन के समर्थन से उत्तर कोरिया ख़ुद को इतना समृद्ध समझने लगा है कि वह अमेरिका को भी भाव नहीं दे रहा. नतीजतन अमेरिका के इशारे पर दक्षिण कोरिया की सेनाएं अब उत्तर कोरिया पर हमले के लिए तैयार हैं. दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली म्यांग बेक ने अपने सेना प्रमुख से कह दिया है कि यदि अब कोई बमबारी होती है तो उसका करारा जवाब देने के लिए तैयार रहें. यही वजह है कि उत्तर कोरिया के मिसाइल बेस पर दक्षिण कोरिया हमला करने की तैयारी में है. उधर उत्तर कोरिया के विदेश मामलों के विशेषज्ञों का मानना है कि दक्षिण कोरिया पर हमला अमेरिका पर बातचीत करने के लिए दबाव बनाने के उद्देश्य से किया गया है.

उधर दोनों देशों के झगड़े की पृष्ठभूमि पर नज़र डालें तो पता चलेगा कि उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच सीमा को लेकर काफी समय से विवाद है. इनकी सीमाओं पर विश्व की किसी भी सीमा से ज़्यादा जवान तैनात हैं. दोनों देशों के बीच 1950 से 1953 तक युद्ध हुआ. इस युद्ध में दक्षिण कोरिया को संयुक्त राष्ट्र का समर्थन था, जबकि उत्तर कोरिया को चीन और रूस का. यदि इतिहास पर नज़र डालें तो पता चलेगा कि कोरियन द्वीप पर 1910 से 1945 तक जापान का राज था. द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जापान ने आत्मसमर्पण किया और संयुक्त राष्ट्र ने इसे दो हिस्सों में बांट दिया. युद्ध के बाद भी अमेरिकी सेनाओं की मौजूदगी दक्षिणी हिस्से में रही, जबकि रूसी सेनाओं की उत्तरी हिस्से में. बाद में विदेशी सेनाएं चली गईं, लेकिन सीमा को लेकर दोनों देशों में विवाद शुरू हो गया. 25 जून, 1950 को उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर हमला कर दिया. इसके बाद दोनों देशों ने सीमा विवाद सुलझाने की कई नाकाम कोशिशें कीं, लेकिन विवाद आज भी जारी है.

feedback@chauthiduniya.com

डुरान का कहना है कि ऊर्जा कंपनियां नदियों पर बांध बनाती हैं, उससे ऊर्जा तैयार करती हैं और लोगों को बेचती हैं.

सूचना का अधिकार
जानने का अधिकार जीने का अधिकार
चौथी दुनिया की पहल

अगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो बीमार

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का महत्व किसी बड़े अस्पताल से कम नहीं होता, क्योंकि यही वह केंद्र है, जहां बच्चों के टीकाकरण और गर्भवती महिलाओं के समुचित इलाज की व्यवस्था करने की ज़िम्मेदारी सरकार की होती है. यही वह केंद्र है, जहां देश के नौनिहालों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं. भारत में ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा की हालत क्या है, यह किसी से छिपा नहीं है. कुछ राज्यों में स्थिति अच्छी है, लेकिन ज़्यादातर जगहों पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की हालत ख़ुद एक मरीज की तरह है. ऐसे में आप सभी से कुछ सवालों का जवाब जानना ज़रूरी है. जैसे, क्या आपकी पंचायत या वार्ड में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है? अगर हां, तो उसकी हालत क्या है? क्या वहां नर्स, डॉक्टर एवं कंपाउंडर नियमित रूप से आते हैं, दवाएं मिलती हैं, जांच की सुविधा है? अगर इनमें से कोई भी एक सुविधा आपको नहीं मिलती है तो आप क्या करते हैं, शिक़ायत या कुछ और? चौथी दुनिया के सूचना अधिकार अभियान के तहत इस अंक में हम आपको यही बता रहे हैं कि आप कैसे उपरोक्त सुविधाएं पा सकते हैं, वह भी बड़ी आसानी से. इसके लिए आपको बस एक आवेदन तैयार करना है और कुछ सवाल पूछने हैं. सवाल क्या होंगे, यह हम आपको बता रहे हैं. फ़िलहाल इस अंक में हम आपको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर नियुक्त नर्स (एएनएम) के बारे में बता रहे हैं. अगर आपके केंद्र पर नियुक्त एएनएम नियमित रूप से नहीं आती या देर से आती है या टीकाकरण अथवा दवा वितरण का काम सही समय और सही ढंग से नहीं होता है तो आप इस अंक में प्रकाशित आवेदन पत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं. तय मानिए, सिर्फ़ एक आवेदन करने से आपके केंद्र की हालत सुधर जाएगी. नर्स सही समय पर नियमित रूप से आएगी, टीकाकरण एवं दवा वितरण का काम सुधर जाएगा. आपको अपने आवेदन में एएनएम से संबंधित उपस्थिति रजिस्टर की प्रति मांगनी है. उनकी छुट्टियों के बारे में पूछना है. टीकाकरण से लाभांवित होने वाले बच्चों की सूची मांगनी है. ज़ाहिर है, जब आप इतने सारे सवाल पूछेंगे तो किसी भी सरकारी विभाग के लिए जवाब दे पाना मुश्किल हो जाएगा. किसी पचड़े में फंसने के बजाय वह स्थिति सुधारने पर ज़्यादा ध्यान देगा. हम उम्मीद करते हैं कि आप इस आवेदन का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे. साथ ही अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करेंगे, क्योंकि यह एक अभियान है कुव्यवस्था और भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ और इसमें आपकी भागीदारी ज़रूरी है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

यदि आपने सूचना क़ानून का इस्तेमाल किया है और अगर कोई सूचना आपके पास है, जिसे आप हमारे साथ बांटना चाहते हैं तो हमें वह सूचना निम्न पते पर भेजें. हम उसे प्रकाशित करेंगे. इसके अलावा सूचना का अधिकार क़ानून से संबंधित किसी भी सुझाव या परामर्श के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं या हमें पत्र लिख सकते हैं. हमारा पता है :

चौथी दुनिया

एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर) उत्तर प्रदेश, पिन -201301
ई-मेल : rti@chauthiduniya.com

आवेदन का प्रारूप
(एएनएम के संबंध में)

सेवा में,
लोक सूचना अधिकारी
(विभाग का नाम)
(विभाग का पता)

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन

महोदय,
.....ग्राम पंचायत में कार्यरत एएनएम के संबंध में निम्नलिखित सूचनाएं उपलब्ध कराएं:

1. इस ग्राम पंचायत में कार्यरत एएनएम के संबंध में निम्नलिखित सूचनाएं उपलब्ध कराएं:
क. नाम
ख. पद
ग. इस पंचायत में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि
घ. कार्यभार/जिम्मेदारी का विवरण
ड. प्रतिदिन ड्यूटी पर आने और जाने का समय

2. उक्त एएनएम के उपस्थिति रजिस्टर की पिछले छह महीनों की प्रति उपलब्ध कराएं.

3. उक्त एएनएम द्वारा पिछले एक वर्ष में इस ग्राम पंचायत में किए गए टीकाकरण और दवा वितरण कार्यों की सूची उपलब्ध कराएं, जिसमें निम्नलिखित सूचनाएं अवश्य शामिल हों:
क. लाभार्थी का नाम व पता
ख. लाभार्थी को टीका लगाने या दवा दिए जाने की तारीख
ग. दवा और टीके का नाम

4. उक्त एएनएम अगर समय पर गांव का दौरा नहीं करती है तो उसके ख़िलाफ क्या कार्यवाही किए जाने का प्रावधान है? कृपया इस संबंध में नियमों/नीति निर्देशों की प्रतियां उपलब्ध कराएं.

5. इस पंचायत का कार्यभार संभालने के बाद अब तक उक्त एएनएम के खिलाफ देर से आने या अनुपस्थित रहने से संबंधित यदि कोई शिकायत प्राप्त हुई है तो उसका विवरण उपलब्ध कराएं, जिसमें निम्नलिखित सूचनाएं अवश्य शामिल हों:
क. शिकायत करने वाले का नाम
ख. शिकायत का संक्षिप्त विवरण
ग. शिकायत की तारीख
घ. शिकायत पर की गई कार्यवाही का विवरण
ड. कार्यवाही करने वाले अधिकारी का नाम, पद एवं पता

मैं आवेदन शुल्क के रूप में.....रुपये अलग से जमा कर रहा/रही हूं.
या
मैं बीपीएल कार्डधारक हूं, इसलिए सभी देय शुल्कों से मुक्त हूं. मेरा बीपीएल कार्ड नंबर.....है.

यदि मांगी गई सूचना आपके विभाग/कार्यालय से संबंधित न हो तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (3) का संज्ञान लेते हुए मेरा आवेदन संबंधित लोक सूचना अधिकारी को पांच दिनों की समयावधि के अंतर्गत हस्तांतरित करें. साथ ही अधिनियम के प्रावधानों के तहत सूचना उपलब्ध कराते समय प्रथम अपील अधिकारी का नाम और पता अवश्य बताएं.

भवदीय

नाम.....
पता.....
फोन नंबर.....

संलग्नक.....
(यदि कुछ हो तो)

ज़रा हट के

दुनिया का सबसे बोरिंग दिन

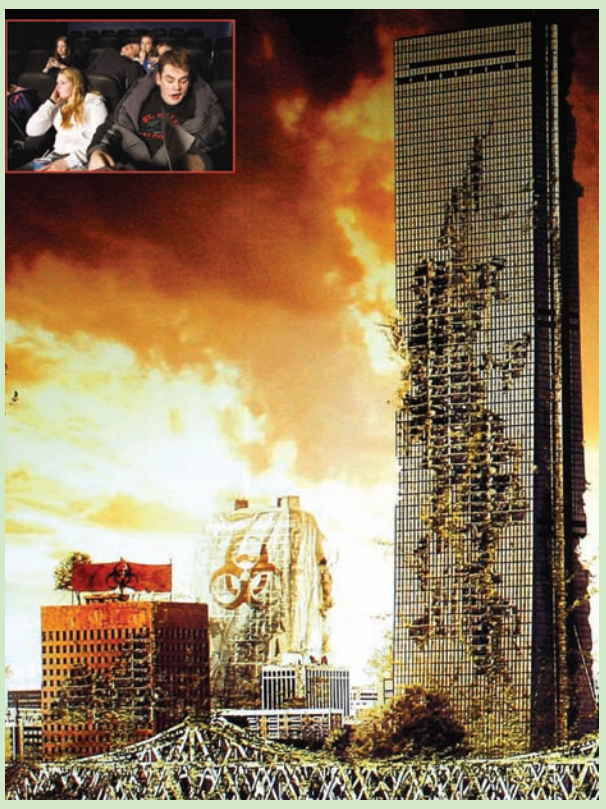

आपने अपने आसपास दुनिया के सबसे बोरिंग लोग तो देखे होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे बोरिंग दिन कौन सा है? नहीं पता, चलो हम ही बता देते हैं. वह दिन है 11 अप्रैल, 1954. इस दिन कुछ भी विशेष नहीं हुआ था. शोधकर्ता इसे 20वीं सदी का सबसे बोरिंग दिन मान रहे हैं. इससे पहले उस दिन को सबसे बोरिंग दिन के रूप में चिन्हित किया गया था, जिस दिन बीबीसी रेडियो के पास समाचार नहीं थे. समाचार वाचक रेडियो पर आया और उसने उद्घोषणा की कि आज कोई समाचार नहीं है! परंतु अब शोधकर्ताओं ने 11 अप्रैल, 1954 को सर्वाधिक बोरिंग दिन के रूप में मान्यता दी है. अब आप सोच रहे होंगे कि किस पैमाने से यह तय किया गया कि यही दिन सबसे बोरिंग है. चलिए आपको वह तकनीक भी बताते हैं. हर दिन कोई न कोई घटना होती रहती है, परंतु माना गया कि 1954 के अप्रैल माह की 11 तारीख़ को कुछ भी विशेष नहीं हुआ था.

शोधकर्ताओं ने इसके लिए 30 करोड़ महत्वपूर्ण घटनाओं को एक विशेष कंप्यूटर शोध कार्यक्रम में डाला और गणना की. कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के विलियम टनस्टाल द्वारा विकसित किए गए इस सॉफ्टवेयर ने पता लगाया कि 11 अप्रैल, 1954 को 2-3 छोटी-मोटी घटनाओं को छोड़कर कुछ भी विशेष नहीं हुआ. इस दिन बेल्जियम में चुनाव हुए थे, तुर्की के एक बुद्धिजीवी का जन्म हुआ था और जैक शफलबोटम नामक फुटबॉल खिलाड़ी का निधन हुआ था. इसके अलावा इस दिन कुछ नहीं हुआ. हालांकि कहने वाले इन्हें भी खास घटनाएं मान सकते हैं, लेकिन शोधकर्ताओं का कुछ और ही सोचना है.

सूरज मेरी संपत्ति है

यूं तो हम चांद को मामा और सूरज को अपना आराध्य देव बताते रहते हैं, लेकिन वैज्ञानिक तौर पर यह किसी की भी संपत्ति नहीं है. दरअसल स्पेन की एक महिला ने दावा किया है कि सूर्य उसकी संपत्ति है और उसने अपनी इस संपत्ति को पंजीकृत भी कराया है. अब हो सकता है कि आपको सूर्य की रोशनी पाने के लिए भी शुल्क चुकाना पड़े! पढ़ने में यह बात आपको विचित्र लग सकती है, लेकिन है सौ फ़ीसदी सही. अब सवाल उठता है कि सूर्य क्या किसी की संपत्ति हो सकता है? 1967 में स्वीकृत की गई बाह्य अवकाश ट्रिटी के अनुसार, कोई भी देश धरती से बाहर अंतरिक्ष के किसी भी स्थान पर अपना स्वामित्व नहीं जता सकता है, परंतु इस ट्रिटी में आम लोगों का उल्लेख नहीं किया गया है. यानी कोई व्यक्ति चाहे तो ग्रहों और तारों पर अपना स्वामित्व जता सकता है और ऐसा पहले हुआ भी है. अमेरिका के कुछ लोगों ने चंद्रमा, मंगल और शुक्र ग्रह पर अपना क़ब्ज़ा होने का दावा किया है, परंतु सूर्य अभी तक इस तरह के दावों से बचा हुआ था. अब स्पेन की 49 वर्षीय एंजेल्स डुरान ने दावा किया है कि उन्होंने सूर्य पर अपना दावा प्रस्तुत किया था, जिसे मान्यता भी मिली है. उन्होंने साक्ष्य के रूप में एक दस्तावेज जारी किया है, जिसमें लिखा है कि डुरान सूर्य नामक तारे की मालिक है, जो पृथ्वी से क़रीब 14,96,00,000 किलोमीटर दूर है.

डुरान का कहना है कि ऊर्जा कंपनियां नदियों पर बांध बनाती हैं, उससे ऊर्जा तैयार करती हैं और लोगों को बेचती हैं. नदी का पानी तो सबका है, फिर कोई कंपनी उस पर अपना अधिकार कैसे जता सकती है. जब यह हो सकता है तो फिर वह सूर्य की मालिक क्यों नहीं बन सकती हैं. डुरान अब स्पेन के उद्योग मंत्रालय से मिल रही हैं, ताकि भविष्य की योजनाएं तैयार की जा सकें. बहरहाल उनका इरादा लोगों से सूर्य ऊर्जा के बदले शुल्क वसूलना है. इसका 50 फ़ीसदी हिस्सा सरकार को, 30 फ़ीसदी यूके के पेंशन फंड को और 10 फ़ीसदी भुखमरी से निपटने के लिए बने फंड को दिया जाएगा. 10 फ़ीसदी शोध में ख़र्च होगा और बाक़ी डुरान अपने पास रखेंगी. मामला तो दिलचस्प है. फ़ैसला आने तक आप मुफ्त में सूर्य की सेवा ले सकते हैं.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

राशिफल

दिल्ली, 20 दिसंबर–26 दिसंबर 2010

मेष (21 मार्च से 20 अप्रैल)
शिक्षा-प्रतियोगिता की दिशा में सफलता मिलने के योग हैं. व्यवसायिक योजना को बल मिलेगा. वाद-विवाद की स्थिति हितकर नहीं होगी. दांपत्य जीवन में कटुता आ सकती है. किसी बात को लेकर भय सा बना रहेगा.

वृष (21 अप्रैल से 20 मई)
मन अज्ञात भय से ग्रस्त रहेगा. मान, पद एवं प्रतिष्ठा की दिशा में वृद्धि होगी. आय के नए स्रोत बनेंगे. प्रणय संबंध मधुर होंगे. पूजा-पाठ में शामिल होने से मन को शांति मिलेगी. किसी अभिन्न मित्र से मुलाकात होने की संभावना है. अधीनस्थ कर्मचारी से तनाव हो सकता है.

मिथुन (21 मई से 20 जून)
व्यवसायिक एवं पारिवारिक समस्या पैदा होने की आशंका है. व्यर्थ की उलझनें मन को भयभीत करेंगी. राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति होगी. इस सप्ताह आप दूसरों की सहायता करने के लिए तत्पर रहेंगे.

कर्क (21 जून से 20 जुलाई)
पिता या उच्चाधिकारी का भरपूर सहयोग मिलेगा. स्थानांतरण एवं परिवर्तन की दिशा में किया जा रहा प्रयास सफल होगा. संतान के दायित्व की पूर्ति होगी. भारी व्यय का सामना करना पड़ सकता है. स्वास्थ्य पर ध्यान दें.

सिंह (21 जुलाई से 20 अगस्त)
आपके पराक्रम एवं वर्चस्व में वृद्धि होगी. जीवनसाथी का सहयोग एवं सानिध्य मिलेगा. सामाजिक जीवन में अपनी ज़िम्मेदारियों का ठीक से निर्वाह करें. स्वास्थ्य शिथिल रहेगा. साधना में मन लगाने से सफलता मिलने के योग हैं.

कन्या (21 अगस्त से 20 सितंबर)
रक्तचाप या हृदय रोगी अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें. अपनी योजनाओं पर अगर ध्यान देंगे तो अच्छा लाभ प्राप्त होगा. मांगलिक कार्यों के लिए किया जा रहा प्रयास सफल साबित होगा. ननिहाल पक्ष से लाभ के योग हैं. वाहन प्रयोग में सावधानी अपेक्षित है.

तुला (21 सितंबर से 20 अक्टूबर)
परिवारीजनों से कष्ट मिल सकता है. वाणी को मधुर बनाए रखें. उदर विकार या त्वचा रोग से पीड़ित हो सकते हैं. कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय न लें. अचानक कहीं यात्रा पर जाना पड़ सकता है.

वृश्चिक (21 अक्टूबर से 20 नवंबर)
इस सप्ताह सामाजिक कार्यों में अधिक व्यस्त रहेंगे. आपके द्वारा कुछ ऐसे कार्य होंगे, जिनकी आपके उच्चाधिकारी प्रशंसा करेंगे. आप पुराने रिश्तों को सुधारने की दिशा में आगे बढ़ेंगे. आंख संबंधी कोई बीमारी परेशानी का कारण बन सकती है.

धनु (21 नवंबर से 20 दिसंबर)
जीवनसाथी का सहयोग एवं सानिध्य मिलेगा. आप पूरे आत्मविश्वास के साथ काम को अंजाम देंगे, जिससे अच्छी सफलता मिलेगी. मकान- संपत्ति आदि की दिशा में किया जा रहा प्रयास सार्थक होगा. राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति होगी.

मकर (21 दिसंबर से 20 जनवरी)
किसी रिश्तेदार से तनाव मिल सकता है. यात्रा-देशाटन की स्थिति सुखद एवं लाभप्रद होगी. किया गया परिश्रम सार्थक होगा. पिता या उच्चाधिकारी के कृपापात्र होंगे. व्यय पर नियंत्रण बनाकर रखें.

कुंभ (21 जनवरी से 20 फरवरी)
इस सप्ताह संयम रखना आपके लिए हितकर होगा. रचनात्मक क्षेत्र में किया जा रहा प्रयास सफल साबित होगा. वाहन सावधानी से चलाएं, वरना दुर्घटना हो सकती है.

मीन (21 फरवरी से 20 मार्च)
फिज़ूलख़र्ची पर नियंत्रण रखें, मन प्रसन्न रहेगा. परिवार के लोगों के स्वास्थ्य की अनदेखी महंगी पड़ सकती है. व्यय की अधिकता रहेगी. कार्यक्षेत्र में रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है. ईश्वर के प्रति आस्था बढ़ेगी.

पंडित सुदर्शन
feedback@chauthiduniya.com

प्रवासी कामगारों के साथ पूरी दुनिया में बुरा बर्ताव किया जाता है, क्योंकि उनके पास कोई अधिकार नहीं होते और न ही स्थानीय कानूनों में उनकी सुरक्षा के लिए कोई प्रावधान होता है.

मध्य-पूर्व में प्रवासी कामगारों का हाल

नए ज़माने की ग़ुलामी

सउदी अरब में प्रवासी कामगारों के साथ ऐसा बर्ताव कोई नई बात नहीं है, लेकिन स्थानीय लोग ऐसा करने के बाद भी बच निकलते हैं तो इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि तमाम मुश्किलों के बावजूद एशियाई श्रमिक नौकरी की तलाश में वहां बड़ी संख्या में जाने के लिए तैयार रहते हैं. ताजा आंकड़ों के मुताबिक, केवल इंडोनेशिया से लगभग 80,000 श्रमिक हर साल सउदी अरब पहुंचते हैं. मुस्तफा के साथ दुर्व्यवहार के बारे में पूछे जाने पर इंडोनेशिया के विदेश मंत्री बस इतना ही कहते हैं कि यह कोई नई बात नहीं है, यह तो होता ही रहता है.

मध्य-पूर्व के देशों में जाकर काम करने वाले एशियाई प्रवासियों का जीवन नारकीय से कम नहीं है. शारीरिक उत्पीड़न, यातनाएं और क्रूरता उनकी रोजाना की ज़िंदगी का हिस्सा हैं. श्रीलंका के अख़बार डेली मिरर की एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार, पिछले छह माह में अकेले बहरीन से 300 से भी ज़्यादा महिला श्रमिक श्रीलंका वापस गई हैं. उन सबकी शिक़ायतें एक जैसी हैं, शारीरिक उत्पीड़न, यौन शोषण, क्षमता से ज़्यादा काम करने की मजबूरी और वेतन न मिलना. बहरीन में श्रीलंका के कॉन्सुल हिग्गोडा का कहना है कि श्रीलंकाई दूतावास के पास बड़ी संख्या में ऐसे मामले आते हैं, जिनमें महिला श्रमिकों ने अपने नियोक्ता पर उत्पीड़न का आरोप लगाया हो. इनमें कुछ ऐसी हैं, जिन्हें महीनों तक वेतन नहीं दिया जाता है, बीमारी की हालत में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाती है और भरपेट खाना तक नहीं मिलता. उनके मालिक हिंसक व्यवहार करते हैं, शारीरिक शोषण करते हैं और उन्हें ज़बरदस्ती घर जाने से रोकते हैं. यदि ये महिला कामगार नौकरी छोड़ना चाहती हैं और पुलिस में शिकायत करती हैं तो मालिक उन्हें भगोड़ा घोषित कर देते हैं. इसका परिणाम यह होता है कि कुछ दिन जेल में रहने के बाद उन्हें वापस अपने देश भेज दिया जाता है. इसी तरह का एक मामला सुमिआती बिनती सालन मुस्तफा का है. 23 साल की सुमिआती इंडोनेशिया की रहने वाली है और सउदी अरब में काम करती है. भीषण शारीरिक यातना के बाद कुछ दिनों पहले उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया. उसके मालिकों ने उसके मुंह और चेहरे को चाकू से गोद दिया था और पूरे शरीर पर गर्म लोहे की छड़ों के निशान थे. उसके चेहरे की हालत ऐसी हो गई थी कि देखकर डर लगता था. लेकिन वह जिनके लिए काम करती थी और जिन्होंने उसकी यह हालत कर दी थी, उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की गई और वे अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं. हालांकि सउदी सरकार ने इंडोनेशियाई अधिकारियों को कार्रवाई का आश्वासन दिया था, लेकिन यह कोरा आश्वासन था.

सउदी अरब में प्रवासी कामगारों के साथ ऐसा बर्ताव कोई नई बात नहीं है, लेकिन स्थानीय लोग ऐसा करने के बाद भी बच निकलते हैं तो इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि तमाम मुश्किलों के बावजूद एशियाई श्रमिक नौकरी की तलाश में वहां बड़ी संख्या में जाने के लिए तैयार रहते हैं. ताजा आंकड़ों के मुताबिक़, केवल इंडोनेशिया से लगभग 80,000 श्रमिक हर साल सउदी अरब पहुंचते हैं. मुस्तफा के साथ दुर्व्यवहार के बारे में पूछे जाने पर इंडोनेशिया के विदेश मंत्री बस इतना ही कहते हैं कि यह कोई नई बात नहीं है, यह तो होता ही रहता है. सच्चाई यह है कि इन देशों की सरकारें उन पैसों के लिए ज़्यादा चिंतित हैं, जो ये कामगार अपने घर भेजते हैं. अधिकारियों की इस चुप्पी का राज भी इसी में छुपा है. मानवाधिकार संस्था ह्यूमन राइट्स वॉच के अनुसार, मध्य-पूर्व के देशों में घरेलू नौकर का काम करने वाले अधिकांश एशियाई कामगार गुलामों की तरह रहते हैं. केवल सउदी अरब में ही 8.8 मिलियन से ज़्यादा विदेशी कामगार हैं, जिनमें से अधिकतर भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और इंडोनेशिया जैसे देशों से आए हैं. काम के गंदे माहौल, अमानवीय शर्तें और लंबे समय तक रुकने के बावजूद उन्हें यहां की नागरिकता नहीं मिलती और वे दुर्व्यवहार के शिकार होते रहते हैं. उनके पास कोई अधिकार नहीं होते और क़ानून भी उनकी मदद नहीं करता. स्थानीय पुलिस और अपने देश की सरकार द्वारा उपेक्षित ये प्रवासी कामगार नौकरी नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि वे वापस स्वदेश भेज दिए जाने से डरते हैं. पूरे मध्य-पूर्व में ऐसा ही होता है और शारीरिक एवं मानसिक प्रताड़ना के सैकड़ों मामले नियमित रूप से सामने आते रहते हैं. दुबई में बनी बहुमंजिला इमारतों में हज़ारों दक्षिण एशियाई श्रमिकों का ख़ून-पसीना लगा है, लेकिन वे यहां रोज़ाना आने वाले लाखों पर्यटकों और ख़रीदारों की निगाहों से पूरी तरह ओझल हैं.

उमाय्यदों के शासनकाल में अरब मुसलमानों को सामाजिक ढांचे में शीर्ष स्थान हासिल था, जबकि गैर अरबी मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक बना दिया गया था. कुरान की इजाजत न होने के बावजूद पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद अरबी पहचान की भावना जोर पकड़ती गई.

कुछ साल पहले पाकिस्तान के चाइल्ड जॉकीज का मामला सामने आया था. पांच-छह साल की उम्र के अबोध बच्चों को दौड़ते हुए ऊंटों के साथ बांध दिया जाता था. कई बच्चे मौत का शिकार हो गए तो कई सारी उम्र के लिए अपाहिज होकर रह गए. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसके ख़िलाफ़ काफी हल्ला-हंगामा हुआ, लेकिन पाकिस्तान की सरकार ने कुछ नहीं किया, वह ख़ामोश बैठी रही. सालों तक यह अमानवीय प्रथा बदस्तूर जारी रही. अंत में संयुक्त अरब अमीरात की सरकार ने इस पर पाबंदी लगाई. प्रवासी कामगारों के साथ पूरी दुनिया में बुरा बर्ताव किया जाता है, क्योंकि उनके पास कोई अधिकार नहीं होते और न ही स्थानीय क़ानूनों में उनकी सुरक्षा के लिए कोई प्रावधान होता है. लेकिन इस मामले में जितनी ख़राब हालत मध्य-पूर्व के देशों में है, उतनी शायद कहीं और नहीं है. इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि कामगारों के साथ बुरा व्यवहार करने वाले नियोक्ताओं के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होती. अधिकांश मालिकों को लगता है कि उनके लिए काम करने वाले श्रमिक उनकी संपत्ति हैं और उन्हें प्रताड़ित करना उनका हक़ है. श्रमिकों के मूल देशों की सरकारें भी ऐसे मामलों में कार्रवाई के लिए जोर नहीं डालतीं, क्योंकि उन्हें इंसानों से ज़्यादा प्रेम डॉलरों से है. स्थानीय अधिकारियों को नाराज़ करने से डॉलरों का प्रवाह रुकने का ख़तरा पैदा हो सकता है. यदि पश्चिमी देशों में एशियाई कामगारों के साथ इस तरह का व्यवहार होता तो मीडिया और मानवाधिकार संस्थाएं अब तक इसके ख़िलाफ़ खड़ी हो चुकी होतीं, लेकिन वहां ऐसी हालत नहीं है. पश्चिमी देशों में नौकरी करने वाले कामगारों को कुछ सालों में वहां की नागरिकता मिल जाती है. उनके बच्चे और परिवारों को स्थानीय क़ानून के मुताबिक़ शिक्षा और चिकित्सा सुविधाएं आसानी से उपलब्ध होती हैं. उन्हें क़ानून की ओर से भी सुरक्षा मिलती है.

लेकिन मध्य-पूर्व के देशों में कमज़ोर और मजबूर लोगों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों होता है? स्पष्ट है कि इन देशों में ग़ैर अरबी मूल के लोगों को नीची निगाह से देखा जाता है. पश्चिमी देशों के नागरिकों को जहां विशेष इज़्ज़त दी जाती है, वहीं ग़ैर अरबी मूल के अन्य देशों के नागरिक नस्लीय दुर्भावना के शिकार होते हैं. वह भी तब, जबकि इस्लाम इस तरह के किसी भी भेदभाव की इजाज़त नहीं देता. अरबी समाज के इस दोहरे आचरण के बारे में सभी जानते हैं, लेकिन कोई इसके ख़िलाफ़ कुछ नहीं बोलता. नस्लीय भेदभाव की जड़ें इस्लाम के शुरुआती दिनों में छुपी हैं. पाकिस्तानी मूल के कनाडाई लेखक तारेक फतह ने अपनी प्रसिद्ध किताब-चेजिंग ए मिराज में जमाते इस्लामी के संस्थापक मौलाना मौदूदी को उद्धृत करते हुए लिखा है कि उमाय्यद सरकार शुरू से ही अरबी रंग में रंगी हुई थी और गैर अरब मूल के लोगों के साथ समानता भरे व्यवहार के पक्ष में नहीं थी. इस्लाम के सिद्धांतों के विपरीत अरब शासकों ने ग़ैर अरबों पर जज़िया लगा दिया, ग़ैर अरबी मूल के लोगों को लगता था कि वे स्थानीय लोगों के गुलाम हैं. फतह ने इसी किताब में डेनवर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लियाकत तकीम को उद्धृत करते हुए लिखा है कि उमाय्यदों के शासनकाल में अरब मुसलमानों को सामाजिक ढांचे में शीर्ष स्थान हासिल था, जबकि ग़ैर अरबी मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक बना दिया गया था. कुरान की इजाज़त न होने के बावजूद पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद अरबी पहचान की भावना जोर पकड़ती गई. इस्लाम अपनाने वाले ग़ैर अरबी लोग, चाहे उनकी सामाजिक हैसियत कैसी भी हो, के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता था. यदि ग़ैर अरबी मूल के मुसलमानों को इस नज़रिए से देखा जाता था तो अन्य धर्मावलंबियों के प्रति उनकी भावनाएं कैसी होंगी, इसका आसानी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है.

समय के साथ नस्लीय भेदभाव की यह भावना और बलवती होती गई. खनिज, खासकर तेल संसाधनों के चलते बिना मेहनत के कमाए पैसों से बढ़ी आर्थिक समृद्धि के कारण मध्य-पूर्व देशों के मूल निवासियों को लगता है कि वे दूसरों से श्रेष्ठ हैं और कमज़ोर लोगों के साथ दुर्व्यवहार करना उनका हक है. अपने देश के निवासियों को मध्य-पूर्व के देशों में जाने की अनुमति देने वाली सरकारें जब तक इसके ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाएंगी, गुलामी का यह आधुनिक स्वरूप बेरोकटोक चलता रहेगा.

इरफ़ान हुसैन
feedback@chauthiduniya.com

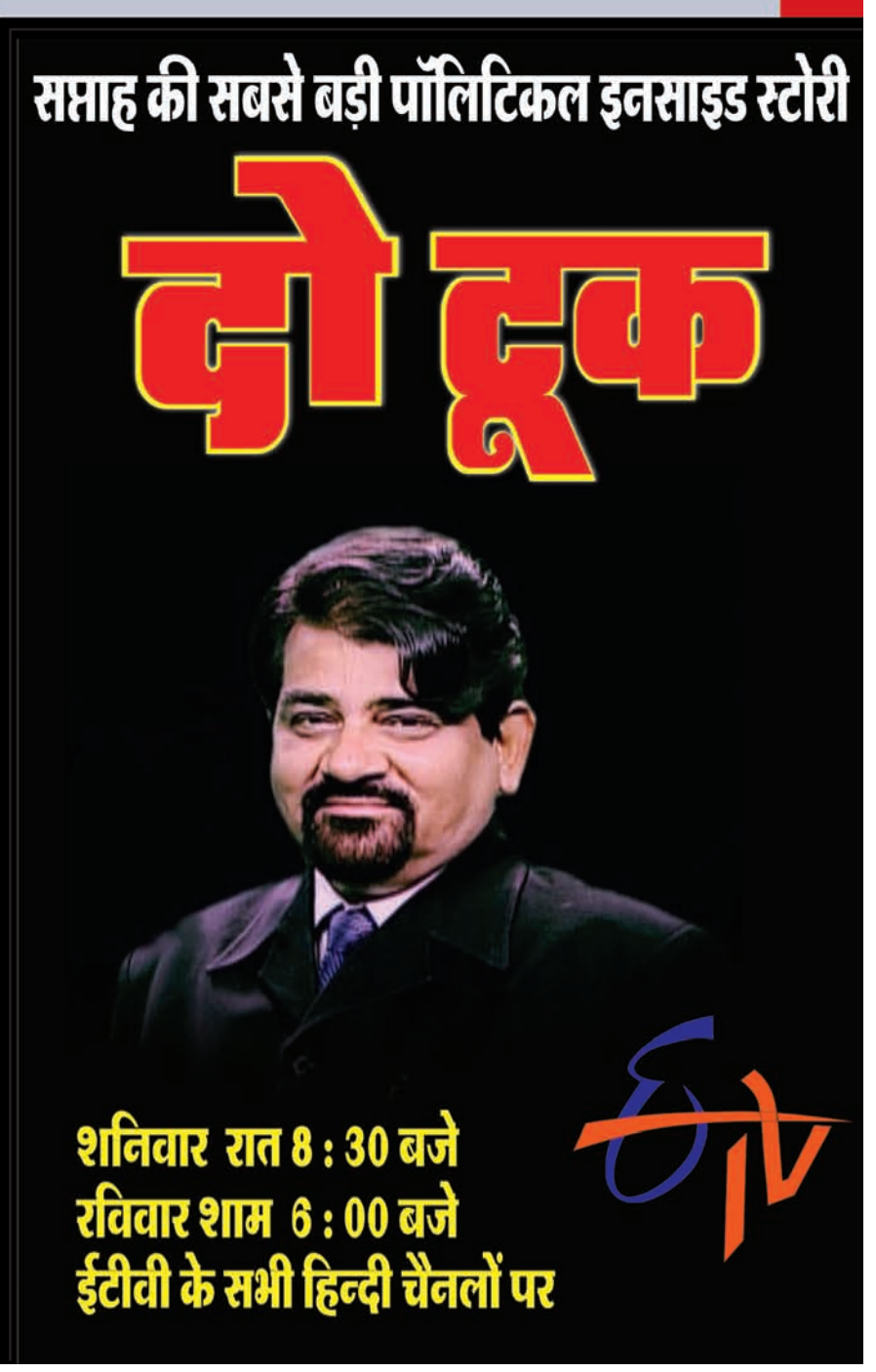

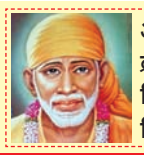

अभी तक शांत मुद्रा में बैठे बाबा तत्क्षण क्रोधित हो उठे और उन्हें अपशब्द कहने लगे, स्त्रियों, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम किसके बाप का माल समझ कर ले जा रही हो?

साई बाबा और ब्राह्मण भोज

बीव्ही देव डहाणू ठाणे में मामलतदार थे. उनकी माता ने लगभग पच्चीस-तीस व्रत किए थे, इसलिए अब उनका उद्यापन करना आवश्यक था. उद्यापन के साथ-साथ सौ-दो सौ ब्राह्मणों का भोजन भी होने वाला था. देव ने एक तिथि निश्चित कर बापू साहेब जोग को एक पत्र शिरडी भेजा. उसमें उन्होंने लिखा कि तुम मेरी ओर से साई बाबा को उद्यापन और भोजन में सम्मिलित होने का निमंत्रण दे देना और उनसे प्रार्थना करना कि उनकी अनुपस्थिति में उत्सव अपूर्ण ही रहेगा. मुझे पूर्ण आशा है कि वह अवश्य पधारेंगे. बापू साहेब जोग ने बाबा को वह पत्र पढ़कर सुनाया. उन्होंने उसे ध्यानपूर्वक सुना और शुद्ध हृदय से प्रेषित निमंत्रण जानकर वह कहने लगे कि जो मेरा स्मरण करता है, उसका मुझे सदैव ही ध्यान रहता है. मुझे यात्रा के लिए कोई भी साधन गाड़ी, तांगा या विमान की आवश्यकता नहीं है. मुझे तो जो प्रेम से पुकारता है, उसके सम्मुख मैं अविलंब प्रगट हो जाता हूं. उसे एक सुखद पत्र भेज दो कि मैं दो अन्य व्यक्तियों के साथ अवश्य आऊंगा. जो कुछ बाबा ने कहा था, जोग ने देव को पत्र में लिखकर भेज दिया. पत्र पढ़कर देव को बहुत प्रसन्नता हुई, परंतु उन्हें ज्ञात था कि बाबा केवल राहाता, रुई और नीमगांव के अतिरिक्त और कहीं भी नहीं जाते हैं. फिर उन्हें विचार आया कि उनके लिए क्या असंभव है. उनकी जीवनी अपार चमत्कारों से भरी हुई है. वह तो सर्वव्यापी हैं. वह किसी भी वेश में अनायास ही प्रगट होकर अपना वचन पूर्ण कर सकते हैं.

उद्यापन से कुछ दिनों पूर्व एक संन्यासी डहाणू स्टेशन पर उतरा, जो बंगाली संन्यासियों के समान वेशभूषा धारण किए था. दूर से देखने में ऐसा प्रतीत होता था कि वह गौरक्षा संस्था का स्वयंसेवक है. वह सीधा स्टेशन मास्टर के पास गया और उनसे चंदे के लिए निवेदन करने लगा. स्टेशन मास्टर ने उसे सलाह दी कि तुम यहां के मामलतदार के पास जाओ, उनकी सहायता से ही तुम यथेष्ठ चंदा प्राप्त कर सकोगे. ठीक उसी समय मामलतदार भी वहां पहुंच गए. स्टेशन मास्टर ने संन्यासी का परिचय उनसे कराया और वे दोनों स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर बैठे वार्तालाप करते रहे. मामलतदार ने बताया कि यहां के प्रमुख नागरिक राव साहेब नरोत्तम सेठी ने धर्मार्थ कार्य के निमित्त चंदा एकत्र करने की एक नामावली बनाई है. अत: अब एक और दूसरी नामावली बनाना उचित सा प्रतीत नहीं होता. इसलिए श्रेयस्कर तो यही होगा कि आप दो-चार माह के पश्चात पुन: यहां दर्शन दें. यह सुनकर संन्यासी वहां से चला गया और एक माह पश्चात देव के घर के सामने तांगे से उतरा. तब उसे देखकर देव ने मन ही मन सोचा कि वह चंदा मांगने ही आया है. उसने देव को कार्य में व्यस्त देखकर उनसे कहा, मैं चंदे के निमित्त नहीं, बल्कि भोजन करने के लिए आया हूं. देव ने कहा, बहुत आनंद की बात है, आपका सहर्ष स्वागत है. संन्यासी ने कहा, मेरे साथ दो बालक और हैं. भोजन में अभी दो घंटे का विलंब था. इसलिए देव ने पूछा, यदि आज्ञा हो तो मैं किसी को उन्हें बुलाने के लिए भेज दूं. संन्यासी ने कहा, आप चिंता न करें, मैं निश्चित समय पर उपस्थित हो जाऊंगा. देव ने उनसे दोपहर में पधारने की प्रार्थना की. ठीक 12 बजे दोपहर को तीन मूर्तियां वहां पहुंचीं और भोज में सम्मिलित होकर भोजन करके वहां से चली गईं. उत्सव समाप्त होने पर देव ने बापू साहेब जोग को पत्र में उलाहना देते हुए बाबा पर वचन भंग करने का आरोप लगाया. जोग वह पत्र लेकर बाबा के पास गए, परंतु पत्र पढ़ने के पूर्व ही बाबा उनसे कहने लगे, मैंने वहां जाने का वचन दिया था तो उसे धोखा नहीं दिया. उसे सूचित करो कि मैं अन्य दो व्यक्तियों के साथ भोजन में उपस्थित था, परंतु जब वह मुझे पहचान ही न सका, तब निमंत्रण देने का कष्ट ही क्यों उठाया था. उसे लिखो कि उसने सोचा होगा कि वह संन्यासी चंदा मांगने आया है. परंतु क्या मैंने उसका संदेह दूर नहीं कर दिया था कि दो अन्य व्यक्तियों के साथ मैं भोजन के लिए आऊंगा और क्या वे त्रिमूर्तियां ठीक समय पर भोजन में सम्मिलित नहीं हुईं? देखो, मैं अपना वचन पूर्ण करने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दूंगा, मेरे शब्द कभी असत्य न निकलेंगे. इस उत्तर से जोग के हृदय में बहुत प्रसन्नता हुई और उन्होंने पूर्ण उत्तर लिखकर देव को भेज दिया. जब देव ने उत्तर पढ़ा तो उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे. उन्हें अपने आप पर बड़ा क्रोध आ रहा था कि मैंने व्यर्थ ही बाबा पर दोषारोपण किया. वह आश्चर्यचकित हो गए कि किस तरह मैंने संन्यासी की पूर्व यात्रा से धोखा खाया, जो चंदा मांगने आया था और मैं संन्यासी के शब्दों का अर्थ भी न समझ पाया कि अन्य दो व्यक्तियों के साथ भोजन को आऊंगा.

इस कथा से विदित होता है कि जब भक्त अनन्य भाव से सद्गुरु की शरण में आता है, तभी उसे अनुभव होने लगता है कि उसके सभी धार्मिक कृत्य उत्तम प्रकार से चलते और निर्विघ्न संपन्न होते रहते हैं.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

परंतु क्या मैंने उसका संदेह दूर नहीं कर दिया था कि दो अन्य व्यक्तियों के साथ मैं भोजन के लिए आऊंगा और क्या वे त्रिमूर्तियां ठीक समय पर भोजन में सम्मिलित नहीं हुईं? देखो, मैं अपना वचन पूर्ण करने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दूंगा, मेरे शब्द कभी असत्य न निकलेंगे.

आरती श्री शिरडी के साई बाबा की

आरती श्री साई गुरूवर की, परमानंद सदा सुरवर की
जाकी कृपा विपुल सुखकारी, दुख, शोक, संकट, भयहारी
शिरडी में अवतार रचाया, चमत्कार से तत्व दिखाया
कितने भक्त चरण पर आए, वे सुख शांति चिरतंन पाए
भाव धरे मन में जैसा, पावत अनुभव वो ही वैसा
गुरू की लगावे तन को, समाधान लाभत उस मन को
साई नाम सदा जा गावे, सो फल जग में शाश्वत पावे
गुरूबारसर करि पूजा सेवा, उस पर कृपा करत गुरुदेवा
राम, कृष्ण, हनुमान रूप में, दे दर्शन जानत जो मन में
विविध धर्म के सेवक आते, दर्शन से इच्छित फल पाते
जय बोलो साई बाबा की, जय बोलो अवधूत गुरू की
साईदास आरती को गावे, घर में बसि सुख मंगल पावे.

श्री सद्गुरु साई बाबा के ग्यारह वचन

1. जो शिरडी आएगा, आपद दूर भगाएगा.
2. चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर.
3. त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा.
4. मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस.
5. मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो, सत्य पहचानो.
6. मेरी शरण आ खाली जाए, हो कोई तो मुझे बताए.
7. जैसा भाव रहा जिस मन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का.
8. भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा.
9. आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर.
10. मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया.
11. धन्य धन्य व भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य.

आटा और हैज़ा

अभी तक शांत मुद्रा में बैठे बाबा तत्क्षण क्रोधित हो उठे और उन्हें अपशब्द कहने लगे, स्त्रियों, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम किसके बाप का माल समझ कर ले जा रही हो? क्या किसी क़र्ज़दार का माल है, जो इतनी आसानी से उठाकर ले जा रही हो?

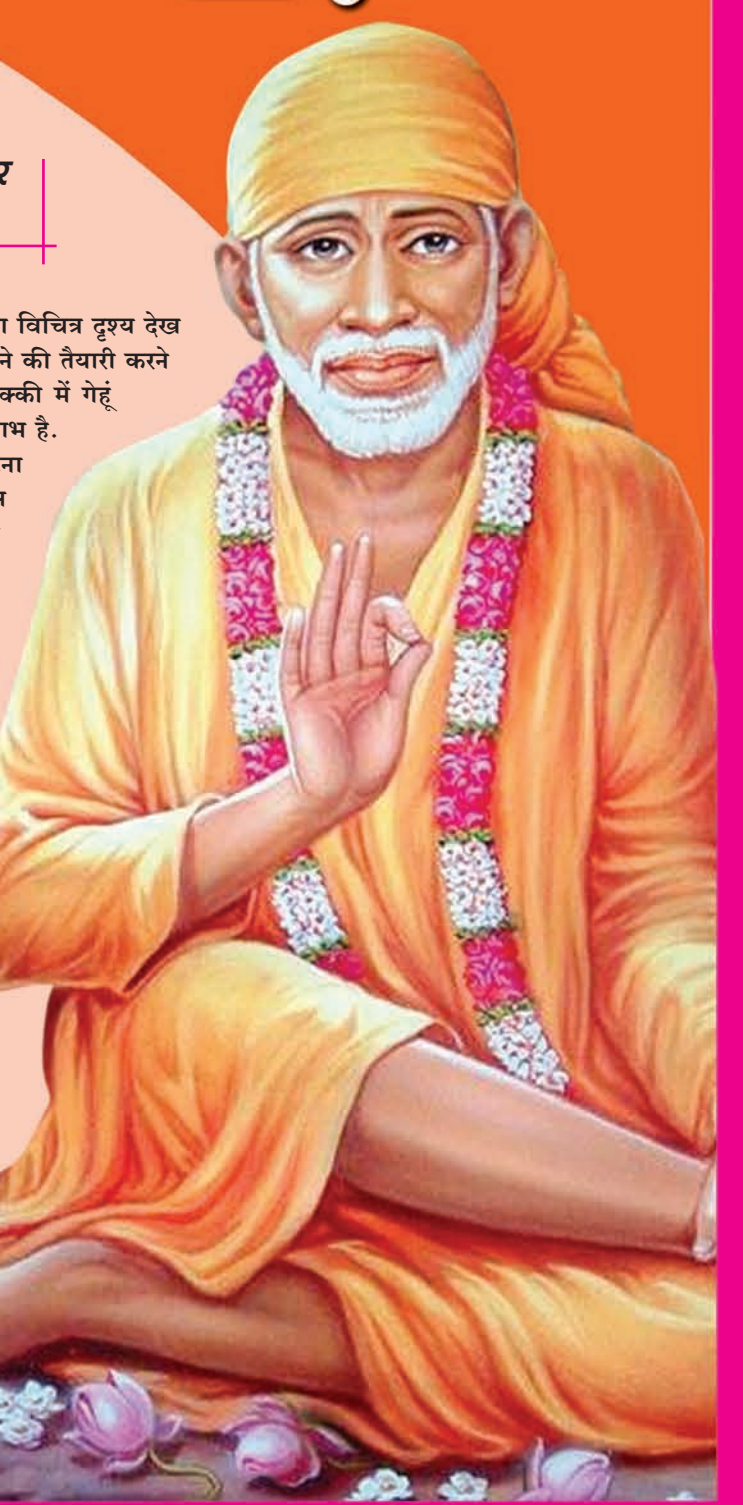

वर्ष 1910 में एक दिन प्रात:काल मैं श्री साई बाबा के दर्शनार्थ मस्जिद में गया. वहां का विचित्र दृश्य देख मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा कि साई बाबा मुंह-हाथ धोने के पश्चात चक्की पीसने की तैयारी करने लगे. उन्होंने फर्श पर एक टाट का टुकड़ा बिछाकर उस पर हाथ से पीसने वाली चक्की में गेहूं डालकर पीसना शुरू कर दिया. मैं सोचने लगा कि बाबा को चक्की पीसने से क्या लाभ है. उनके पास तो कोई है भी नहीं और अपना निर्वाह भी वह भिक्षावृत्ति द्वारा ही करते हैं. इस घटना के समय वहां उपस्थित अन्य व्यक्तियों की भी ऐसी ही धारणा थी, परंतु उनसे पूछने का साहस किसे था? बाबा के चक्की पीसने का समाचार शीघ्र ही सारे गांव में फैल गया और उनकी यह विचित्र लीला देखने हेतु तत्काल नर-नारियों की भीड़ मस्जिद की ओर दौड़ पड़ी. उनमें से चार निडर स्त्रियां भीड़ को चीरती हुई ऊपर आईं और उन्होंने बाबा को बलपूर्वक वहां से हटाकर हाथ से चक्की का खूंटा छीनकर उनकी लीलाओं का गायन करते हुए गेहूं पीसना शुरू कर दिया.

पहले तो बाबा क्रोधित हुए, परंतु फिर उनका भक्ति भाव देखकर वह शांत होकर मुस्कराने लगे. पीसते-पीसते उन स्त्रियों के मन में ऐसा विचार आया कि बाबा का न तो घर-द्वार है और न इनके कोई बाल-बच्चे और न कोई देखरेख करने वाला है. यह स्वयं भिक्षावृत्ति द्वारा निर्वाह करते हैं, अत: इन्हें भोजन आदि के लिए आटे की आवश्यकता ही क्या है. बाबा तो परम दयालु हैं. हो सकता है कि यह आटा हम सब लोगों में ही वितरित कर दें. इन्हीं विचारों में मग्न होकर गीत गाते-गाते उन्होंने सारा गेहूं पीस डाला. फिर उन्होंने चक्की हटाकर आटे को चार समान भागों में विभक्त कर लिया और अपना-अपना भाग लेकर वहां से जाने को तैयार हुईं. अभी तक शांत मुद्रा में बैठे बाबा तत्क्षण क्रोधित हो उठे और उन्हें अपशब्द कहने लगे, स्त्रियों, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम किसके बाप का माल समझ कर ले जा रही हो? क्या किसी क़र्ज़दार का माल है, जो इतनी आसानी से उठाकर ले जा रही हो? अच्छा, अब एक कार्य करो कि इस आटे को ले जाकर गांव की मेंड़ (सीमा) पर बिखेर आओ.

मैंने शिरडीवासियों से प्रश्न किया कि जो कुछ बाबा ने अभी किया है, उसका क्या तात्पर्य है. उन्होंने मुझे बताया कि गांव में विषूचिका (हैज़ा) का जोरों से प्रकोप है और उसके निवारणार्थ बाबा का यह उपचार है. अभी जो कुछ आपने पीसते देखा था, वह गेहूं नहीं, वरन विषूचिका (हैजा) था, जो पीसकर नष्ट-भ्रष्ट कर दिया गया. इस घटना के पश्चात सचमुच हैज़ा शांत हो गया और ग्रामवासी सुखी हो गए.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

पूर्वोत्तर की सामाजिक, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक पृष्ठभूमि और इतिहास के बारे में भी आम लोगों को बहुत ही कम जानकारी है. यह क्षेत्र राजनीतिक तौर पर भी उतना मज़बूत नहीं है.

सदियों का सफ़रनामा

अनंत विजय

तकरीबन चार साल पहले की बात है, एक किताब आई थी भारतीय डाक-सदियों का सफरनामा. लेखक थे अरविंद कुमार सिंह. मैं डाक भवन दिल्ली के सभागार में किताब के विमोचन समारोह में भी शामिल हुआ था. यह किताब नेशनल बुक ट्रस्ट, नई दिल्ली से प्रकाशित हुई थी और उस वक़्त ट्रस्ट की कर्ताधर्ता पुलिस अधिकारी नुजहत हसन थीं. बात आई-गई हो गई. मैंने किताब को बग़ैर देखे-सुने रख दिया था. कई बार इस किताब की चर्चा सुनी-पढ़ी, लेकिन अभी दो मजेदार घटनाएं हुईं, जिनके बाद डाकिया, उसके मनोविज्ञान और डाक विभाग को जानने की इच्छा हुई. हुआ यह कि मैं पिछले दिनों अपनी सोसाइटी में खुले डाकघर में गया और वहां मैंने काउंटर पर बैठे सज्जन से कहा कि मुझे पचास पोस्टकार्ड दे दीजिए तो पहले तो उन्होंने हैरत से मेरी ओर देखा और फिर दोहराया कि कितने पोस्टकार्ड चाहिए. मैंने फिर से उन्हें कहा कि पचास दे दीजिए. इसके बाद उन्होंने अपनी दराज खोलकर कार्ड गिनने शुरू कर दिए, लेकिन बीच-बीच में वह मेरी ओर देख रहे थे. पोस्टकार्ड मुझे सौंपने और पैसे लेने के बीच उनकी आंखों में कुछ प्रश्न तैर रहे थे, जो पैसे वापस करते समय उन्होंने मुझसे पूछ ही लिए. उन्होंने कहा कि आप इतने पोस्टकार्डों का क्या करेंगे? जब तक मैं कुछ बोलता, तब तक उन्होंने ख़ुद ही जवाब दे दिया कि शायद आप कोई मार्केटिंग कंपनी चलाते हैं और अपने ग्राहकों को किसी उत्पाद के बारे में जानकारी देना चाहते हैं और पोस्टकार्ड से सस्ता एवं सुरक्षित माध्यम कुछ और हो नहीं सकता. मैं उनके अनुमान को ग़लत साबित नहीं करना चाहता था, इस वजह से मुस्कराता हुआ डाकघर से निकल गया.

दरअसल मैं पोस्टकार्ड का इस्तेमाल छोटे पत्र लिखने में करता हूं. संचार क्रांति के इस आधुनिक दौर में मेरा अब भी मानना है कि पत्र का स्थान फोन, एसएमएस या फिर ईमेल भी नहीं ले सकते. पत्र का अपना एक महत्व होता है, जिसे पढ़ते वक़्त आप लिखने वाले की भावनाओं को महसूस कर सकते हैं. मुझे अब भी याद आता है कि जब मैं अपने गांव वलिपुर में रहा करता था तो हर दिन नियम से सुबह-सुबह डाकघर जाता था. तक़रीबन बीस साल पहले की बात है, उस वक़्त लैंडलाइन फोन ने बस मेरे घर में क़दम रखा ही था, लेकिन एसटीडी रेट इतने ज़्यादा थे कि फोन पर बात नहीं हो सकती थी. हमारे घर में फोन को लॉक करके रखा जाता था और रात ग्यारह बजने का इंतज़ार किया जाता था, क्योंकि उस वक़्त रात ग्यारह बजे के बाद एसटीडी की दरें काफी कम हो जाती थीं. उस दौर में डाक लाने वाला डाकिया मेरे लिए पूरी दुनिया से जुड़ने और उसे जानने-समझने का एकलौता माध्यम था. इस वजह से डाकिया हमारे समाज का, हमारे इलाक़े का एक अहम व्यक्ति होता था. मेरे साहित्यिक मित्र और प्रकाशक काफी पत्र-पत्रिकाएं भेजते थे, इस वजह से हर रोज मेरे तीन-चार पत्र होते ही थे. कभी-कभी डाकिया इस बात से ख़फ़ा भी होता था कि सिर्फ़ मेरे तीन पत्रों की वजह से उसे तीन-चार किलोमीटर साइकिल चलानी पड़ती है, लेकिन बाद के दिनों में मैंने उससे दोस्ती कर ली थी. इसके दो फ़ायदे हुए, एक तो मेरे पत्र सुरक्षित मिल जाते थे और दूसरे वह पुस्तकों के वीपीपी आदि भी घर तक ले आते थे.

दूसरी घटना भी डाकिया से ही जुड़ी है. मैं जब भी लंबे समय के लिए कहीं बाहर जाता हूं तो यह व्यवस्था करके जाता हूं कि मेरी डाक मेरे अस्थायी पते पर रिडायरेक्ट कर दी जाएं. इस बार यह हुआ कि मैं कहीं बाहर गया था. जब लौटकर आया तो महीने भर से कोई डाक न आने पर मेरा माथा ठनका. मैं अपने पास के डाकघर में पहुंचा और पोस्ट मास्टर से शिक़ायत की तो उन्होंने मेरे इलाक़े के डाकिया को बुलाया और पूछताछ की तो उसने बेहद मासूमियत से जवाब दिया कि इनकी डाक तो रिडायरेक्ट हो रही थी तो मैंने सोचा कि यह यहां से चले गए हैं, सो अब मैं ही इनकी डाक को उसी पते पर रिडायरेक्ट कर देता हूं. डाकिया का यह जवाब इतना मासूमियत भरा और अपनापन लिए था कि मैं कुछ कह नहीं पाया और उन्हें वस्तुस्थिति बताकर डाकघर से बाहर निकल आया. आज के इस भागमभाग के दौर में कौन इतना ध्यान रखता है कि अमुक व्यक्ति की डाक इस पते पर रिडायरेक्ट होनी है. कुरियर के बढ़ते चलन वाले इस दौर में निजी कंपनियों से आप यह अपेक्षा कर ही नहीं सकते. दोनों घटनाओं से संबंधित अलग-अलग अध्याय इस किताब में हैं, भारतीय पोस्टकार्ड और सरकारी वर्दी में सबका चहेता.

इन दोनों घटनाओं के बाद मैंने अरविंद कुमार सिंह की किताब निकाली और उसे पढ़ना शुरू किया. सदियों का सफरनामा में डाक विभाग से जुड़ी हर छोटी-बड़ी और रोचक जानकारियां मौजूद हैं. जैसे कि हम डाक बंगला का नाम हमेशा से सुनते रहे हैं, कई बार डाक बंगलों में रुकने और रहने का मौक़ा भी मिला है, लेकिन यह नहीं सोचा कि इन्हें डाक बंगला क्यों कहते हैं. अरविंद कुमार सिंह ने अपनी इस किताब में यह बताया है कि क्यों इन सरकारी गेस्ट हाउसों को डाक बंगला कहा जाता है. इसका उद्भव डाक विभाग के लिए हुआ था. सड़कों के किनारे उन्नीसवीं सदी के शुरुआती दिनों तक होटल या सराय नाम मात्र की थीं. इसी नाते डाक बंगले और विश्रामगृह बनाए गए. ये सरकारी नियंत्रण में थे और वहां पर खिदमतगार, चौकीदार और पोर्टर सेवा में उपलब्ध रहते थे. लॉर्ड डलहौजी के जमाने में कई और डाक बंगले बने. डाक बंगले पुरानी डाक चौकियों के ही उन्नत रूप थे. 1863-64 तक डाक विभाग के हाथों में ही इन डाक बंगलों का प्रबंध रहा. इसी वर्ष डाक विभाग ने डाक बंगलों से मुक्ति पा ली. अरविंद ने इस प्रणाली के बारे में प्रसिद्ध लेखक चेखव की चर्चित कहानी-ट्रैवलिंग विथ मेल के ज़रिए रूस में इस तरह की व्यवस्था का उदाहरण दिया है. इस तरह की कई रोचक जानकारियों के अलावा डाक विभाग और डाकिया के बारे में कई शोधपरक जानकारियां भी पेश की गई हैं. मसलन स्वतंत्रता संग्राम में डाक विभाग और डाकियों की भूमिका पर एक पूरा अध्याय है. 1857 की क्रांति के वक़्त उत्तर प्रदेश में आंदोलनकारियों के आठ हरकारों को गिरफ़्तार कर फांसी पर चढ़ा दिया गया था. इस तरह की कई घटनाएं इस किताब में दर्ज हैं, जो अब तक या तो अछूती रही हैं या फिर बेहतर तरीक़े से रेखांकित नहीं हो पाईं. इस किताब में एक ऐसे महकमे का भी उल्लेख है, जो हर साल तक़रीबन ढाई करोड़ ऐसे पत्रों को गंतव्य तक पहुंचाता है, जिन पर या तो पता लिखा ही नहीं होता है या फिर ऐसा पता लिखा होता है, जिसे इलाक़े के चप्पे-चप्पे से वाक़िफ़ डाकिया भी नहीं ढूंढ पाता. इस विभाग को रिटर्न लेटर ऑफिस कहा जाता है. इसके अलावा डाक विभाग की उन ऐतिहासिक इमारतों के चित्र और रोचक विवरण भी इस किताब में हैं, जिन्हें हम देखते तो हैं, पर इस बात का एहसास तक नहीं होता है कि वे कितनी अहम इमारतें हैं.

अरविंद कुमार सिंह ने बेहद श्रमपूर्वक शोध के बाद यह पुस्तक लिखी है. इसके पहले डाक विभाग पर कुछ छिटपुट किताबें आई हैं. मुल्कराज आनंद ने अंग्रेजी में एक किताब लिखी थी-स्टोरी ऑफ द इंडियन पोस्ट ऑफिस. लेकिन, अरविंद सिंह की किताब मुल्कराज आनंद की किताब से बहुत आगे जाती है. इस वजह से अरविंद की किताब को प्रसिद्ध लेखिका महाश्वेता देवी मूल्यवान मानती हैं. मुझे तो यह किताब इस लिहाज़ से अहम लगी कि यह एक ऐसे महकमे के इतिहास का दस्तावेजीकरण है, जो दशकों से हमारे जीवन और समाज का न केवल अंग रहा है, बल्कि हमें गहरे तक प्रभावित भी करता रहा है. नेशनल बुक ट्रस्ट ने इस किताब को हिंदी के अलावा अंग्रेजी, उर्दू एवं असमिया में भी प्रकाशित करके बड़ा काम किया है. अभी-अभी अरविंद कुमार सिंह की नई किताब-डाक टिकटों पर भारत दर्शन भी नेशनल बुक ट्रस्ट ने छापी है. यह भी अपनी तरह की एक अनूठी और कह सकते हैं कि हिंदी में पहली किताब है. यह बात संतोष देती है कि हिंदी में भी इन विषयों पर काम शुरू हो गया है.

(लेखक आईबीएन-7 से जुड़े हैं)
anant.ibn@gmail.com

पुस्तक अंश मुन्नी मोबाइल

गतांक से आगे

प्रदीप सौरभ

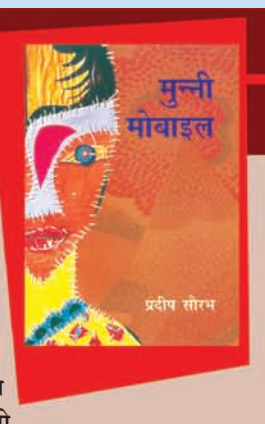

आनंद भारती अपने होटल से दाल-रोटी की खोज में निकल गए. एक स्टोर में उन्होंने एक बियर ली. स्टोर मालिक की शक्ल भारतीय लग रही थी. उन्होंने उससे पूछा, भारत में कहां रहते हैं?

मैं पाकिस्तानी हूं, उसने बड़ी तहजीब से जवाब दिया.

आसपास इंडियन खाना मिल जाएगा? आनंद भारती ने उससे फिर पूछा. उसने अपनी घड़ी को देखते हुए कहा, वेस्ट मिनिस्टर के पीछे एक इंडियन रेस्त्रां है. जल्दी चले जाएं, शायद खाना आपको मिल जाए.आनंद भारती स्टोर से निकल तेज क़दमों से उसके बताए रास्ते पर चल पड़े. थोड़ी देर बाद उन्हें एक ग्लो साइन बोर्ड चमकता हुआ दिखाई दिया. उसमें लिखा था, इंडियन फूड. वह बोर्ड को देख ख़ुश हुए. उन्हें लगा कि आज उन्हें मनपसंद भोजन मिल जाएगा.

रेस्त्रां काफी छोटा था. करीने से एक कोने में बार काउंटर था. काउंटर पर बैठकर पीने की जगह नहीं थी. नज़दीक-नज़दीक दस-बारह चेयर-टेबिल लगे हुए थे. कुछ अंग्रेज भारतीय भोजन का मज़ा ले रहे थे. आनंद भारती एक टेबिल पर जा बैठे. एक कम उम्र का लड़का मैन्यू उनके सामने रख गया. मैन्यू में अरहर की दाल, स्टीम राइस, रोटी से लेकर शाही पनीर तक मौजूद था. बटर चिकन और रोगन जोश भी शामिल था. मैन्यू पढ़ने के बाद आनंद भारती ने एक ग्लास बियर का आर्डर दिया. खाने का आर्डर लेने आने पर उन्होंने वेटर से पूछा, तुम भारतीय हो?

नहीं, वेटर ने तुरंत जवाब दिया.

आनंद भारती को स्टोर की तरह यहां भी झटका लगा. उन्होंने फिर पूछा, तो कहां के हो?

बांग्लादेश, वेटर ने बेतकल्लुफी के साथ जवाब दिया.

तुम्हारे मालिक? आनंद कुछ और जानना चाह रहे थे.

बांग्लादेश. वेटर उसी मुस्तैदी से बोला. भारती ने खाने का आर्डर दिया. बियर की चुस्की के दौरान वह सोचते रहे कि इंडियन फूड रेस्त्रां का मालिक बांग्लादेशी. वह इस बात के लिए भी हैरान थे कि भारतीय खाने की खोज में एक पाकिस्तानी ने मदद की और खाना खिलाया बांग्लादेशी ने. भारतीय महाद्वीप के बेशक भौगोलिक टुकड़े हो गए हों, लेकिन अंतरात्मा अब भी एक है. शासक बेशक आपस में भिड़ते रहें, लेकिन अवाम अंदर ही अंदर एकजुट है. यही सब सोचते हुए वह खाना ख़त्म कर होटल की ओर चल पड़े.

...अब ब्रिस्टल की बारी थी. वाइल्ड स्क्रीन की सिल्वर जुबली के आयोजन में भारतीय टीम को भाग लेने जाना था. ब्रिस्टल जाने से पहले देर रात आनंद भारती के मोबाइल की घंटी बजी. स्क्रीन का नंबर चमक रहा था. मुन्नी के फोन से वह हैरान हुए. वह उसे सख्त हिदायत देकर आए थे कि बिना किसी खास बात के मिसकाल न करे. अट्ठारह रुपये प्रति मिनट लगते थे. घंटी बजनी जो शुरू हुई तो रुकने का नाम ही न ले. एक बार पूरी घंटी बजकर बंद हो गई. आनंद भारती ने फोन नहीं उठाया. दोबारा फिर घंटी बजी. उन्हें लगा कि कोई खास बात है, जो मुन्नी उन्हें फोन पर फोन किए जा रही है. उन्हें लगा कि कहीं सोसायटी में वह किसी से भिड़ तो नहीं गई या फिर घर में चोरी-वोरी न हो गई हो. आनंद भारती ने फोन उठा लिया. मोबाइल पर फफक कर रोने की आवाज़ आई. मुन्नी कुछ बोल नहीं रही थी. आनंद भारती ने पूछा, क्यों रो रही हो?

प्रीति, उधर से मुन्नी की भर्राई आवाज़ आई.

क्या हो गया प्रीति को? आनंद भारती कुछ परेशान स्वर में बोले.

साहब, रात को सोई तो सुबह उठी नहीं. सोने से पहले उसने दर्द की शिक़ायत की थी. स्टोर से लाकर दवा दे दी थी.

आनंद भारती असमंजस में थे. उन्होंने पूछा, दवा रखी है?

नहीं साहब, गोलू ने फेंक दी, मुन्नी ने रोते हुए कहा.

संवाद आगे नहीं बढ़ रहा था. आनंद भारती ने यह कहते हुए फोन काट दिया कि लौट के आऊंगा तो बात करूंगा. वह सोचने लगे कि ज़रूर दवा रिएक्शन कर गई होगी. गांव में दवा की दुकानों में नकली दवा मिलना आम है. अब तो सरकारी अस्पतालों में भी नकली दवा मिलती है. लोगों की नासमझी और दवा बेचने वालों की हवस के चलते न जाने कितने बेकसूर मर जाते हैं.

मणिपुर की दर्दभरी कहानी

एस. बिजेन सिंह

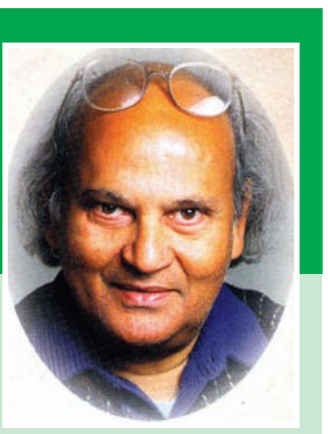

अगर आप पूर्वोत्तर भारत को क़रीब से जानना-समझना चाहते हैं तो डॉ. लाल बहादुर वर्मा द्वारा लिखित उपन्यास *उत्तर पूर्व* आपके लिए एक बेहतर मददगार साबित हो सकता है. यह डॉ. वर्मा की वह जीवंत कृति है, जिसमें मणिपुर का इतिहास, संस्कृति, समाज एवं राजनीति सब कुछ है. उत्तर पूर्व का मुख्य आधार ही मणिपुर है. मणिपुर यूनिवर्सिटी के इर्द-गिर्द बुने इस उपन्यास की शुरुआत में थांगजम मनोरमा को समर्पित एक कविता भी है. जुलाई, 2004 में बलात्कार के बाद मनोरमा की हत्या कर दी गई थी और इसका आरोप भारतीय सेना के जवानों पर लगा था. इस घटना के विरोध में मणिपुर की महिलाओं ने असम रायफल्स के मुख्य फाटक पर निर्वस्त्र होकर प्रदर्शन किया था. उपन्यास के पहले पन्ने पर प्रकाशित कविता उन प्रदर्शनकारी महिलाओं का उत्साह बढ़ाती है.

मुझे याद है अगस्त, 2010 में प्रगति मैदान (दिल्ली) में लगा 15वां पुस्तक मेला. मेले का विषय था-पूर्वोत्तर भारत का साहित्य, लेकिन वहां के बारे में कोई भी खास किताब देखने को नहीं मिली. मणिपुर की तो कोई किताब ही नहीं आई. कोई लेखक उधर के मामलों पर अपना क़ीमती वक़्त बर्बाद नहीं करना चाहता. ऐसे में डॉ. वर्मा ने जो काम किया है, वह सराहनीय है. उन्होंने अपने मणिपुर प्रवास की यादों को संजोकर उन्हें उपन्यास की शक्ल दे दी और नाम दिया-उत्तर पूर्व.

मणिपुर धनुर्धर अर्जुन की ससुराल है. मणिपुर धनुर्धर अर्जुन की ससुराल है. यही नहीं, यहीं पर मोइरांग नामक वह स्थान भी है, जहां आज़ाद हिंद फौज की भारत विजय योजना साकार हुई थी.

यह उपन्यास केंद्र की उपेक्षा का दंश झेल रहे पूर्वोत्तर भारत की चिंता पर रोशनी डालता है. मणिपुर में सेना का राज है. वहां आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लागू है. इस एक्ट की आड़ लेकर किसी को पकड़ना, गोली मार देना और महिलाओं के साथ दुष्कर्म सेना के लिए आम बात है. उपन्यास के कुछ पात्र इस एक्ट के शिकार होते हैं. कई परिवारों को इस एक्ट का शिकार होना पड़ता है. उपन्यास बताता है कि शांतिपूर्ण ज़िंदगी जी रहे इराबो को इस एक्ट ने किस तरह प्रभावित किया. बाहर के लोगों, खासकर हिंदीभाषियों को मणिपुर में उपेक्षा की नज़र से देखा और ***मयांग*** कहकर संबोधित किया जाता है. बर्मा (उपन्यास का एक पात्र) वहां की संस्कृति में कैसे शामिल होकर धीरे-धीरे घुल-मिल जाता है, यह उपन्यास का अहम हिस्सा है. पूर्वोत्तर के बारे में देश के बाक़ी हिस्से के लोग ज़्यादा नहीं जानते और न ही जानने में दिलचस्पी रखते हैं. चाहे मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल हो या फिर मिजोरम. उत्तर भारतीय तो वहां के लोगों को चाइनीज या नेपाली समझ बैठते हैं.

पूर्वोत्तर की सामाजिक, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक पृष्ठभूमि और इतिहास के बारे में भी आम लोगों को बहुत ही कम जानकारी है. यह क्षेत्र राजनीतिक तौर पर भी उतना मज़बूत नहीं है. इन सारी परिस्थितियों को डॉ. वर्मा ने अपने उपन्यास में विभिन्न पात्रों के माध्यम से बहुत सहज ढंग से पेश किया है. इबोहल, बर्मा, इराबो, तनु, आरके, जुही एवं राधा इस उपन्यास के ऐसे पात्र हैं, जिन्होंने वहां की ज़िंदगी को गहराई से जिया और भोगा है. इन पात्रों का चिंतन-मनन उपन्यास के हर पन्ने पर मिलता है. डॉ. वर्मा ने वहां के जीवन, समस्याओं और परंपराओं को बहुत गहराई तक महसूस किया और फिर उसे उपन्यास की शक्ल में सबके सामने पेश किया है. यह हाशिए पर धकेले जा रहे एक राज्य के बारे में सटीक चिंतन है. यही नहीं, लेखक ने इस उपन्यास में पूर्वोत्तर के इतिहास से जुड़ी कई अहम जानकारियां पेश की हैं.

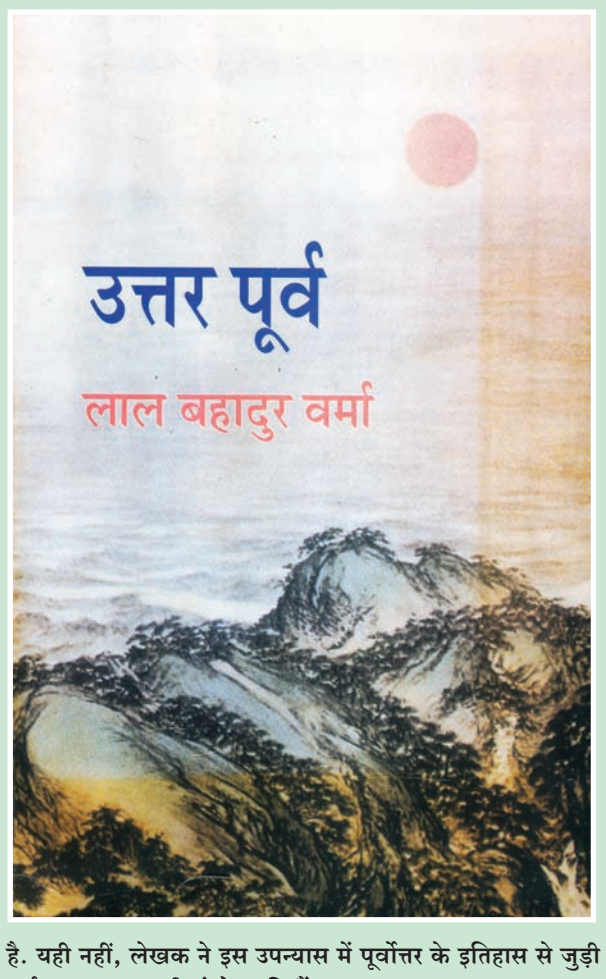

उपन्यास *उत्तर पूर्व* को पढ़ना केवल उत्तर पूर्व को जानना नहीं है, बल्कि वहां से जुड़ी हर चीज को जानना-समझना भी है. लेखक ने भूमिका में लिखा है, *मैंने बहुत से अच्छे-बुरे काम किए हैं पैंसठ वर्षों के दौरान, पर मैं किसी में इतना उजागर नहीं हुआ, किसी ने मुझे इतना नहीं रचा और सजाया-संवारा, जितना उत्तर पूर्व ने.* पंडित जवाहर लाल नेहरू ने मणिपुर को ***लैंड ऑफ ज्वैल*** कहा था. इस बात को लेखक ने बहुत गहराई से समझा और इसका विश्लेषण भी किया. उपन्यास का प्रत्येक परिच्छेद सुंदर काव्य पंक्तियों से शुरू होता है. मैतै, मणिपुरी और भारतीय होने की त्रिविधा से जूझ रहे मणिपुरियों की मानसिक लड़ाई को लेखक ने जाना. थोपी गई भारतीयता को वहां के लोग कैसे नकारते हैं और झेलते हैं, यह लेखक ने काफी सूझबूझ से बताया है. 336 पृष्ठों के इस उपन्यास में लेखक की सोच और विचारधारा साफ-साफ झलकती है. मैं मूल रूप से पूर्वोत्तर का हूं. उपन्यास पढ़ने के बाद सोचता हूं कि मैंने इसे पहले क्यों नहीं पढ़ा. वहां का नागरिक होने के बावजूद वहां की चीजों के बारे में मुझे इतनी अच्छी समझ नहीं है. उत्तर पूर्व पढ़ने के बाद लगा कि खोजने-समझने के लिए अभी बहुत कुछ बाक़ी है. दरअसल, पूर्वोत्तर के बारे में बहुत कम किताबें देखने-पढ़ने को मिलती हैं. खासकर हिंदी में तो और भी कम. मुझे याद है अगस्त, 2010 में प्रगति मैदान (दिल्ली) में लगा *15वां पुस्तक मेला*. मेले का विषय था-***पूर्वोत्तर भारत का साहित्य***, लेकिन वहां के बारे में कोई भी खास किताब देखने को नहीं मिली. मणिपुर की तो कोई किताब ही नहीं आई. कोई लेखक उधर के मामलों पर अपना क़ीमती वक़्त बर्बाद नहीं करना चाहता. ऐसे में डॉ. वर्मा ने जो काम किया है, वह सराहनीय है. उन्होंने अपने मणिपुर प्रवास की यादों को संजोकर उन्हें उपन्यास की शक्ल दे दी और नाम दिया-उत्तर पूर्व.

bijen@chauthiduniya.com

टेककॉम के ये फोन मल्टीमीडिया फोन हैं, जिनमें आजकल की आधुनिक जीवनशैली को मैच करने वाले लगभग सभी फीचर्स मौजूद हैं.

फैशन का टशन

ड्रेस चाहे एथनिक हो या वेस्टर्न, सोबर हो या मॉडर्न, यह जंक ज्वेलरी हर ड्रेस पर ख़ूब जंचती है. ट्रेंडी बॉबल्स के एक्सेसरीज युवाओं की जेब पर बिल्कुल फिट बैठती है. इस ब्रांड में बोल्ड और मॉडर्न पैटर्न के साथ अलग-अलग शेप भी उपलब्ध हैं.

आजकल की फैशनेबल कुड़ियों को स्टाइलिश और फंकी चीजें ही लुभाती हैं, चाहे उनकी ड्रेस हो या ड्रेस के साथ पहने जाने वाले एक्सेसरीज. लड़कियों को भारी-भरकम ज्वेलरी के बजाय हल्के-फुल्के स्टड्स और एक्सेसरीज ही पसंद आते हैं, लेकिन फैशन के साथ क़दम-ताल मिलाकर चलने वाली युवतियों के लिए इन एक्सेसरीज का ट्रेंडी होना ज़रूरी है और अगर इनके दाम कम हों तो क्या कहने. आधुनिक युवतियों को लुभाने के लिए ट्रेंडी बॉबल्स की ज्वेलरी इन दिनों बतौर एक्सेसरी ख़ूब चल रही है. ड्रेस चाहे एथनिक हो या वेस्टर्न, सोबर हो या मॉडर्न, यह जंक ज्वेलरी हर ड्रेस पर ख़ूब जंचती है. ट्रेंडी बॉबल्स के एक्सेसरीज युवाओं की जेब पर बिल्कुल फिट बैठती है. इस ब्रांड में बोल्ड और मॉडर्न पैटर्न के साथ अलग-अलग शेप भी उपलब्ध हैं. विभिन्न रंगों में उपलब्ध अलग-अलग टेक्सचर और मटेरियल में बने ब्रेसलेट, नेकलेस, इयररिंग और पेंडेंट खास स्टाइल स्टेटमेंट बनाते हैं. मॉडर्न लड़की के लिए हर रूप जैसे हिपस्टर, टॉम ब्वॉय, अपटाउन गर्ल, डिवा या चिक कुड़ियों के लिए ट्रेंडी बॉबल्स के एक्सेसरीज बेस्ट सूटेड हैं.

इन दिनों जब मिक्स एंड मैच के फैशन का जादू चल रहा हैं तो इसी ट्रेंड पर मिक्स एंड मैच एक्सेसरीज भी उपलब्ध हैं. ट्रेंडी बॉबल्स की परफेक्ट चिक ज्वेलरी आपकी पर्सनालिटी में और भी निखार ला देती है. इसे बदलते फैशन ट्रेंड को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है. इसे पहन कर आप अपने आप को टफ लुक दे सकेंगी और अपनी हिप-हॉप इमेज भी बरक़रार रख सकेंगी. आमतौर पर देखा जाता है कि ज़्यादा उम्र की महिलाओं के लिए इस तरह की फंकी ज्वेलरी बाज़ार में उपलब्ध नहीं होती, लेकिन ट्रेंडी बॉबल्स न सिर्फ़ युवा लड़कियों के लिए है, बल्कि इन्हें आधुनिक विचारों वाली उम्रदराज औरतों को भी ध्यान में रखकर बनाया गया है. इन एक्सेसरीज की क़ीमत 69 रुपये से लेकर 200 रुपये तक है.

वीडियोकॉन का ट्रेंडी स्पोर्ट फोन

वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज ने भारत में सबसे पहला डुकाटी ब्रांड लाइसेंस मोबाइल फोन पेश किया है. इसके साथ वीडियोकॉन ने मो-बाइकिंग की एक अद्भुत अवधारणा प्रस्तुत की है. मो-बाइकिंग रोमांच की भावना है, यह एक उभरती हुई जीवनशैली है, जहां एडवेंचर गेम्स को आराम का नया तरीक़ा माना जाता है. कंपनी ने डुकाटी सीरीज का स्पोर्ट फोन वी-6200 लांच किया है. इस अवसर पर वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज के निदेशक सौरभ धूत, मोबाइल फोन एंड डी-2एच के सीईओ अनिल खेड़ा, डुकाटी मोटर्स इंडिया के सीईओ आशीष चोरडिया एवं अभिनेत्री श्रुति हसन मौजूद थे. सौरभ धूत ने कहा कि जिस तरह बाज़ार ने वीडियोकॉन को स्वीकार किया है, उसी से ख़ुश होकर कंपनी ने यह फोन लांच किया है. अनिल खेड़ा ने कहा कि वी-6200 युवा उमंग और एडवेंचर स्पोर्ट्स की नई उभरती जीवनशैली का प्रतिनिधित्व करेगा. यह मोबाइल फोन उद्योग में वांछित नयापन पैदा करेगा. इसमें ऐसी विशेषताएं एवं फीचर्स हैं, जिन्हें पहले कभी नहीं देखा गया. इसका ब्रांड लाइसेंस डुकाटी के साथ जुड़ा हुआ है.

वी-6200 देश में अपनी तरह का एकमात्र फोन है. इसे सभी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया है और यह एक संपूर्ण मो-बाइक अनुभव प्रदान करता है. इसमें दिशा का पता लगाने के लिए ई-कंपास, तापमान मापने के लिए थर्मामीटर, वायु का दाब मापने के लिए बैरोमीटर, ऊंचाई का पता लगाने के लिए एल्टीमीटर, क़दमों की संख्या गिनने के लिए स्पीडोमीटर, जीपीएस सिस्टम और यह पता लगाने के लिए कि कहीं आप ख़तरनाक पराबैंगनी किरणों का सामना तो नहीं कर रहे हैं, यूवी सेंसर दिया गया है. इसका मॉडल एंटी स्लिप ग्रिप यानी खुरदरे स्टाइल में डिज़ाइन किया गया है. इसमें 2 मेगा पिक्सल कैमरा, डुअल एलईडी टार्च, 6 एमएमटीएफटी स्क्रीन, मैप इंडिया से आजीवन वैधता वाला जीपीएस नेविगेशन सिस्टम, 4 जीबी कार्ड, नार्मल एवं स्पोर्ट्स 2 हेडसेट्स और कस्टमाइज्ड एलईडी पल्स इंडिकेटर्स जैसी ख़ूबियां शामिल हैं. इसके साथ ही इसमें मोबाइल ट्रैकर, एफएम, एफएस रिकॉर्डर, सूर्योदय-सूर्यास्त मीटर आदि सुविधाएं भी हैं. दिलचस्प बात यह है कि इस फोन को तीन मोड यानी फोन, फन एवं स्पोर्ट्स मोड पर चलाया जा सकता है.

बच्चों के लिए नया कॉमिक्स

भारतीय बच्चों को अंतरराष्ट्रीय कॉमिक साहित्य से रूबरू कराने के लिए कई कॉमिक सीरीजों का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद किया जा रहा है. बच्चों का पसंदीदा कार्टून टिनटिन बहुत जल्द हिंदी में प्रकाशित होने वाला है. एक प्रसिद्ध पाश्चात्य कॉमिक, जिसकी रचना बेल्जियम में हुई थी, को भारतीय बाज़ार में पहुंचाने की कवायद शुरू हो चुकी है. बेल्जियम में टिनटिन कार्टून सीरीज का हिंदी अनुवाद शुरू हो चुका है. यही नहीं, आठ किताबों का अनुवाद पूरा हो चुका है. टिनटिन एक किशोरवय लड़का है, जो अपने कुत्ते स्नोई एवं कैप्टन हैडवैक के साथ साहसिक और रोमांचक यात्राओं पर निकलता है. कहानी में डिटेक्टिव थॉमसन एंड थॉमसन नामक जुड़वां भाई प्रमुख पात्र हैं. बेल्जियम दूतावास के अनुसार, टिनटिन सीरीज की कॉमिक ग्रेट स्नेक्स को हिंदी में बाल की खाल नाम से प्रकाशित किया गया है. वहीं डिटेक्टिव थॉमसन एंड थॉमसन को संतू-बंतू और स्नोवी डॉग को नटखट नाम दिया गया है. बिलियंस ऑफ बिलियास ब्लू ब्लिस्टरिंग बरनेकल्स को काले कछुवे के नाम से प्रकाशित किया गया है. भारतीय बाज़ार में ये पुस्तकें जल्द आने वाली हैं. हिंदी में कॉमिक्स की क़ीमत 195 रुपये रखी गई है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

टेककॉम का नया कलेक्शन

ग्लैमरस बॉलीवुड अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे ने टेककॉम इलेक्ट्रॉनिक्स का नया मोबाइल फोन कलेक्शन भारतीय बाज़ार में लांच किया है. आईटी और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी टेककॉम ने सात मोबाइल फोनों का यह कलेक्शन लांच करके भारतीय मोबाइल फोन बाज़ार में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है. इस रेंज में टी-21, टी-31, टी-33, टी-51, टी-55, टी-60 और टी क्यू-21 सभी डुअल सिम हैंडसेट हैं. बेहतरीन फीचर्स के साथ ये मोबाइल फोन देखने और हैंडल करने में भी कंफर्टेबल हैं. लांचिंग के अवसर पर टेककॉम की मोबाइल फोन डिवीजन के निदेशक ने कहा कि यह रेंज ग्रामीण और शहरी, दोनों तरह के ग्राहकों को ध्यान में रखकर लांच की गई है. फ़िलहाल कंपनी के तक़रीबन 100 डिस्ट्रीब्यूटर और 500 रिटेलर भारत में मौजूद हैं. कंपनी इन मोबाइल फोनों के बेहतरीन प्रचार-प्रसार के लिए आगामी छह महीनों में ग्राहकों को लुभाने वाले कई प्रोमोशनल ऑफर लाने वाली है. टेककॉम के ये फोन मल्टीमीडिया फोन हैं, जिनमें आजकल की आधुनिक जीवनशैली को मैच करने वाले लगभग सभी फीचर्स मौजूद हैं. इनमें टी क्यू-21 सबसे खास फोन है. जीपीआरएस/वैप इनेबल्ड इस फोन में डुअल सिम और 8 जीबी एक्सपेंडेबल मेमोरी की सुविधा है. 1.3 मेगा पिक्सल कैमरा भी है, जिससे ली गई तस्वीरें इसके 6.1 सेमी क्यूवीजीए एलसीडी स्क्रीन पर देखने में काफी अच्छी लगती हैं. बाक़ी अन्य मोबाइल मॉडलों में भी डुअल सिम के साथ वीडियो रिकॉर्डर, इंडियन कैलेंडर, ब्लुटुथ, एक्सपेंडेबल मेमोरी आदि मल्टीमीडिया फीचर्स हैं. इस रेंज के मोबाइल फोनों की क़ीमत 1500 रुपये से लेकर 4000 रुपये तक है.

विज्ञापन हेतु संपर्क करें : email : advt@chauthiduniya.com

भारत में शीतकालीन खेलों का दायरा बेहद सीमित रहा है. कश्मीर के गुलमर्ग, हिमाचल के मनाली एवं उत्तराखंड के औली में ढलानों पर स्कीइंग प्रतियोगिताएं होती रही हैं.

शीतकालीन सैफ खेल

आयोजन पर आशंकाएं बरक़रार

पिछले तीन सालों से टलते आ रहे शीतकालीन सैफ खेलों को लेकर इन दिनों उत्तराखंड में तेज़ी आ गई है. आयोजन में अब केवल एक माह का समय बचा है, किंतु घोषित तिथियों पर इनके संपन्न होने को लेकर कई प्रकार की आशंकाएं बरक़रार हैं, इनमें औली में स्कीइंग प्रतियोगिता प्रमुख है. शीतकालीन सैफ खेल भारतीय ओलंपिक संघ, भारतीय शीतकालीन खेल महासंघ एवं राज्य सरकार की लचर व्यवस्था का एक नमूना बनकर रह गए हैं. सैफ दक्षिण एशिया के 8 देशों एक संगठन है, जिसमें भारत, बांग्लादेश, मालदीव, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफ़ग़ानिस्तान एवं नेपाल शामिल हैं. 1980 में एक विचार आया कि सदस्य देश सैफ खेल आयोजित करें, इससे पारस्परिक संबंध अधिक मधुर होंगे. यह विचार 1984 में पहली बार काठमांडू में साकार हुआ, जहां पहले सैफ खेलों का आयोजन हुआ. अब तक 11 बार हो चुके सैफ खेल हर दो साल के अंतराल में होते हैं. इनमें हमेशा भारत का वर्चस्व रहा है, जबकि पाकिस्तान को 8 बार, श्रीलंका को 2 बार और नेपाल को एक बार दूसरे स्थान पर आने का मौक़ा मिल चुका है. इन खेलों के ज़्यादातर रिकार्ड भारतीय खिलाड़ियों के नाम पर हैं.

भारत में शीतकालीन खेलों का दायरा बेहद सीमित रहा है. कश्मीर के गुलमर्ग, हिमाचल के मनाली एवं उत्तराखंड के औली में ढलानों पर स्कीइंग प्रतियोगिताएं होती रही हैं. सैफ विंटर गेम्स का विचार भारतीय ओलंपिक संघ के सचिव रणधीर सिंह के दिमाग़ की उपज माना जाता है. उन्होंने ही 2006 के कोलंबो सैफ खेलों के दौरान इसके भारत में आयोजन का प्रस्ताव रखा और इसके लिए उत्तराखंड का चयन भी कर लिया. संघ ने राज्य सरकार को शीतकालीन खेलों हेतु आधारभूत ढांचा खड़ा करने और तैयारी के लिए तीन साल का समय देते हुए फरवरी 2008 तक आयोजन कराने की घोषणा की थी. राज्य सरकार ने इसके लिए एक लंबी-चौड़ी विंटर गेम्स आयोजन समिति भी बना दी, लेकिन आयोजन स्थलों पर आधारभूत सुविधाएं न जुट पाने के कारण आयोजन अब तक नहीं हो पाया. इधर जबसे आयोजन की नई तिथियों की घोषणा हुई है, तबसे सरकार हरकत में आई है, लेकिन आउटडोर आयोजन स्थल औली को आज भी बर्फ का इंतज़ार है, जहां स्कीइंग प्रतियोगिताएं होनी हैं. यदि घोषित तिथियों तक औली में बर्फ न गिरी तो हो सकता है कि इसकी कुछ प्रतियोगिताएं बर्फ होने तक टाल दी जाएं. हालांकि आयोजन समिति मौसम की मार और विकट परिस्थितियों का हवाला अभी से देने लगी है.

आयोजन के लिए केंद्र से 110 करोड़ और राज्य से 5 करोड़ रुपये पहले ही मिल चुके हैं, लेकिन देरी की वजह से लागत बढ़ चुकी है. विंटर ओलंपिक की शुरुआत 1924 में फ्रांस के केमोनिकस में हुई थी. 1940 एवं 1944 में विश्व युद्ध के कारण इनका आयोजन नहीं हो सका. 2006 में टयूरिन में हुए 19वें शीतकालीन ओलंपिक में 8 खेलों की लगभग 86 प्रतिस्पर्धाओं में 80 देशों ने भाग लिया था. इसमें भारत से 4 प्रतियोगी शामिल हुए, जबकि नेपाल से एक. 2010 के कनाडा के वैंकूवर में हुए शीतकालीन विंटर ओलंपिक में 82 देशों के लगभग 2500 प्रतियोगियों ने भाग लिया था, जिसमें यूरोपीय एवं अमेरिकी देशों का ही बोलबाला रहा. इसमें भारत से 3, पाकिस्तान एवं नेपाल से 1-1 प्रतियोगी शामिल हुए. जबकि भारत में हो रहे शीतकालीन सैफ खेलों में कितने देश एवं खिलाड़ी भाग लेंगे, यह अभी तक तय नहीं है. 8 सैफ देशों में से नेपाल आंतरिक विवादों से जूझ रहा है और पाकिस्तान एवं अफ़ग़ानिस्तान में चरमपंथी-कट्टरपंथी ताक़तों के ख़िलाफ़ संयुक्त सेनाओं का युद्ध चल रहा है. ऐसे में इन देशों से खिलाड़ियों के आने की उम्मीद नहीं है. उल्लेखनीय है कि भारत एवं भूटान के अलावा इन्हीं तीन देशों में शीतकालीन खेलों की संभावनाएं हैं, क्योंकि बांग्लादेश, मालदीव एवं श्रीलंका में बर्फ ही नहीं गिरती.

दूसरी ओर आयोजन समिति सभी सदस्य देशों के खिलाड़ियों द्वारा हिस्सा लेने की बात कर रही है. मुक़ाबले में कोई टीम न होने की स्थिति में भारत की ओर से कई टीमें उतर सकती हैं. तैयारी न होने और बर्फ न गिरने के कारण कई सालों से पुराने खिलाड़ियों को न तो प्रैक्टिस का मौक़ा मिला और न नए खिलाड़ी आगे आ रहे हैं. कई खेल तो पहली बार हो रहे हैं, जिन्हें कैसे खेलना है, इसके लिए कोचिंग शुरू होने वाली है, लेकिन वह भी कैसे हो? हो सकता है कि अंतिम समय तक बर्फ गिरने पर उत्तराखंड, हिमाचल एवं कश्मीर के युवाओं और स्कीइंग जानने वाले लोगों को प्रशिक्षण देकर जैसे-तैसे खड़ा कर दिया जाए. सबसे बड़ी ग़लती यह हुई कि औली की ढाल पर जमी मखमली घास ट्रैक बनाने के लिए उधेड़ दी गई, ताकि जब बर्फ गिरे तो यहां स्कीइंग अच्छी तरह हो सके. लेकिन जब कम बर्फ गिरने की बात आई और इस कारण यहां प्रतियोगिता न होने का प्रश्न उठा तो सुझाव मिला कि फिर से यथास्थिति बनाई जाए, ताकि कृत्रिम रूप से बर्फ जमा कर स्कीइंग कराई जा सके. ऐसा कराया भी गया, किंतु बरसात ने सब गुड़ गोबर कर दिया. इससे लगभग सवा किलोमीटर की इस ढलान पर बहा मलबा जोशीमठ के कई घरों में जा घुसा.

इन दिनों एक बार फिर मिट्टी बिछाकर घास उगाने का काम हो रहा है, किंतु इतनी ठंड में अब घास उगना संभव नहीं है. ट्रैक पर कृत्रिम रूप से बर्फ जमाने के लिए 6.5 करोड़ रुपये की मशीन लाई गई है, जिसका अभी व्यवहारिक परीक्षण चल रहा है. बर्फ जमाने के लिए एक बड़ा तालाब बनाया गया है, जिसमें 5 किलोमीटर दूर से पानी आता है. पहले यह कहा गया कि बर्फ गिरने के बाद इस मशीन से 1300 मीटर लंबे और 40 मीटर चौड़े स्कीइंग स्लेप पर एक फीट तक बर्फ की तह बिछाकर उसे उपयुक्त बनाने के लिए बीटर्स से दबाया जाएगा, फिर इसी मशीन से कृत्रिम बर्फ जमाकर स्कीइंग कराई जाएगी. लेकिन अब जैसे हालात हैं, उनमें कृत्रिम बर्फ जमाकर स्कीइंग कराना असंभव है. इसी तरह अभी यहां स्की लिट लगना बाक़ी है. दो चरणों में होने वाले इन खेलों का उद्घाटन एवं पहला चरण आगामी 7 से 12 जनवरी तक आउटडोर प्रतियोगिताओं के रूप में औली में होना है, जबकि 14 से 19 जनवरी तक दूसरा चरण एवं समापन समारोह देहरादून में संपन्न होगा, जहां इंडोर प्रतियोगिताएं होंगी. लगभग 11000 फीट की ऊंचाई पर स्थित चमोली ज़िले का औली आउटडोर प्रतियोगिताओं का स्थल है, जो देहरादून से लगभग 300 किलोमीटर दूर है. औली की ढलान पर तीन खेलों के तहत कुल 15 पदकों का फ़ैसला होना है, जिनमें एल्पाइन स्कीइंग, नोर्डिक स्कीइंग एवं स्नो बोर्ड शामिल हैं. पहले दो खेलों के तहत महिला एवं पुरुष वर्ग की कुल 10 प्रतिस्पर्धाएं होनी हैं. दूसरे चरण के लिए देहरादून में दो हज़ार दर्शकों की क्षमता वाला 65 मीटर लंबा एवं 30 मीटर चौड़ा इंडोर आइस स्केटिंग रिंक बनाया गया है. इस पर 55 करोड़ रुपये से अधिक की लागत आई है. यह मैदान काम करने लगा है. देश में सिर्फ़ देहरादून में ही ऐसा रिंक है. यहां स्केटिंग के तीन खेल यानी स्पीड स्केटिंग, फिगर स्केटिंग एवं आइस हॉकी होने हैं. जूनियर बालक एवं बालिका वर्ग के लिए भी कम दूरी की स्केटिंग प्रतियोगिताएं रखी गई हैं.

आयोजन में चौतरफा देरी और इसके विभिन्न पहलुओं को लेकर सीएजी अपनी रिपोर्ट दे चुका है. 2009 में आई इस रिपोर्ट में कई सवाल उठाए गए हैं, जिनमें निर्माण की मंथर चाल, गुणवत्ता, धन का दुरुपयोग और तकनीकी कमियों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया. एक सवाल यह भी था कि काम पूरा होने से पहले विदेशी सलाहकार कंपनियों को दो करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान क्यों कर दिया गया? अगर स्कीइंग प्रतियोगिताएं टलती हैं तो इससे राज्य सरकार की किरकिरी तय है. औली में प्रतियोगिताएं होने की स्थिति में सिर्फ़ 500 लोगों के रुकने की व्यवस्था हो सकती है, शेष को जोशीमठ में ही रुकना होगा. हरिद्वार से औली तक 300 किलोमीटर सड़क मार्ग आज भी कई स्थानों पर बेहद ख़राब है.

एल. मोहन कोठियाल
feedback@chauthiduniya.com

देश का पहला इंटरनेट टीवी
हर दिन 50,000 से ज़्यादा दर्शक
दो टूक-संतोष भारतीय के साथ
ब्लैक एंड व्हाइट रोज़ाना 1 बजे
पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया
स्पेशल रिपोर्ट
नायाब हैं हम-उर्दू के मशहूर शायरों, गीतकारों के साथ मुलाक़ात
साई की महिमा
एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा-201301 www.chauthiduniya.tv

Postal Regn. No. DL/ND-11/6139/2009-11, RNI No. DELHIN/2009/30467

यह गौहर के लिए परीक्षा की घड़ी थी, लेकिन उन्होंने हार न मानते हुए बेहतर प्रदर्शन किया और लोगों को उनका काम पसंद भी आया.

अंतरराष्ट्रीय पर्यटन का हिस्सा बनता बॉलीवुड

रीतिका सोनाली

बॉलीवुड फिल्मों का बाज़ार दूसरे देशों की फिल्मों के बाज़ार से ज़्यादा व्यापक है. यही वजह है कि इन फिल्मों की शूटिंग लोकेशंस का काफी प्रचार-प्रसार होता है. एक बात जो सबसे ज़्यादा अहम है, वह यह कि जहां-जहां फिल्मों की शूटिंग होती है, वहां के पर्यटन व्यवसाय में काफी इज़ाफ़ा हो जाता है. यह बात कई देश मान चुके हैं और वे चाहते हैं कि उनके पर्यटन स्थलों पर ख़ासकर बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग हो. इस बात पर किसी और ने नहीं, बल्कि रोमानिया के एक मंत्री ने मुहर लगाई है. हालांकि हमारे देश में इसका बिल्कुल उल्टा है. यहां किसी भी मॉन्यूमेंट या टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर शूटिंग की इजाज़त लेना फिल्म निर्माताओं के लिए मुश्किलों भरा काम है. यही वजह है कि अपने देश में बेहतरीन लोकेशंस एवं पर्यटन स्थल होने के बावजूद वहां फिल्मों की शूटिंग कम ही होती है. रोमानिया के एक मंत्री बार्बी केरली का कहना है कि बॉलीवुड केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि व्यापार का बहुत बड़ा ज़रिया है. केरली ने बॉलीवुड के फिल्म निर्माताओं को शूटिंग के लिए रोमानिया आमंत्रित किया है. उनके अनुसार, अगर बॉलीवुड वहां शूटिंग करेगा तो उनके देश का प्रचार होगा, साथ ही जिन जगहों पर फिल्म की शूटिंग होगी, वहां पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा. यही बात मालदीव के पर्यटन मंत्री टोइड मोहम्मद ने भी कही. बकौल टोइड, अगर बॉलीवुड के फिल्म निर्माता उनके यहां आकर शूटिंग करेंगे तो वह मालदीव की अधिकांश जगहों को शूटिंग लायक़ बना देंगे. सिर्फ़ 6.5 लाख आबादी वाले द्वीप मालदीव की अर्थव्यवस्था पर्यटन पर निर्भर है. यहां 85,000 भारतीय रहते हैं. यहां बॉलीवुड की फिल्में और टेलीविज़न धारावाहिक बच्चों से लेकर बड़ों तक पसंद किए जाते हैं. स्थानीय ट्रेवल एजेंट कहते हैं कि बॉलीवुड की वजह से यहां पर्यटन को काफी बढ़ावा मिला.

ऋतिक रोशन की फिल्म काइट्स की शूटिंग मालदीव में हुई थी. इससे मालदीव के पर्यटन व्यवसाय में काफी इज़ाफ़ा हुआ. बी टाउन के लोगों को आकर्षित करने के लिए ही इजिप्ट टूरिज्म ने अपना ब्रांड एंबेसडर बॉलीवुड अदाकारा सेलिना जेटली को बनाया है. हालांकि इजिप्ट के पिरामिड में पहले से ही बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग होती रही है, लेकिन इन दिनों इजिप्ट की लोकप्रियता बॉलीवुड में बढ़ती जा रही है. सेलिना जेटली द्वारा इजिप्ट के पिरामिड के पास कराए गए फोटो शूट ने कला जगत के काफी लोगों को आकर्षित किया. सिर्फ़ बॉलीवुड या कला जगत नहीं, बल्कि आम लोगों के बीच भी इजिप्ट को लोकप्रिय बनाने के लिए वहां की सरकार ने कोशिशें शुरू की हैं. ऐश्वर्या राय एवं प्रशांत द्धारा इजिप्ट के पिरामिड के आसपास घूमकर गाए फिल्म जींस के गीत अजूबा है... को ख़ूब पसंद किया गया. इसके बाद फिल्म कभी खुशी कभी गम में शाहरुख़ खान एवं काजोल पर फिल्माया गया रोमांटिक गीत सूरज हुआ मद्धिम... भी ख़ूब लोकप्रिय हुआ. इसके बाद फिल्म सिंह इज किंग के गीत जी करदा... और तेरी ओर...से भी इजिप्ट के पिरामिड को ख़ूब प्रचार-प्रसार मिला.

यह फॉर्मूला केवल विदेशों पर ही लागू होता है. पर्यटन बढ़ने के पीछे तर्क यही होता है कि एक तो लोग शूटिंग के दौरान ही पहुंच कर कलाकारों और लोकेशंस को देखना चाहते हैं. दूसरे यह कि ज़्यादातर लोगों में फिल्म देखने के बाद शूटिंग की लोकेशंस देखने की चाहत होती है. उदाहरण के लिए फिल्म वीर की ज़्यादातर शूटिंग जयपुर में हुई थी. शूटिंग के बाद उस लोकेशन की ख़ूब चर्चा हुई और वहां पर्यटन पहले से कई गुना बढ़ गया. ऐसे उदाहरणों की कमी नहीं है. सवाल यह उठता है कि अगर दूसरे देश बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग को लेकर लालायित हैं तो फिर हमारी सरकार ऐसा क्यों नहीं सोचती? क्यों नहीं वह बॉलीवुड को उतनी अहमियत देती?

ritika@chauthiduniya.com

गुल की टर्निंग 30

पिछले दिनों जब गुल पनाग एक इवेंट में हिस्सा लेने दिल वालों की दिल्ली पहुंचीं तो उन्हें यहां के पुरुषों का रवैया पसंद नहीं आया. हालांकि ख़ुद दिल्ली की होने की वजह से उनका प्रेम इस शहर के प्रति कम नहीं होता, लेकिन वह यहां लड़कियों की असुरक्षा को लेकर काफी दुखी हैं. अपनी आने वाली फिल्म टर्निंग 30 के प्रोमोशन के लिए वह फिर से दिल्ली में नज़र आएंगी और लड़कियों की बाइक रेस में भी हिस्सा लेंगी. बाइक चलाने की शौकीन गुल लड़कियों को हिम्मत के साथ जीने की सलाह देती हैं. उनका मानना है कि किसी भी मामले में यदि असहमति से काम न चले तो जबरदस्त विरोध जताना चाहिए और यह विरोध तब तक जारी रखना चाहिए, जब तक अपनी मांग पूरी न हो जाए. यह उन्होंने दिल्ली में लड़कियों के साथ हो रही अप्रिय घटनाओं के प्रति सरकार और प्रशासन की चुप्पी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा. फिल्म टर्निंग 30 के निर्माता प्रकाश झा हैं और निर्देशन की जिम्मेदारी संभाली है अलंकृता श्रीवास्तव ने. फिल्म में गुल के साथ पूरब कोहली और सिद मक्कड़ भी हैं. कहानी भी अलंकृता श्रीवास्तव ने ही लिखी है. टर्निंग 30 नैना नामक एक लड़की की कहानी है. इसमें नैना का किरदार गुल ने निभाया है. 30वें जन्मदिन पर नैना को अपने एडवरटाइज़िंग करियर में संकट झेलना पड़ता है. मुंबई जैसे महंगे शहर में रहने वाली अकेली औरत को करियर में संघर्ष के दौरान किन-किन हालात से गुजरना पड़ता है, यही कहानी है नैना की.

मासूम रिया

बी टाउन बेब रिया सेन इन दिनों दक्षिण और दूसरी भाषाओं की फिल्में कर रही हैं. आजकल वह एक मलयालम फिल्म की शूटिंग में व्यस्त हैं. यह फिल्म एक अंधे व्यक्ति को फोकस करके बनाई गई, जिसका निर्देशन सलमान अंसारी कर रहे हैं. उनका मानना है कि रिया के चेहरे पर जो मासूमियत है, वह इस इंडस्ट्री के किसी और चेहरे पर नज़र नहीं आती. इसके अलावा सेन बहनों का जलवा एक साथ जल्द ही पर्दे पर नजर आने वाला है. रवींद्र नाथ टैगोर के उपन्यास नौका डूबी पर बनने वाली फिल्म में दोनों एक साथ नजर आएंगी. वाइफ स्वैपिंग की कहानी में दोनों बहनों ने तगड़ा किरदार निभाया है. इस फिल्म में निर्माता सुभाष घई और निर्देशक रितुपर्णा सेनगुप्ता के बीच ही बहस के मुद्दे तैयार हो गए थे. चूंकि उपन्यास में दोनों महिलाएं कभी आमने-सामने नहीं लाई गईं, रितुपर्णा भी फिल्म में ठीक यही दिखाना चाहती थीं, लेकिन सुभाष घई का मानना था कि फिल्म में दोनों सुंदरियों को एक साथ न दिखाना दर्शकों के साथ नाइंसाफी होगी. रितुपर्णा को कलात्मक और संवेदनशील फिल्में बनाने में महारत हासिल है. उनका मानना है कि उपन्यास के किसी भी पहलू को छला नहीं जाना चाहिए. हालांकि निर्देशक की इस सोच से दोनों बहनों को कोई आपत्ति नहीं है. जनवरी 2011 में रिलीज होने वाली यह फिल्म हिंदी-बांग्ला भाषा का मिश्रण है. इसमें दोनों बहनों के साथ बंगाली सुपर स्टार प्रसन्नजीत होंगे.

गौहर की दस्तक

सत्तर के दशक में हेलन को होश उड़ा देने वाली डांसर माना जाता था. अब गौहर खान ने इक्कीसवीं सदी की बेस्ट डांसर्स में अपना नाम दर्ज करा लिया है. जबसे उन्होंने फिल्म वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई में आइटम डांस किया है, उनके सितारे चमकने लगे हैं. पिछले कुछ समय से वह काफी चर्चा में हैं, बी टाउन में लोग उन्हें नोटिस करने लगे हैं. रणवीर कपूर के साथ यशराज फिल्म्स के बैनर तले बनी फिल्म रॉकेट सिंह-सेल्समैन ऑफ द ईयर में उनके काम को काफी सराहना मिली, लेकिन इसमें उनके रोल के बिल्कुल उलट एक आइटम डांस का ऑफर किया गया. यह निश्चित ही गौहर के लिए परीक्षा की घड़ी थी, लेकिन उन्होंने हार न मानते हुए बेहतर प्रदर्शन किया और लोगों को उनका काम पसंद भी आया. बिल्कुल साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाली गौहर ने जीवन में सभी चुनौतियों को न सिर्फ़ स्वीकार किया, बल्कि उन पर खरी भी उतरीं. मॉडलिंग, वीजे, विज्ञापन और फिर फेमिना मिस इंडिया कांटेस्ट में चौथा स्थान पाकर भी वह आगे बढ़ने का सपना देखती रहीं, बल्कि उसे पूरा करने के लिए उन्होंने जमकर मेहनत की. दूसरे न्यूकमर्स की तरह उन्होंने अपने करियर में ग़लत फ़ैसले कम किए और ध्यान रखा कि वह बड़े और नामी निर्देशकों के साथ ही काम करें. बी टाउन में गौहर द्धारा अपने पैर जमाने की कोशिश निश्चित रूप से सराहनीय है.

प्रीव्यू

टूनपुर का सुपरहीरो

भारत में ऐनिमेशन फिल्मों के निर्माण पर काफी ध्यान दिया जा रहा है. भारत की पहली लाइव एक्शन थ्री डी ऐनिमेशन फिल्म टूनपुर का सुपर हीरो जल्द ही सिनेमाघरों में छाने वाली है. इस फिल्म में अजय देवगन एवं काजोल भूमिका में होंगे. उनके साथ बाल कलाकार चिंकी जायसवाल एवं अमेय पांडे हैं. फिल्म के निर्देशक अनुभव सिन्हा हैं और इसमें ऐनिमेशन इफेक्ट दिया है मशहूर ऐनिमेटर किरण खुराना ने. कहानी लिखी रागी भटनागर ने और निर्देशन किरीत खुराना का है. फिल्म को प्रोड्यूस किया है कुमार मंगत पाठक, कृषिका लुल्ला एवं शरण कपूर ने. संगीत दिया है अनु मल्लिक ने और सिनेमेटोग्राफी है निर्मल जानी की. हिंदी भाषा में बनी इस फिल्म का संपादन ब्रि स्क्रीन, इंटरटेनमेंट एवं क्लिंब मीडिया के स्टूडियो में किया गया. डिस्ट्रीब्यूशन की जिम्मेदारी इरोज इंटरनेशनल और आईबीसी मोशन पिक्चर्स को दी गई है. फिल्म का बजट लगभग एक अरब रुपये है और इसमें स्पेशल इफेक्ट्स के लिए बेहतरीन कंप्यूटर तकनीकों का प्रयोग किया गया है.

यह फिल्म उन बच्चों पर आधारित है, जो बुरी चीजों के बारे में सोचते हैं, लेकिन उन सभी के सच हो जाने पर उन्हें असलियत का एहसास होता है. फिल्म में अजय देवगन आदित्य नामक फिल्म स्टार का किरदार निभा रहे हैं और उनकी पत्नी प्रिया का रोल काजोल अदा कर रही हैं. फिल्मों में सफलता पाने के बाद आदित्य एवं प्रिया वे सारी खुशियां पा लेते हैं, जिनकी उन्हें चाह होती है, लेकिन बच्चे कबीर एवं रायमा अपने पापा आदित्य को रीयल लाइफ हीरो के तौर पर देखना चाहते थे. आदित्य अपने बच्चों के आगे रीयल लाइफ हीरो बनना चाहते हैं और उनका यह सपना तब पूरा होता है, जब वह बच्चों के कार्टून वर्ल्ड पहुंच जाते हैं. यहां पर उन्हें देवटून के लिए टूनासुरों से लड़ाई करनी पड़ती है. फिल्म में रजा मुराद एवं तनुजा ने स्पेशल अपीयरेंस दी है. यह फिल्म आगामी 17 दिसंबर को रिलीज होगी.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया

उत्तर प्रदेश
उत्तराखंड

दिल्ली, 20 दिसंबर-26 दिसंबर 2010

www.chauthiduniya.com

आजम ख़ान समाजवादी पार्टी में, पर

मुसलमान कहां हैं

फोटो- पीटीआई

विजय यादव

समाजवादी पार्टी में वापसी के बाद आजम ख़ान ने भले ही अमर सिंह पर निशाना साधा हो, लेकिन उन्हें अब यह भी साबित करना होगा कि उत्तर प्रदेश के मुसलमान आज कहां और किसके साथ खड़े हैं. राजनीति में दोस्ती-दुश्मनी का खेल चलता रहता है, जिसके नफे-नुक़सान को आम मतदाता, ख़ासतौर पर मुस्लिम समाज अच्छी तरह से समझने लगा है. बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम इसका सबूत हैं. आजम ख़ान की वापसी के बाद मुलायम सिंह यादव, शिवपाल, अखिलेश यादव समेत तमाम नेता ऐसे प्रफुल्लित हैं, मानों समूचा मुस्लिम वोट बैंक पार्टी की झोली में आ गिरा है. सपा के यह खेवनहार लोकसभा चुनाव में रामपुर सीट से जयाप्रदा की शानदार जीत का दृश्य शायद भूल जाते हैं. आजम ख़ान के लाख विरोध करने के बावजूद रामपुर के मुसलमानों ने जयाप्रदा को लोकसभा पहुंचा कर ही दम लिया था. अब सवाल यह है कि जब आजम ख़ान अपने ही घर में प्रभावी नहीं रहे तो वह समूचे उत्तर प्रदेश में मुसलमानों पर कितना प्रभाव छोड़ सकेंगे. वह भी उन परिस्थितियों में, जब मुस्लिम समाज के राजनीतिक मसलों के साथ-साथ प्राथमिकताएं एवं समस्याएं भी बदल चुकी हैं. आम मुसलमान बाबरी मस्जिद की शहादत जैसे भावनात्मक मुद्दों के साथ ही अब शिक्षा और आर्थिक क्षेत्र में हिस्सेदारी के मसले पर भी गंभीर है. ग़रीब से ग़रीब मुसलमान अपने बच्चों को तरक्की की दौड़ में शामिल कराने की कतार में खड़ा है. इसे भांपकर ही उत्तर प्रदेश की सियासत में पीस पार्टी, उलेमा काउंसिल और मोमिन कांफ्रेंस तेजी से आगे बढ़ रही हैं. इन संगठनों ने आम आदमी के बुनियादी सवालों को उठाया है, इसका असर है कि इन्हें मुसलमानों और हिंदुओं का बराबर समर्थन मिल रहा है. समाजवादी पार्टी के लिए सबसे बड़ा ख़तरा भी इन्हीं संगठनों से है. लखीमपुर खीरी में हुए विधानसभा उपचुनाव में भी सपा के बाद पीस पार्टी ही दूसरे स्थान पर रही थी. वर्ष 2012 में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनज़र उत्तर प्रदेश मुसलमानों की राजनीति की प्रयोगशाला बन चुका है. भाजपा को छोड़ दें तो कमोबेश सभी राजनीतिक दल मुसलमानों को रिझाने और उन्हें अपने पाले में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं. यह अनायास भी नहीं है. उत्तर प्रदेश विधानसभा की 180 सीटें ऐसी हैं, जिन पर मुस्लिम वोट बैंक किसी भी प्रत्याशी का भाग्य बदल सकता है. 20 से अधिक जनपदों में मुसलमानों की संख्या बीस प्रतिशत से अधिक है. रामपुर में मुसलमानों की आबादी 52.91 प्रतिशत है. तीन बड़े मुस्लिम नेता भी यहीं से रिश्ता रखते हैं. ख़ुद आजम ख़ान रामपुर खास विधानसभा सीट से सात बार से विधायक हैं. कांग्रेस की बेगम नूरबानो, भाजपा के मुख्तार अब्बास नकवी रामपुर से ही ताल्लुक रखते हैं. फिर भी रामपुर की साक्षरता दर महज 33 प्रतिशत है. ऐसे में अगर रामपुर के मुस्लिम मतदाता आजम ख़ान, नूरबानो और नकवी को दरकिनार कर जयाप्रदा को लोकसभा पहुंचा देते हैं तो इसका क्या संदेश है? जाहिर है कि रामपुर के मुस्लिम अपनी ज़रूरतें पहचान चुके हैं. यही तस्वीर उत्तर प्रदेश के अन्य ज़िलों की भी है. लखीमपुर खीरी के विधानसभा उपचुनाव के परिणाम से साफ़ पता चलता है कि मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी पर पूरा भरोसा नहीं जताया. यहां से सपा प्रत्याशी ने जीत भले ही हासिल की, लेकिन मतदाताओं ने दूसरे स्थान पर पीस पार्टी को ही रखा. पीस पार्टी को 24 हज़ार से अधिक मत मिले, जो कुल वोटिंग का 18 फ़ीसदी है. इससे पहले पीस पार्टी का वजूद केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश में ही माना जाता था, लेकिन पश्चिम की ओर उसकी ऊंची छलांग ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के अलावा बहुजन समाज पार्टी को भी चिंतित कर दिया है. पीस पार्टी का ही असर रहा कि कांग्रेस यहां चौथे नंबर पर पहुंच गई, जबकि इस इलाक़े से कांग्रेस का सांसद है और कांग्रेस ने सांसद पुत्र को ही उम्मीदवार बनाया था. उल्लेखनीय है कि लखीमपुर खीरी में मुसलमानों की आबादी 22.54 फ़ीसदी है. जब लखीमपुर में उपचुनाव हो रहा था, उस समय मुलायम सिंह यादव और आजम ख़ान एक-दूसरे के निकट आ चुके थे. दोनों ओर से प्रेम का पैगाम दिया जा रहा था, लेकिन मुसलमान मतदाताओं ने सपा के साथ पीस पार्टी पर भी उतना ही भरोसा जताया, जो दर्शाता है कि मुस्लिम समाज अब किसी एक नेता के कहने पर चलने वाला नहीं है. वह अपना अच्छा-बुरा सोच-समझ कर वोट करने की ठान चुका है. इन स्थितियों में आजम ख़ान समाजवादी पार्टी के लिए कितने असरकारक होंगे, यह कह पाना मुश्किल है. पीस पार्टी ने पिछले लोकसभा चुनावों में 21 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे और उसके प्रत्याशियों को 26 हज़ार से लेकर सवा लाख तक वोट मिले थे. लोकसभा चुनाव में पार्टी चौथे और पांचवें स्थान पर रही थी. फिर डुमरियागंज में तीसरे और लखीमपुर में दूसरे स्थान पर पहुंच गई, जो उसकी स्वीकार्यता का प्रतीक है.

उर्दू-अरबी-फारसी विश्वविद्यालय के कुलपति अनीस अंसारी की एक बात से राजनीतिक दलों के प्रति मुसलमानों की धारणा का पता चल जाता है. अंबेडकर महासभा परिसर में आयोजित एक कार्यक्रम में उनके जज्बात फूट पड़े. वह कहते हैं कि राजनीतिक दल मुसलमानों की बुनियादी ज़रूरतों का मसला नहीं उठाते हैं. बाबरी मस्जिद की शहादत का मसला उठाकर नेता मुसलमानों की भावनाओं का दोहन करते हैं, लेकिन वे यह पहल नहीं करते कि मुसलमानों को उच्च शिक्षा में आरक्षण मिले, दलित और पिछड़े मुसलमानों को भी हिंदुओं की तरह आरक्षण मिले. उनका सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक स्तर ऊंचा उठ सके. बस एक अनजाना ख़ौफ़ दिखाकर मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जाता है. अंसारी का यह दर्द आम मुसलमानों के भीतर भी छिपा है, जो अब राह ताक रहा है कि कोई उसकी स्थिति में बदलाव लाए. आजम ख़ान इस उम्मीद पर कितने ख़रे उतरेंगे, यह कह पाना मुश्किल ही नहीं, बल्कि नामुमकिन है. वजह आजम ख़ान सपा की सरकार में मंत्री रहे हैं. राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं, फिर भी उनके घर का मुसलमान ही शिक्षा के स्तर पर काफ़ी पिछड़ा हुआ है. ऐसे में वह प्रदेश भर के मुस्लिमों को उनका रहनुमा होने का विश्वास कैसे दिला पाएंगे, इस सवाल का जवाब तलाशने की आवश्यकता अब ख़ुद समाजवादी पार्टी को है. सपा के भीतर आजम के विरोधी भी इसी ताक में हैं. सपा इस ख़तरे को भांप रही है, ऐसा पार्टी की रंगनाथ आयोग और सच्चर कमेटी की सिफ़ारिशों के प्रति जाहिर की गई चिंता को देखकर लगता है. समाजवादी पार्टी के लिए आजम ख़ान मुस्लिम चेहरा बनकर आए हैं. उनकी वापसी को इसी नज़रिए से प्रस्तुत भी किया गया. इससे ख़ुद सपा के भीतर उन मुस्लिम नेताओं को तकलीफ होना लाज़िमी है, जो आजम ख़ान के पार्टी से निष्कासित होने के बाद उन्हें कोसते फिर रहे थे. पूर्व सांसद रशीद मसूद ने मंच से यह चिंता जाहिर भी कर दी. मसूद ने कहा कि पूर्व की बातों का दिल में मलाल न रखिएगा. जाहिर है कि सपा के मुस्लिम नेता, जो आजम ख़ान के बाहर होने के बाद मुलायम सिंह यादव के काफ़ी नजदीक आ गए थे, एक ही झटके में ख़ुद को किनारे पर खड़ा महसूस करने लगे हैं. रशीद मसूद का बयान इसी ओर इशारा करता है. समय की मांग और मजबूरी में ये सभी चुप भले हैं, लेकिन यह खामोशी सपा के लिए किसी आने वाले तूफान के संकेत से कम नहीं है. अगर ऐसा होता है तो यह उसके ग्राफ को बढ़ाने के बजाय घटाने का काम ही करेगी. आजम ख़ान का जिक्र हो रहा है तो कल्याण सिंह की बात न आए, ऐसा हो नहीं सकता. भाजपा के भीतर रहते हुए कल्याण सिंह का जो दबदबा रहा, वह सभी जानते हैं. भाजपा छोड़ने के बाद कल्याण सिंह की दुर्गति उत्तर प्रदेश की आम जनता देख चुकी है. फिर कल्याण भाजपा में वापस आए, लेकिन पार्टी को उनका वह लाभ नहीं मिला, जो अपेक्षित था. नतीजा कल्याण को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया. कल्याण के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी छोड़ने वाले आजम ख़ान को अब अपनी उपयोगिता साबित करनी होगी. अगर ऐसा न हो सका तो उनका हाल भी कमोबेश कल्याण की तरह ही होगा.

फोटो- प्रभात पाण्डेय

feedback@chauthiduniya.com

कुछ और ही दिखा रहा 2007 का अनुभव

मुस्लिम वोट पर झपट्टा मारने की चिंता से कांग्रेस भी कम चिंतित नहीं है. लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश से कांग्रेस को जो उम्मीद जगी थी, वह लखीमपुर एवं निधौलीकलां के उपचुनाव के बाद दम तोड़ती नज़र आ रही है. सोनिया गांधी और राहुल गांधी का जादू भी मुस्लिम समाज पर नहीं चल रहा है. इन सबके बीच बहुजन समाज पार्टी बेफिक्र नज़र आती है. पार्टी ने लखीमपुर और निधौलीकलां का उपचुनाव नहीं लड़ा. इससे पहले के जो भी उपचुनाव हुए, उनमें सत्ताधारी दल को जीत हासिल हुई, भदोही के उपचुनाव को अपवाद छोड़कर. इन उपचुनावों में बसपा को मुस्लिम समाज का वोट हासिल हुआ और उसने सपा के क़ब्ज़े वाली सीटों को हथियाने में भी सफलता हासिल की. कांग्रेस के लिए आजम ख़ान भले ही चिंता की बात हों, लेकिन बसपा के लिए आजम कोई ख़ास महत्व नहीं रखते. बहुजन समाज पार्टी के लिए वर्ष 2007 के विधानसभा चुनाव की नजीर सामने है. उस चुनाव में आजम ख़ान सपा में ही थे. फिर भी बहुजन समाज पार्टी ने न केवल पहली बार अपने दम पर उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई, बल्कि वह बड़ी संख्या में मुस्लिम विधायकों को सदन पहुंचाने में क़ामयाब रही. उस चुनाव में बसपा के टिकट पर अब्दुल मन्नान (हरदोई), अकबर हुसैन (मुरादाबाद), अकीलुर्रहमान ख़ान (मुरादाबाद), अनीस अहमद खां उर्फ फूल बाबू (पीलीभीत), अरशद खां (पीलीभीत), अलाउद्दीन (बलरामपुर), आसिफ (हरदोई), खातून तौफीक (सिद्धार्थ नगर), गुलाम मोहम्मद ख़ान (बहराइच), जुल्फिकार अहमद भुट्टो (आगरा), ताहिर हुसैन सिद्दीकी (फर्रुखाबाद), दाऊद अहमद (हरदोई), नवाब काजिम अली खां उर्फ नावेद मियां (रामपुर), शेख नसीरूद्दीन सिद्दीकी (फिरोजाबाद), फरहत हसन (ज्योतिबा फुले नगर), फरीद महफूज किदवई (बाराबंकी), मोहम्मद इकबाल (बिजनौर), मोहम्मद इरशाद ख़ान (लखनऊ), मोहम्मद जलील खां (गोंडा), मोहम्मद ताबिस ख़ान (संत कबीर नगर), मोहम्मद जासमीर अंसारी (सीतापुर), मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी (इलाहाबाद), मुस्लिम खां (बदायूं), मुहम्मद गाजी (बिजनौर), रिजवान अहमद खां (ज्योतिबा फुले नगर), वारिस अली (बहराइच), शहजिल इस्लाम अंसारी (बरेली), शहनवाज (बिजनौर), हसरतुल्ला (एटा), हाजी अलीम (बुलंदशहर) एवं हाजी याकूब (मेरठ) ने जीत हासिल की थी. सपा से आजम ख़ान के जाने के बाद लोकसभा चुनाव हुआ, जिसमें बसपा ने विधानसभा चुनाव की तर्ज़ पर भले ही अपेक्षित सफलता हासिल नहीं की, लेकिन उसके वोट बैंक पर असर पड़ता दिखाई नहीं दिया. बसपा के पास केवल एक ही चेहरा है और वह ख़ुद मुख्यमंत्री मायावती हैं, जो फिलहाल क़ामयाब हैं. अब माया से अल्पसंख्यकों को आजम ख़ान दूर कर सकेंगे, इतनी कूव्वत उनमें तो नहीं दिखती. पिछले चुनावी अनुभव भी यही बताते हैं.

हाईकोर्ट के आदेश और शासनादेश के अनुपालन में दो वर्ष के अंदर प्रदेश के कई ज़िलों में मस्टर रोल पर काम करने वाले 120 कर्मचारियों को नियमित भी किया जा चुका है लेकिन 1100 कर्मचारियों को छोड़ दिया गया.

जिन ज़िलों में प्रत्याशियों के निर्विरोध निर्वाचन की संभावना प्रबल होती दिख रही है, वे ज़िले हैं, मेरठ, बुलंदशहर, बिजनौर, ज्योतिबाफुले नगर, काशीरामनगर, हमीरपुर, कौशांबी, उन्नाव, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोरखपुर, कुशीनगर, महोबा और गौतमबुद्ध नगर.

पक्की नौकरी का चुनावी दांव

फोटो-प्रभात पाण्डेय

उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव समय से पहले हो सकते हैं. समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस व अन्य विरोधी दल यह संभावना जाहिर कर रहे हैं. इन दलों का यह पूर्वाभास अनायास नहीं है. राज्य में बहुजन समाज पार्टी की सरकार जिस तरह के लोक लुभावने निर्णय ले रही है, उसी की प्रतिक्रिया है कि विरोधी दलों को विधानसभा चुनाव की पदचाप सुनाई दे रही है. ऐसी ही एक सरकारी कोशिश दैनिक वेतन भोगी और अस्थाई कर्मचारियों को नियमित करने का तोहफ़ा देने की है. सरकार के इस निर्णय से क़रीब 30 हज़ार कर्मचारी लाभान्वित होंगे. बसपा सरकार को लगता है कि ऐसा करके वह सरकारी कर्मचारियों का दिल जीत लेगी लेकिन सरकार के इस निर्णय में नौकरशाही बाधक बनती दिख रही है. वजह राज्य सरकार ने सितंबर माह में निर्णय लिया था कि वर्ष 1991 से पहले प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी और अस्थाई कर्मचारियों को स्थाई किया जाएगा. इस फ़ैसले से राज्य सरकार पर 80 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष का अतिरिक्त आर्थिक बोझ भी पड़ेगा. इन अस्थाई कर्मचारियों को नियमित करने के लिए अतिरिक्त पदों का सृजन करने की पहल भी की गई. सरकार के इस निर्णय से विरोधी दलों में खलबली है और वह इसे चुनावी लाभ लेने की बसपा की मुहिम का हिस्सा मान रहे हैं. वर्षों से अपनी मांग पूरी होने का इंतजार कर रहे इन कर्मचारियों में उन मंत्रियों-विधायकों और सरकारी अफसरों के प्रति नाराज़गी भी है जो हर सुविधा का भोग करना तो अपना हक़ समझते हैं लेकिन कर्मचारियों के साथ इंसाफ़ करने की जहमत नहीं उठाते. वर्षों से मस्टर रोल पर काम करने वाले इन कर्मचारियों को अभी तक नियमित नहीं किया गया है जबकि इसके लिए शासनादेश तक जारी हो चुका है. शासनादेश में साफ़ कहा गया है कि यदि किसी भी दैनिक मस्टर रोल पर कर्मचारी को सेवा करते हुए तीन माह व्यतीत हो चुके हैं और उसके पास निर्धारित शैक्षिक तथा तकनीकी योग्यता है तो उन्हें वर्कचार्ज में कर दिया जाए. हाईकोर्ट भी इन कर्मचारियों की मांगों को जायज ठहरा चुका है. आरोप है कि इन कर्मचारियों को नियमित करने के एवज में रिश्वत के तौर पर भारी रक़म की मांग हो रही है. महीने भर की मेहनत मजदूरी करने के बाद इन कर्मचारियों के हाथ में बमुश्किल चार हज़ार रुपए भी नहीं आते हैं. ऐसे में वह अधिकारियों के आगे लाखों रुपए की रिश्वत का नज़राना कैसे पेश करें, यह व्यवस्था के लिए शर्मनाक पहलू है.

हाईकोर्ट के आदेश और शासनादेश के अनुपालन में दो वर्ष के अंदर प्रदेश के कई ज़िलों में मस्टर रोल पर काम करने वाले 120 कर्मचारियों को नियमित भी किया जा चुका है लेकिन 1100 कर्मचारियों को छोड़ दिया गया, उसी शासनादेश और हाईकोर्ट का आदेश होने के बावजूद. रिश्वत के लिए अधिकारियों ने मुख्यमंत्री, राज्यपाल और मंत्रियों की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ किया है. इसे सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करना ही तो कहा जाएगा कि शासन सत्ता की यह शीर्ष हस्तियां जिन आलीशान आवासों में रहती हैं, उनकी देखभाल करने वालों को ही अपने हक़ से वंचित रहना पड़ रहा है. बावजूद इसके ये कर्मचारी अपने काम से मुंह नहीं मोड़ रहे हैं. राजधानी लखनऊ में कालीदास मार्ग स्थित मंत्री आवास, उप मंत्री आवास, नया मंत्री आवास, वीडी मार्ग, बटलर पैलेस कॉलोनी, सचिवालय कॉलोनी, महानगर, इंदिरा नगर कॉलोनी, डायमंड डेरी कॉलोनी, हैवलक रोड कॉलोनी, दिलकुशा कॉलोनी, बादशाह नगर कॉलोनी, गुलिस्तां कॉलोनी, विष्णुपुरी कॉलोनी, निरालानगर कॉलोनी, अलीगंज कॉलोनी, मोतीझील कॉलोनी समेत कई अन्य सरकारी कॉलोनियां हैं, जिनकी देखभाल का जिम्मा मस्टर रोल पर काम करने वाले ये कर्मचारी उठा रहे हैं. इन मंत्रियों और विधायकों के फ्लैटों में जब बिजली या पानी की आपूर्ति में कोई दिक्कत आती है तो वह दिन-रात किसी भी वक्त इन कर्मचारियों की सेवा लेने से तनिक संकोच नहीं करते लेकिन जब इन्हें इनका हक़ दिलाने की बारी आती है तो सभी मुंह फेर लेते हैं. ख़ुद को नियमित कराने के लिए ये कर्मचारी सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता से लेकर अन्य अफसरों को सैकड़ों ज्ञापन दे चुके हैं. जिन पर संबंधित अधिकारी अपनी टिप्पणियां भी दर्ज़ करते हैं लेकिन उन्हें नियमित करने का आदेश जारी करने के लिए रुपयों की मांग कर डालते हैं जिसे पूरी करने में ये कर्मचारी असमर्थ हैं. इन कर्मचारियों को उम्मीद की एक किरण मई माह में राज्य सलाहकार परिषद के अध्यक्ष सतीश चंद्र मिश्र की अध्यक्षता में हुई एक बैठक के निर्णयों से दिखाई दी थी. इसमें फ़ैसला लिया गया कि जो कर्मचारी वर्षों से दैनिक वेतन या संविदा पर काम कर रहे हैं, उनकी कट ऑफ डेट तय करके नियमित किया जाएगा. जिन कर्मचारियों का निलंबन छह महीने से अधिक हो गया है, उन्हें बहाल किया जाएगा. उस समय बैठक के इस निर्णय पर मुख्य सचिव प्रशांत कुमार मिश्र, प्रमुख सचिव वित्त वीके शर्मा, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री शैलेश कृष्ण, प्रमुख सचिव गृह कुंवर फतेह बहादुर समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भी अपनी मुहर लगाई. तब से लेकर अब तक ये कर्मचारी फ़ैसले पर अमल होने की राह ही देख रहे हैं. इससे पहले दस मई, 2002 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भी अपने एक महत्वपूर्ण फ़ैसले में यह व्यवस्था दी थी कि दस वर्ष तक सरकारी सेवा में रह चुके अस्थाई एवं नियमित सरकारी कर्मचारियों को भी पेंशन पाने का अधिकार है. यह निर्णय न्यायमूर्ति एस एन श्रीवास्तव व राजेंद्र सिंह की याचिका पर दिया था. न्यायमूर्ति श्रीवास्तव ने यह निर्णय न्यायिक नज़ीर और एक जुलाई, 1989 को जारी शासनादेश का हवाला देते हुए दिया. इस शासनादेश में कहा गया है कि दस वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर चुके सरकारी सेवकों को सेवानिवृत्त होने अथवा सक्षम चिकित्साधिकारी द्वारा आगे सेवा करने में पूर्णतया अक्षम घोषित करने पर अधिवर्षता व असमर्थता पेंशन, सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी तथा पारिवारिक पेंशन उसी तरह व उन्हीं दरों पर मिलेगी जैसे स्थाई कर्मचारियों को उन्हीं परिस्थितियों में संगत नियमों के अंतर्गत अनुमन्य होती है. ऐसे कई शासनादेश जारी हुए लेकिन रिश्वत नहीं मिलने से वह सभी बेकार साबित हो रहे हैं. तकनीकी योग्यता रखने के बावजूद ये कर्मचारी सालों से अस्थाई नौकरी में हैं. इनके लिए नियमित नौकरी तो अब एक ख़्वाब बन कर रह गई है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

प्रक्रिया पूरी होते ही नियमित होंगे कर्मचारी : टी. राम

लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर इन चीफ और विभागाध्यक्ष त्रिभुवन राम के अनुसार नौ सितंबर को जारी शासनादेश के मुताबिक़ विभाग में कार्यरत मस्टररोल व दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी तभी नियमित होंगे जबकि अधिसंख्य पद स्वीकृत होंगे. इसकी प्रक्रिया पूरी की जा रही है. उन्होंने जानकारी दी कि प्रदेश के 72 ज़िलों में उनके विभाग में संबंधित कर्मचारियों के 82 संवर्ग हैं. इन सभी कर्मचारियों की उनके संवर्गवार सूचना मंगा ली गई है जिसे सूचीबद्ध किया जा रहा है ताकि किसी भी कर्मचारी का नाम छूटने न पाए. इसमें यह भी देखा जा रहा है कि संबंधित कर्मचारी कहां तैनात है, उसे वेतन कहां से मिल रहा है, वेतन का भुगतान कैसे किया जा रहा है. साथ ही अन्य जानकारी एकत्रित की जा रही है. टी. राम के मुताबिक़ यह केवल लखनऊ के कर्मचारियों का मामला ही नहीं है बल्कि पूरे प्रदेश में ऐसे सैकड़ों कर्मचारी हैं. इन सभी के मामलों को सूचीबद्ध करने के बाद अधिसंख्य पदों को स्वीकृत करने का काम शासन स्तर से कराया जाएगा. इंजीनियर इन चीफ ने उम्मीद जाहिर की कि शासन की मंशा के अनुरूप नवंबर माह के अंत तक सभी कर्मचारियों को नियमित कर दिया जाएगा.

पहाड़ पर सियासत का मैदान

सभी फोटो-प्रभात पाण्डेय

बीएल जोशी, मार्गरेट अल्वा, डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक, एनडी तिवारी

दस साल का उत्तराखंड और पांच मुख्यमंत्री. न कोई शिक्षा नीति, न ही स्वास्थ्य नीति. न ही अन्य किसी सरकारी विभाग की ख़ुद की नीति. प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता लेकिन राजनीतिक परिपक्वता का अभाव. राज्य गठन के साथ देखे गए सपने अभी भी आंखों में बसे हैं. पर सपने सच भी कैसे हों, उत्तराखंड में जिस किसी भी दल की सरकार रही हो, उसका मुखिया अपनी कुर्सी बचाने में व्यस्त रहता है. रह जाते हैं मंत्री और वह सीएम की कुर्सी तक पहुंचने का षड्यंत्र रचने में लगे रहते हैं. विकास की योजनाएं फाइलों में कैद होकर रह जाती हैं. सच यही है जो देखने और सुनने में काफ़ी कड़वा लगता है. राजनीतिक अस्थिरता ने भ्रष्टाचार को भी ख़ूब बढ़ावा दिया है. जल, जंगल और ज़मीन पर हक़ की लड़ाई के साथ उत्तराखंड आंदोलन शुरू हुआ था. पहाड़ पूरी तरह से सशक्त हो. उत्तराखंड अलग राज्य गठित हुए दस साल बीत जाने के बाद भी प्रकृति के इन संसाधनों का भरपूर इस्तेमाल नहीं हो सका है. नतीजा राज्य में बेरोज़गारी बढ़ रही है. मानव शक्ति का पलायन दूसरे राज्यों में हो रहा है. घपले-घोटालों ने राज्य का नाम कलंकित कर रहा है. ऊर्जा प्रदेश होने के बावजूद राज्य में अंधेरा है और फिर भी सत्ताधारी दल यह कहने से संकोच नहीं करता कि यहां ऑल इज वेल है.

उत्तराखंड की इस बदहाली और दुर्दशा के लिए भाजपा और कांग्रेस के साथ ही उत्तराखंड नामधारी विभिन्न दल भी उतने ही जिम्मेदार हैं. किसी भी नए राज्य के गठन के साथ वहां विकास के नाम की लूटखसोट कोई नई बात नहीं है. उत्तराखंड के साथ ही जन्मे झारखंड ने इस मामले में तो सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए हैं. लेकिन इतने भर से संतोष नहीं किया जा सकता है. राज्य में सबसे पहले भाजपा की अंतरिम सरकार का गठन हुआ और उसके मुखिया की कमान नित्यानंद स्वामी को सौंपी गई. मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के साथ ही नित्यानंद की उल्टी गिनती शुरू हो गई. अलग राज्य गठन होने से केंद्र से करोड़ों की राशि मिली थी. इस धन से विकास के कार्य शुरू किए गए जिसे नेताओं, नौकरशाहों और दलालों के गिरोह ने लूट लिया. यह सिलसिला आज तक अनवरत जारी है. इस दौरान अगर कुछ बदला है तो केवल मुख्यमंत्री और राज्यपाल. दस सालों में उत्तराखंड ने नित्यानंद स्वामी, भगत सिंह कोश्यारी, नारायण दत्त तिवारी, भुवन चंद खंडूरी और रमेश पोखरियाल निशंक को मुख्यमंत्री के रूप में देखा. वहीं चार राज्यपालों सुरजीत सिंह बरनाला, सुदर्शन अग्रवाल, बीएल जोशी और मार्गरेट अल्वा को भी देखा. राज्यपाल और मुख्यमंत्री तो बदलते रहे लेकिन राज्य की तक़दीर और तस्वीर न बदल सकी.

देवभूमि की बदहाल तस्वीर जल, जंगल और ज़मीन के अधूरे मॉडल से ही साफ़ हो जाती है. पानी उत्तराखंड की प्रकृति प्रदत्त अनमोल उपहार है. इसके बावजूद राज्य की कृषि भूमि का अधिकांश हिस्सा असिंचित है. मसलन पर्वतीय क्षेत्र की केवल चार प्रतिशत कृषि भूमि और घाटी की महज छह प्रतिशत कृषि भूमि ही सिंचित है. समूचे उत्तराखंड में सिंचित कृषि भूमि का औसत महज 14 प्रतिशत है जो राज्य में विकास के सूखे की तस्वीर ही दिखाता है. ऊर्जा प्रदेश के नाम से प्रसिद्ध उत्तराखंड में बिजली का उत्पादन भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है. जल विद्युत परियोजनाओं में घपलेबाज़ी का शोर दिल्ली तक सुनाई दे चुका है. राज्य की नदियां निजी कंपनियों को दी जाती रहीं. नतीजा जल विद्युत परियोजनाएं जन विरोध का शिकार होकर रह गईं. जंगलों को काटकर बेशक़ीमती लकड़ियों का उपयोग शानोशौकत दिखाने में किया जा रहा है. जंगल ख़त्म हो रहे हैं नतीजा वन्य जीव शहर की ओर भाग रहे हैं. इससे प्रकृति का संतुलन ही ख़तरे में पड़ गया है. पहाड़ के वाशिंदे आज भी पुराने भू-क़ानून की मार सह रहे हैं. हास्यापद स्थिति यह है कि उत्तराखंड राज्य तो एक है लेकिन भू-क़ानून दो तरह के हैं. इसी का नतीजा है कि अनिवार्य चकबंदी आज तक नहीं हो सकी है. पर्याप्त भूमि मौजूद होने के बाद भी आपदा पीड़ितों को ज़मीन मुहैया नहीं कराई जा सकी है तो इसकी वजह भू-क़ानून ही है. तराई के इलाक़े में जनजातियों की ज़मीनों पर भू-माफियाओं और दबंगों ने क़ब्ज़ा कर रखा है. हरिद्वार से लेकर रामनगर तक वनभूमि पर बसे खत्तों को आज तक राजस्व गांव का दर्ज़ा नहीं दिया जा सका है.

उत्तराखंड की इस बदहाल तस्वीर का मूल कारण राजनीतिक अस्थिरता और भ्रष्टाचार ही है. हाल ही में बाबा रामदेव राज्य के एक मंत्री पर उनसे रिश्वत मांगने का आरोप लगाकर इस सच्चाई को उजागर कर चुके हैं. बाबा के आरोपों से अगर कोई सबसे तिलमिलाया है तो वह पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी हैं. भ्रष्टाचार के मामले में कांग्रेस और भाजपा की हालत यह है कि जब कांग्रेस की सरकार आती है तो भाजपा उस पर आरोपों की बौछार करती है और जब भाजपा की सरकार रहती है तो कांग्रेस पलटवार करती है.

उत्तराखंड की इस बदहाल तस्वीर का मूल कारण राजनीतिक अस्थिरता और भ्रष्टाचार ही है. हाल ही में बाबा रामदेव राज्य के एक मंत्री पर उनसे रिश्वत मांगने का आरोप लगाकर इस सच्चाई को उजागर कर चुके हैं. बाबा के आरोपों से अगर कोई सबसे तिलमिलाया है तो वह पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद खंडुरी हैं. भ्रष्टाचार के मामले में कांग्रेस और भाजपा की हालत यह है कि जब कांग्रेस की सरकार आती है तो भाजपा उस पर आरोपों की बौछार करती है और जब भाजपा की सरकार रहती है तो कांग्रेस पलटवार करती है. इन आरोप-प्रत्यारोपों के बीच भ्रष्टाचार का धंधा अनवरत जारी रहता है. ताजा उदाहरण वर्ष 2007 के चुनाव का है. सत्ता हासिल करने के लिए भाजपा ने कांग्रेस सरकार पर 56 घोटालों के आरोप लगाए. जनता ने भाजपा को सत्ता सौंपी लेकिन अब भाजपा कांग्रेस के शासनकाल के इन घोटालों को भूल चुकी है. मतदाता यह नहीं समझ पा रहे हैं कि कांग्रेस सही थी या फिर भाजपा ने उनके साथ ग़लतबयानी की. वर्ष 2012 में विधानसभा चुनाव होना है. ऐसे में सत्ता हासिल करने और उसे बचाए रखने की कांग्रेस और भाजपा की होड़ एक बार फिर से शुरू हो चुकी है. कांग्रेस ने भाजपा पर ज़मीन घोटाले, जल विद्युत परियोजनाओं में घोटाले समेत कई आरोप लगाए हैं. पूर्व के घटनाक्रम को देखते हुए मतदाताओं को लग रहा है कि कहीं इस बार भी उनके साथ छल तो नहीं किया जा रहा है. यह राज्य में निराशा के माहौल को ही उजागर करता है.

सुरजीत सिंह बरनाला

भुवनचंड खंडुरी

इन सबके बीच मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक दावा करते हैं कि राज्य में उद्योगों के साथ रोजगार के अवसर बढ़े हैं. दो लाख लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर से रोजगार मिला है. अलग राज्य गठन के बाद से पिछले दस सालों में चालीस हज़ार लोगों को सरकारी नौकरी मिली है. अपनी बात में दम भरने के लिए निशंक प्रति व्यक्ति सालाना आय का जिक्र करना नहीं भूलते. वह कहते हैं कि अलग राज्य गठन के समय उत्तराखंड में प्रति व्यक्ति औसत आय 14,300 रुपए सालाना थी जो दस सालों में बढ़कर 42 हज़ार रुपए सालाना पहुंच गई है. राज्य योजना का आकार दस साल पहले 670 करोड़ रुपए था जो अब 6800 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है. जब अलग राज्य मिला था, उस दौरान विकास की दर 2.9 प्रतिशत पर थी. आज विकास की दर बढ़कर 9.4 प्रतिशत हो चुकी है जो राष्ट्रीय स्तर से अधिक है. आंकड़ों संबंधित निशंक के यह दावे अपनी जगह सही हैं लेकिन इन सबके बीच यह सवाल अहम हो जाता है कि अगर विकास हो रहा है तो पहाड़ के बेटों के हाथ क्यों खाली हैं. उन्हें दूसरे राज्यों के लिए पलायन क्यों करना पड़ रहा है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

नीरा की गिरफ़्तारी के मायने

आडवाणी के रिश्तेदार को भी मिला था प्लॉट

नोएडा प्लाट आवंटन मामले को शुरू से ही दबाने का प्रयास किया गया. वजह इसमें कई राजनीतिज्ञों और उनके रिश्तेदारों ने भी लाभ हासिल किया था. सीबीआई ने जब मामले की जांच शुरू की, उस समय तत्कालीन राज्यपाल मोतीलाल वोरा ने कहा कि वह इस मामले को राज्य सतर्कता आयोग को सौंपेंगे. उस दौर के मुख्य सचिव माता प्रसाद पांडेय ने मामले की फाइल को आगे नहीं बढ़ने दिया. सीबीआई के सूत्रों के मुताबिक़ माता प्रसाद के बेटे और भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी के एक रिश्तेदार को इसका लाभ मिला था. वरिष्ठ नौकरशाह सुरेंद्र सिंह, पूर्व कैबिनेट सचिव टीएसआर सुब्रहमण्यम भी प्लॉट लेने वाले लोगों में शामिल थे. ग़ौर करने वाली बात यह है कि नोएडा में प्लॉट लेने के लिए पान बीड़ी की दुकान व जूस पार्लर चलाने का प्रमाण पत्र तक पेश किया गया. ख़ुद नीरा यादव ने चार प्लॉट लिए. इनमें दो बेटियों के लिए और एक पति के नाम पर लिया गया. नीरा यादव को तो सज़ा हो गई लेकिन एक सवाल अभी भी न्याय के गलियारे में तैर रहा है कि प्लॉट का लाभ लेने वाले राजनीतिकों और उनके रिश्तेदारों को कब जेल भेजा जाएगा.

वादे हैं वादों का क्या

वो कौन सी वजहें थीं जिनके चलते नीरा यादव ने अपने रिटायरमेंट से तीन महीने पहले ही वीआरएस ले लिया था. सत्ता के गलियारों में तमाम शिगूफ़े चले. कहा गया कि मुख्यमंत्री के इशारे पर पंचम तल पर बैठे एक शीर्ष अधिकारी ने नीरा यादव को वीआरएस लेने और आईएएस एसोसिएशन के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने पर मजबूर किया था. लेकिन इस वायदे के साथ कि नीरा के ख़िलाफ़ तमाम मामले ठंडे बस्ते में डाल दिए जाएंगे. वीआरएस लेने के बाद वे तमाम उम्र चैन से रह पाएंगी. लेकिन नीरा यादव को वे वायदे जेल में याद आ रहे होंगे.

देश भर में जब टू जी स्पेक्ट्रम घोटाले को लेकर हंगामा मचा है. संसद में कामकाज ठप्प होने का रिकॉर्ड बन रहा है. प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह लाचारी का लबादा ओढ़े हैं. पूर्व दूरसंचार मंत्री ए. राजा बेशर्मी भरी मुस्कान बिखेर रहे हैं और भ्रष्टाचार के मसले पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी हाथ बांधे खड़ी हैं. इस माहौल में नीरा यादव को चार साल की कैद सुगबुगाहट पैदा नहीं करती है. वह भी उस माहौल में जबकि भ्रष्टाचार न्यायपालिका में भी गहराई तक जड़ें जमा चुका है. पीएफ घोटाले ने माननीय न्यायाधीशों के दामन पर भी दाग़ छोड़े हैं. उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्य सचिव नीरा यादव एकमात्र ऐसी अधिकारी नहीं हैं जिन्हें भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते जेल जाना पड़ा है. उत्तर प्रदेश के ही एक और पूर्व मुख्य सचिव अखंड प्रताप सिंह पर भी भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लग चुके हैं. अखंड प्रताप सिंह को भी जेल जाना पड़ा था. फिलहाल वह जमानत पर जेल से रिहा हो चुके हैं. नीरा यादव और अखंड प्रताप सिंह में एक बात कॉमन है, वह यह कि इन दोनों को मुलायम सिंह यादव ने ही मुख्य सचिव बनाया था. वर्ष 1997 में उत्तर प्रदेश के आईएएस अफसरों ने मतदान के जरिए जिन तीन महाभ्रष्ट अफसरों को चुना था, उनमें अखंड प्रताप सिंह, बृजेंद्र यादव और नीरा यादव ही शामिल थे.

नीरा यादव को चार साल की कैद भाजपा के लिए भी मुश्किलें बढ़ाने वाली है. टू जी स्पेक्ट्रम घोटाले में भाजपा भले ही केंद्र सरकार को घेरने में सफ़ल हो गई है लेकिन नीरा यादव के मामले में पासा उलटा पड़ सकता है. सर्वविदित है कि 1971 बैच की आईएएस अधिकारी नीरा यादव के पति पूर्व आईपीएस महेंद्र यादव हैं जो राजनीतिज्ञ भी हैं. महेंद्र यादव अभी रालोद के राष्ट्रीय महासचिव हैं. प्रदेश में जब भाजपा-बसपा गठबंधन की सरकार थी, उस समय महेंद्र यादव माध्यमिक शिक्षा मंत्री थे और नीरा यादव उसी विभाग की प्रमुख सचिव भी रहीं. भाजपा सरकार में कल्याण सिंह के मुख्यमंत्री रहते हुए नीरा यादव पर भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लगे लेकिन कल्याण सरकार चुप्पी साधे रही. अब अदालत का फ़ैसला आने के बाद कांग्रेस को भाजपा पर निशाना साधने का मौक़ा मिल गया है. कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता प्रमोद तिवारी कहते हैं कि नीरा यादव और उनके पति भाजपा से जुड़े रहे हैं. अगर भाजपा को घपले-घोटाले ही देखने हैं तो पहले उसे अपने गिरेबान में झांकना चाहिए.

नीरा को मुख्य सचिव बनाने के लिए 1970 बैच के रवि माथुर और शंभुनाथ को भी नज़रअंदाज़ किया गया था. नीरा यादव के ख़िलाफ़ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला था. सीबीआई यह संपत्ति तीन सौ करोड़ रुपए से अधिक की बता रही है.

प्रमोद तिवारी अब भले ही भाजपा को नसीहत दे रहे हैं लेकिन नीरा यादव कांग्रेसी नेताओं की भी प्रिय रही हैं. वीरबहादुर सिंह ने भी नीरा यादव को ख़ास तवज्जो दी, भाजपा ने उनके पति को मंत्री बनाया तो सपा ने ख़ुद नीरा यादव को मुख्य सचिव के ओहदे से नवाजा. नीरा को मुख्य सचिव बनाने के लिए 1970 बैच के रवि माथुर और शंभुनाथ को भी नज़रअंदाज़ किया गया था. नीरा यादव के ख़िलाफ़ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला था. सीबीआई यह संपत्ति तीन सौ करोड़ रुपए से अधिक की बता रही है. सीबीआई के तत्कालीन निदेशक विजय रामाराव ने कैबिनेट सचिव और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को पत्र भेजकर जानकारी दी थी कि नीरा ने नोएडा के सीईओ तथा अध्यक्ष के पद पर रहते हुए अपने पद का दुरुपयोग किया. करोड़ों की ज़मीन अपने रिश्तेदारों को आवंटित की. तत्कालीन राज्यपाल रोमेश भंडारी ने इस मामले की जांच के लिए 1997 में जस्टिस मुर्तजा हुसैन की अध्यक्षता में कमेटी बनाई थी. कमेटी ने पाया कि नीरा ने न केवल अपना प्लॉट सेक्टर 32 से सेक्टर 14-ए में कराया बल्कि घर बनवाने के लिए तमाम नियमों को ताक पर रखा. इस रिपोर्ट पर कल्याण सरकार ने चुप्पी साधे रखी. सीबीआई ने नीरा पर सात मामलों में मुक़दमा चलाने की सिफ़ारिश की थी लेकिन राज्य सरकार ने यह कहकर अनुमति देने से इनकार कर दिया कि औचित्य ही नहीं बनता है. बाद में सुप्रीमकोर्ट के हस्तक्षेप पर सीबीआई अपनी कार्रवाई आगे बढ़ा सकी थी.

उत्तर प्रदेश के दाग़दार अफसरों में अखंड प्रताप सिंह और नीरा यादव ही दो चेहरे नहीं हैं बल्कि दाग़ी चेहरों और नामों की यह लिस्ट काफ़ी लंबी है. नोएडा भूमि आवंटन के एक अन्य मामले में आईएएस राकेश बहादुर, संजीव सरन, रवींद्र के नायर और देवदत्त आरोपी हैं. सीबीआई इन चारों के ख़िलाफ़ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है. इनके अलावा 15 अधिकारी इसी मामले में निलंबित किए जा चुके हैं. खाद्यान्न घोटाले में मेरठ विकास प्राधिकरण के वित्त नियंत्रक सत्येंद्र सिंह गंगवार समेत नौ लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है. ईओडब्लू और खाद्य सेल ने आठ मामले दर्ज़ कर 175 लोगों को नामजद किया है. सूचना विभाग में भर्ती प्रकरण में सीबीआई ने आईएएस अधिकारी महेश गुप्ता के ख़िलाफ़ भी चार्जशीट दाखिल की थी. दो आईएएस भाइयों अभिनव चंद्रा और अभिषेक चंद्रा के ख़िलाफ़ जाली सर्टिफिकेट लगाने का मामला चल चुका है. यह दोनों ही उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और फिलहाल दूसरे राज्यों में तैनात हैं. सतर्कता अधिष्ठान में पुस्तक घोटाला, विशिष्ट बीटीसी घोटाला, उत्तर प्रदेश निर्यात निगम घोटाला, यूपीएसआईडीसी में सस्ते दामों पर ज़मीन घोटाला, जेल बंदीरक्षक भर्ती घोटाला, वन विभाग में तेंदु पत्ता घोटाला व अन्य तमाम घोटालों के केस दर्ज़ होने के बाद वे मामले फाइलों में दबकर रह गए. सरकारी ख़जाने पर कुंडली मारकर बैठे नौकरशाही-नेता गठजोड़ में नीरा यादव की गिरफ्तारी के बाद डर ज़रूर बैठा है लेकिन यह कितने दिनों तक कायम रहेगा, यह कहना मुश्किल है. वजह अखंड प्रताप सिंह को जेल ज़रूर हुई लेकिन वह जमानत पर रिहा होकर मजे कर रहे हैं. नीरा यादव भी जेल की सलाखों के पीछे कितने दिनों तक रह पाएंगी, यह सभी जानते हैं. उन्हें भी जमानत मिलनी ही है. जमानत का यही रास्ता भ्रष्टाचारियों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, जिसे रोकने की ज़रूरत है.

फोटो-पीटीआई

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव

आतंक में जनादेश

अरविंद जयतिलक

लोकतंत्र की तबाही का मंजर और जनादेश के साथ भद्दा मजाक अगर देखना हो तो उत्तर प्रदेश का पंचायत चुनाव इसकी सबसे बड़ी बानगी साबित हो सकती है. उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव के दरम्यान जो धनबल और बाहुबल का घिनौना खेल देखा गया सो तो है ही, बाद का खेल और भी हैरान और अचंभित करने वाला है. उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में कुछ ऐसा ही हुआ. जनादेश पर सत्ता की फौज के सहारे किस तरह राजनीतिक डकैती डाली जाती है और जनादेश के मंतव्य को कैसे सत्तातंत्र की धमकाऊ भाषा और शक्ति के घालमेल से अपने अनुकूल व्याख्यायित और रूपांतरित किया जाता है, उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव से बेहतर इसका और कोई उदाहरण नहीं हो सकता है. अभी तक तो चुनावों में निर्वाचित प्रत्याशियों को डराने-धमकाने और ख़रीद फरोख्त की ही बात सुनने में आती थी लेकिन इस बार पंचायत चुनाव में सियासत की व्यूहरचना कुछ इस अंदाज़ में रची गई है कि चित्त भी अपनी और पट भी अपनी. यानी सत्तातंत्र द्वारा लोकतंत्र को रौंदने और लूटने के मकसद से बनाई गई कार्ययोजना कई किश्तों में तैयार की गई और उसे सत्ता पराक्रम द्वारा सधे हुए क़दमों से अंजाम भी दिया जा रहा है. यह किसी से छिपा नहीं है कि 2012 में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र तक़रीबन सभी बड़े राजनीतिक दलों ने पंचायत चुनावों में अपना प्रत्याशी नहीं उतारने का फ़ैसला किया था और उन्होंने तदनुसार ऐसा किया भी. शायद उन्हें इस बात का डर सता रहा था कि कहीं पंचायत चुनाव में उनके दलीय प्रत्याशी गोते लगा गए तो उसका असर मिशन 2012 के विधानसभा चुनाव पर पड़ना तय है. बड़े पैमाने पर होने वाले सियासी नुक़सान से बचने के लिए राजनीतिक दलों ने पंचायत चुनाव को दूर से ही समझना ज़्यादा मुनासिब समझा. पंचायत चुनाव के नतीजे का ऊंट किस करवट बैठेगा इसका सही आकलन न कर पाने की वजह से सत्ताधारी बसपा से लेकर सपा, कांग्रेस और भाजपा ने भी अपना प्रत्याशी आधिकारिक तौर पर मैदान में नहीं उतारा. सपा, भाजपा और कांग्रेस की मजबूरी को तो समझा जा सकता है. लेकिन सत्तारूढ़ बसपा, जो प्रदेश में सुशासन की स्थापना और विकास करने की लगातार राग अलापती आ रही है, आखिर उसने अपना प्रत्याशी पंचायत चुनाव में क्यों नहीं उतारा? बेशक बसपा की यह रणनीति चुनाव परिणाम आने से पूर्व तक एक अनसुलझा प्रश्न था. लेकिन चुनाव परिणाम आने के बाद बसपा की रणनीति को आसानी से समझा जा सकता है. बसपा को यह अच्छी तरह मालूम था कि अगर वह पंचायत चुनाव में दल के आधार पर अपना प्रत्याशी उतारती तो उसे मुंह की खानी पड़ सकती थी. क्योंकि पत्थरों का संसार बसाने वाली साम्राज्ञी के रणनीतिकारों को ज़मीनी हक़ीक़त अच्छी तरह मालूम था. सरकार की ओर से विकास के दावे चाहे जो भी किए जाएं, लेकिन सच्चाई यही है कि आज उत्तर प्रदेश देश के अन्य राज्यों से लगातार पिछड़ता जा रहा है. जनता में सरकार के क्रियाकलापों को लेकर गहरा असंतोष व्याप्त है. ऐसे में बसपा का डरना और पंचायत चुनाव परिणाम का उसके ख़िलाफ़ होना स्वाभाविक था. लेकिन पंचायत चुनावों में अपना प्रत्याशी न उतारने वाली सत्तारूढ़ बहुजन समाज पार्टी अब चुनाव जीतने वाले प्रत्याशियों को न केवल अपना बता रही है बल्कि उनके सीने पर चढकर सत्तातंत्र की लाठी के जोर से उन्हें अपने पाले में खींचकर, पंचायतों के पदों पर काबिज़ होने की जुगत भी भिड़ाती देखी जा रही है. पंचायतों के माध्यम से लोकतंत्र को सत्ता की मुट्ठी में कैद रखने की इसे सबसे बड़ी साजिश भी करार दिया जा सकता है. अब तक का इतिहास तो यही बताता है कि इस राजनीतिक महाठगी के घिनौने खेल में जिसके पास सत्तारूपी लाठी होती है, भैंस वही हांक ले जाता है. लेकिन इस बार का खेल भैंस और लाठी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि लोकतंत्र को भी हांकने की पूरी तैयारी कर ली गई है. सत्तारूढ़ बसपा की तैयारी तो यही बता रही है कि वह अपने जोर से एक ऐसे नृपतंत्रात्मक लोकतंत्र की बुनियाद रखना चाहती है जिसकी संस्कृति सजदा और पायबोस पर टिकी है. याद होगा पंचायत चुनाव से पूर्व बसपा सुप्रीमो मायावती यही रट लगा रही थीं कि पंचायत चुनाव में उनकी पार्टी न तो अपना प्रत्याशी उतारेगी और न ही अपने पार्टी के सांसदों, विधायकों और पदाधिकारियों के सगे संबंधियों को चुनाव लड़ने की इजाजत देगी. उन्होंने यह भी ऐलान किया था कि अगर ऐसा जो भी पार्टी का काडर करेगा उसे पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा. लेकिन सत्ता साम्राज्ञी की इस उद्घोषणा में छिपे इरादे को कोई परख नहीं पाया. आम आदमी तो यह मानकर चल रहा था कि बसपा सुप्रीमो जो कहती हैं, वह करती भी हैं. लेकिन उनकी मनाही के बावजूद उनके सांसदों, विधायकों और पदाधिकारियों के सगे संबंधियों का चुनावी मैदान में उतरना आखिर क्या संदेश देता है? सच कहा जाए तो अब बसपा सुप्रीमो की जुबान भी एक साथ कई भाषा बोलने लगी है. शायद इसी का नतीजा रहा कि बसपा काडर के किरदार पंचायत चुनाव में ख़ूब भाग्य आजमाए और सत्ता की लाठी के सहारे लोकतंत्र की पीठ पर सवार भी हुए. चुनाव परिणाम पर नज़र दौड़ाइए तो बिसात पर जितने भी प्यादे अपना पर फैलाते नज़र आ रहे हैं उन्हें बसपा अपना बता रही है. इस राजनीतिक जय-विजय की विद्रूपता की कहानी के कथानक का ताना बाना किस तरह बुना गया है, इसी से समझा जा सकता है कि कल तक मुनादी पीटने वाली बसपा जो यह बताने से नहीं थक रही थी कि उसने पंचायत चुनाव में अपना एक भी प्रत्याशी नहीं उतारा है, आज वही भोंपू बजाती देखी जा रही है कि पंचायत चुनाव में उसका ही तिलिस्म चला है और उसके ही प्रत्याशी जंग जीतकर आए हैं. क्या इस गौरव गाथा पर सवाल खड़ा करना तर्कसंगत नहीं है? जब सत्ताधारी बसपा ने चुनाव के दरम्यान अपना प्रत्याशी ही नहीं उतारा तो अचानक पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के लिए मैदान में सामने आए प्रत्याशी उसके सदस्य कैसे हो गए? चुनाव के दरम्यान सत्ता के निकटस्थों द्वारा धनबल और बाहुबल का किस कदर प्रयोग किया गया और कितनी हत्याएं हुई यह किसी से छिपा नहीं है. इसे लोकतंत्र की त्रासदी ही कहा जाएगा कि पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव में उत्तर प्रदेश के जिन पंद्रह-सोलह ज़िलों में बसपा उम्मीदवारों का निर्विरोध चुना जाना लगभग तय बताया जा रहा है, उनमें अधिकांश बसपा के बड़े नेताओं की पत्नियां, भाई और निकट के सगे संबंधी हैं. लेकिन मजे वाली बात यह है कि चुनाव पूर्व इन्हीं प्रत्याशियों को आधिकारिक तौर पर बसपा ख़ुद अपना बताने से परहेज कर रही थी. इसीलिए कि वे अगर चुनाव में हार जाते हैं, तो कम से कम मुंह छिपाने लायक जगह बचेगी और वह कह सकेगी कि हारने वाले प्रत्याशी उनकी पार्टी के सदस्य नहीं हैं. लेकिन अब जब वे सत्तातंत्र की मेहरबानी से चुनाव जीत गये हैं तो बसपा को सब अपनी ही जागीर दिखने लगी है. निर्विरोध निर्वाचन में शुमार होने वाले इन माननीयों के बारे में भी जान लेना ज़रूरी है कि आखिर इनमें कौन ऐसे सुर्ख़ाब के पर लगे हैं कि इनके ख़िलाफ़ कोई मैदान में डटना तक गवारा नहीं समझ रहा है. इसलिए कि ये सत्ता के गलियारे से आते हैं. तंत्र इनकी जी हजूरी करता है और क़ानून इनके हिसाब से आगे-पीछे होता है. सबसे पहले बात बसपा के प्रदेश अध्यक्ष और सहकारिता मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के अपने ही भतीजे प्रमोद मौर्य की, भला इनके ख़िलाफ़ कोई चुनावी मैदान में कैसे उतर सकता है? मसलन वन मंत्री फतेहबहादुर सिंह की पत्नी साधना सिंह गोरखपुर से उम्मीदवार हैं और उनके ख़िलाफ़ कोई प्रत्याशी नहीं है. बसपा सांसद जयप्रकाश रावत की पत्नी ज्योति रावत के ख़िलाफ़ भी उन्नाव से कोई नहीं लड़ रहा है. इसी तरह से पूर्व सांसद रिजवान जहीर की पत्नी हुमा रिजवान, ज्योतिबाफुले नगर के बसपा ज़िलाध्यक्ष हेम सिंह आर्य की पत्नी कमलेश, विधानपरिषद सदस्य रामचंद्र प्रधान के भाई धर्मेंद्र और गौतमबुद्ध नगर के बसपा नेता की पत्नी भी मैदान में हैं. और इन तीसमारों के ख़िलाफ़ भी कोई प्रत्याशी मैदान में आने की हिम्मत नहीं जुटा रहा है. जिन ज़िलों में प्रत्याशियों के निर्विरोध निर्वाचन की संभावना प्रबल होती दिख रही है, वे ज़िले हैं, मेरठ, बुलंदशहर, बिजनौर, ज्योतिबाफुले नगर, काशीरामनगर, हमीरपुर, कौशांबी, उन्नाव, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोरखपुर, कुशीनगर, महोबा और गौतमबुद्ध नगर. अगर इन ज़िलों के सियासी तापक्रम का आकलन किया जाए तो यहां काफ़ी गर्माहट महसूस की जा सकती है. इन ज़िलों में सियायी बाहुबलियों द्वारा समानांतर सत्ता चलाने की भी बात यदा-कदा उठती रही है. ऐसे में समझा जा सकता है कि इनके ख़िलाफ़ चुनावी मैदान में कोई क्यों नहीं दिख रहा है? अब लाख टके का सवाल यह उठता है कि क्या इस प्रदेश में लोकतंत्र जिंदा बचा है? या सत्ता की धमनियों की गर्माहट से पिघलाकर उसका वजूद ही मिटा दिया गया है? तथाकथित बसपा प्रत्याशियों के ख़िलाफ़ मुक़ाबले में किसी का न होना साफ़ इंगित कर रहा है कि दाल में कुछ काला है. लोकतंत्र में निर्विरोध निर्वाचित होने का आखिर क्या मतलब होता है? क्या यह अपने आप में अटपटा नहीं लगता है कि जिस लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए ही पंचायती राज व्यवस्था का विधान बनाया गया, उसी लोकतंत्र की भावना को सत्ता के पैरों से रौंदकर एक विद्रूप लोकतंत्र की रचना की जा रही है. एक जिंदा लोकतंत्र और एक जिंदा कौम अगर निर्विरोध निर्वाचन को अपनाने के लिए बाध्य होती है तो यही माना जाएगा कि कहीं न कहीं उसकी गर्दन पर सत्ता की तलवार लटक रही है. तो फिर इस निर्विरोध निर्वाचन को अंजाम तक पहुंचाने की प्रक्रिया को, लोकतंत्र की जय कहने के बजाए यही माना जाएगा कि सब कुछ सत्तातंत्र की धौंस से चालित यह एक घटिया उपक्रम मात्र है? क्या किसी भी दृष्टिकोण से यह तर्क वाजिब दिख रहा है कि निर्विरोध निर्वाचित प्रत्याशियों का आभामंडल इतना व्यापक और सहज है कि लोकतंत्र की सारी मर्यादा उसी में समाहित हो जाएगी? और लोकतंत्र की सम्मानित जनता उनके आगे उसी तरह घिघियाती नज़र आएगी जैसे मध्यकालीन राजाओं के आगे नतमस्तक हो जाया करती थी. शायद लोकतंत्र को यही दिन देखना बाक़ी था.

feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया के उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड संस्करण के प्रकाशन पर अरुण आचार्य, संस्थापक, मां सरस्वती इंटर कॉलेज, कुसमरा महाविद्यालय, कुसमरा, मैनपुरी परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं

विशेषताएं :

1. विद्यालय का विशालकाय भवन एवं क्रीड़ास्थल.
2. विद्यालय का उद्देश्य बच्चों को संस्कारवान व सुसंस्कृत बनाना.
3. नवोदय, सैनिक, मिलिट्री स्कूलों में प्रवेश के लिए कोचिंग की उत्तम व्यवस्था है.
4. कला, विज्ञान एवं कॉमर्स वर्ग की मान्यता.
5. छात्र/छात्राओं के लिए शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास के लिए सांस्कृतिक गतिविधियां, गोष्ठियों का आयोजन.

केंद्र और राज्य सरकारें बराबर एक राग अलापती हैं कि जल, जंगल और ज़मीन पर आदिवासियों का हक़ है लेकिन यह बातें सुनने में ही अच्छी लगती हैं.

राजनीति की बिसात पर सोनभद्र

देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू सोनभद्र में स्विट्जरलैंड का अक्स देखते थे. नेहरू अपने जीवनकाल में सोनभद्र को स्विट्जरलैंड नहीं बना सके. उनके बाद देश ने कई प्रधानमंत्री देखे, उत्तर प्रदेश में कई दशकों तक कांग्रेस की सरकार भी रही लेकिन नेहरू का ख्वाब अधूरा ही रहा.

तारा चंद गुप्ता

उत्तर प्रदेश की राजनीतिक बिसात में सोनभद्र एक ऐसा मोहरा है जिसे खिलाड़ी (नेता) इस्तेमाल तो वजीर की तरह करते हैं लेकिन उसकी असल हैसियत प्यादे से भी नीचे है. सरकार के खजाने में सर्वाधिक राजस्व जमा करने का श्रेय सोनभद्र को जाता है. नेता और नौकरशाह अपनी तिजोरी भरने का काम भी इसी के जरिए करते हैं. इन सबके बीच अगर किसी का हक़ मारा जा रहा है तो वह यहां का आम आदमी है. इनमें आदिवासियों की स्थिति सर्वाधिक बदतर है. इन आदिवासियों का इस्तेमाल राजनीतिक दल अपने स्वार्थ के लिए करते हैं लेकिन जब हक़ देने की बारी आती है तो सबकुछ ख़ुद डकार जाते हैं. मसलन क्षेत्र में स्थापित वैध और अवैध सभी क्रशरों में से अधिकांश राजनीतिक दलों के नेताओं और उनके परिजनों के हैं. खनन के पट्टे पर भी नेता, नौकरशाह और खनन माफ़िया सांप की तरह कुंडली मारकर बैठे है. यही वजह है कि सोनभद्र में अवैध खनन के मसले पर सब चुप्पी साधे रहते हैं. तू भी खा मैं भी खाऊं की नीति लागू है.

सोनभद्र को लूटने के इरादे से नेताओं ने यहां की जनता को पढ़ाई-लिखाई से दूर रखने में ही अपनी भलाई समझी. साक्षरता के सरकारी आंकड़े नेताओं की इस साजिश का ख़ुलासा करते हैं. ज़िले की कुल आबादी 14,63,468 है जिसमें पुरुषों की संख्या 7,71,817 और महिलाएं 6,91,651 हैं. इस आबादी में महज 39.86 फ़ीसदी लोग ही साक्षर हैं. इनमें आधी आबादी यानि महिलाएं केवल 27.09 फ़ीसदी ही पढ़ी लिखी हैं. सोनभद्र को ऊर्जांचल भी कहा जाता है लेकिन यहां के 1426 गांवों में से आधे से अधिक गांवों में बिजली नहीं है. सोनभद्र में औद्योगिक इकाईयों की भरमार है लेकिन यहां का आम आदमी खाली पेट सोने के लिए मजबूर है. आदिवासियों का हक़ मारा जा रहा है. सोनभद्र उत्तर प्रदेश का अकेला जनपद है जहां सर्वाधिक आदिवासी हैं लेकिन यहां से एक भी आदिवासी विधायक नहीं है. राजनीतिक दलों ने एक सोची समझी साजिश के तहत आदिवासियों का विधानसभा में प्रतिनिधित्व छीन लिया. अब आदिवासी अपने हितों के लिए संघर्ष कर रहे हैं लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है. अभी सोनभद्र में दो विधानसभा सीटें दुद्धी और राबर्ट्सगंज के अलावा राजगढ़ का कुछ हिस्सा आता है. इनमें दुद्धी से सीएम प्रसाद और राबर्ट्सगंज से सत्य नारायण जैसल और राजगढ़ से अनिल मौर्या विधायक हैं. वर्ष 2004 से पहले सोनभद्र के आदिवासियों को जनजाति का दर्ज़ा नहीं मिला था और वह अनुसूचित जाति में आते थे. अनुसूचित जनजाति का दर्ज़ा मिलने के बाद से आदिवासियों को अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व सीट से चुनाव लड़ने के अधिकार से वंचित हो जाना पड़ा. नए परिसीमन में दुद्धी, ओबरा, राबर्ट्सगंज और घोरावल विधानसभा सीट गठित हुई हैं. इनमें भी आदिवासियों के लिए फिलहाल कोई सीट रिजर्व नहीं है. आदिवासी अपना हक़ पाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं है.

इस राजनीतिक लूट-खसोट का आलम यह है कि राबर्ट्सगंज नेहरू के सपनों का स्विट्जरलैंड नहीं बन सका. देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू सोनभद्र में स्विट्जरलैंड का अक्स देखते थे. नेहरू अपने जीवनकाल में सोनभद्र को स्विट्जरलैंड नहीं बना सके. उनके बाद देश ने कई प्रधानमंत्री देखे, उत्तर प्रदेश में कई दशकों तक कांग्रेस की सरकार भी रही लेकिन नेहरू का ख्वाब अधूरा ही रहा. ग़ैर-कांग्रेसी सरकारों के दौर में भी सोनभद्र की उपेक्षा ही हुई. सरकारी अदूरदर्शिता व उदासीनता का नतीजा है कि नेहरू का स्विट्जरलैंड आज नक्सललैंड व डेथलैंड बन चुका है. यहां की खदानें मजदूरों की कब्रगाह बन चुकी हैं. अंधाधुंध खनन ने प्राकृतिक संतुलन बिगाड़ कर रख दिया है. जिस नैसर्गिक सुंदरता पर फ़िदा होकर नेहरू ने सोनभद्र को स्विट्जरलैंड की उपमा दी थी, वह ख़त्म होने को है. अगर यह कहें कि नेता, नौकरशाह और खनन माफ़िया के गठजोड़ की मार से सोनभद्र कराह रहा है तो ग़लत न होगा.

केंद्र और राज्य सरकारें बराबर एक राग अलापती हैं कि जल, जंगल और ज़मीन पर आदिवासियों का हक़ है लेकिन यह बातें सुनने में ही अच्छी लगती हैं. सोनभद्र के संदर्भ में देखें तो यहां न तो जल न ही जंगल और न ही ज़मीन पर आदिवासियों को हक़ मिल सका है. और तो और आदिवासियों को सांस लेने के लिए शुद्ध हवा भी नहीं मिल पा रही है. अनियोजित औद्योगिकीकरण ने यहां की हवा में प्रदूषण का ज़हर घोल कर रख दिया है. हालात की गंभीरता देखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ अपने पर्यावरण कार्यक्रम से संबंधित रिपोर्ट में भी सोनभद्र के संदर्भ में चिंता जाहिर कर चुका है. फिर भी न सरकार चेत रही है और न ही स्थानीय प्रशासनिक अमला. प्रकृति के खजाने को लूट कर सभी ख़ुद को मालामाल करने में लगे हैं. सोनभद्र कभी मिर्जापुर का अभिन्न अंग हुआ करता था. चार मार्च, 1989 को इसे मिर्जापुर से अलग कर ज़िले का दर्ज़ा दिया गया. यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ज़िला है जिसका क्षेत्रफल क़रीब 7,388 वर्ग किलोमीटर है. क्षेत्रफल के साथ ही सोनभद्र इस मायने में भी ख़ास है कि इसकी सीमाएं चार राज्यों को छूती हैं. सोनभद्र की पश्चिम सीमा में मध्य प्रदेश, दक्षिण में छत्तीसगढ़, पूर्व में झारखंड और बिहार है. सोनभद्र की पहाड़ियों में चूना पत्थर और कोयला मिलने के साथ ही क्षेत्र में पानी की प्रचुरता होने से यह इलाक़ा उद्यमियों के आकर्षण का केंद्र बना लेकिन क्षेत्र की यह ख़ासियत ही इसके वजूद पर अब ख़तरा बनकर मंडरा रही है. अनियोजित औद्योगिक विकास ने क्षेत्र के पर्यावरण को बुरी तरह क्षति पहुंचाई है. संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण कार्यक्रम से संबंधित रिपोर्ट पर अगर ग़ौर करें तो पता लगेगा कि हालात कितने भयावह हो चुके हैं. इस रिपोर्ट में साफ़ तौर पर कहा गया है कि सोनभद्र-सिंगरौली इलाक़े में रहने वालों के ख़ून में पारे की मात्रा सामान्य से काफ़ी अधिक हो चुकी है. ऐसा होने से मनुष्य के गुर्दे, दिमाग, स्नायुतंत्र व शरीर के अन्य अंग काम करना बंद कर सकते हैं.

चिकित्सकीय भाषा में कहें तो पर्यावरणीय मानकों को ताक पर रखकर होने वाले औद्योगिकीकरण से सोनभद्र की जनता धीरे धीरे मौत की ओर बढ़ रही है. हालात पर शीघ्र ही काबू न पाया गया तो आने वाली नस्लें विकलांग पैदा हो सकती हैं. संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपनी रिपोर्ट में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के उस तथ्य का भी उल्लेख किया जिसमें तापीय परियोजनाओं से होने वाले मर्करी के कुल उत्सर्जन की 17 फ़ीसदी मात्रा के लिए ज़िले में स्थापित बिजली घरों को जिम्मेदार माना गया है. एक फ्रांसीसी कंपनी के अध्ययन में कहा गया है कि सोनभद्र-सिंगरौली क्षेत्र में स्थापित बिजलीघर प्रत्येक वर्ष 720 किलोग्राम पारे का उत्सर्जन कर रहे हैं. इसमें वर्ष 1997 में अदिवासियों की ओर से विश्व बैंक से की गई शिकायत का जिक्र भी है जिसमें तापीय परियोजनाओं के निर्माण में पर्यावरणीय हितों का ध्यान नहीं रखे जाने का आरोप लगाया गया था. दुखद पहलू यह भी है कि इन परियोजनाओं से न केवल प्रदूषण का संकट बढ़ रहा है बल्कि मजदूरों के हित भी मारे जा रहे हैं. सोनभद्र में तापीय विद्युत परियोजनाएं, एनसीएल की खदानें, हिंडाल्को, कानोरिया केमिकल्स, जेपी सीमेंट की फैक्टरी के अलावा लगभग साढ़े तीन सौ क्रशर प्लांट और बालू व पत्थर की एक हज़ार से अधिक खदानें हैं. इन खदानों में अब तक सैकड़ों मजदूरों की मौत हो चुकी है. सैकड़ो की संख्या में श्रमिक घायल हुए हैं लेकिन उन्हें उचित मुआवज़ा तक नहीं मिलता है. कुछ मजदूर संगठन अगर विरोध में आवाज़ बुलंद करते हैं तो उन्हें डरा धमका कर दबा दिया जाता है. खनन माफ़िया के आगे किसी का जोर नहीं चलता है. रिहंद बांध विश्व प्रसिद्ध है, उसी बांध का पानी रासायनिक कचरे की वजह से ज़हरीला हो चुका है. इसी का दुष्परिणाम है कि फ्लोराइड की वजह से हज़ारों लोगों के हाथ पैर टेढ़े हो गए हैं. गर्भ में ही शिशुओं की मौत हो रही है लेकिन कोई इसे देखने-सुनने वाला नहीं है. गोविंद बल्लभ पंत रिहंद सागर का पानी ज़हरीला होने का एक बड़ा कारण बिजली कारखानों से निकलने वाली फ्लाई ऐश भी है. इस फ्लाई ऐश को सीधे पानी में बहा दिया जा रहा है. प्रशासन इस ओर से आंख मूंदे रहा, इसका फ़ायदा उठाते हुए अब जंगल में भी फ्लाई ऐश फेंका जा रहा है. इससे वानिकी संतुलन को ख़तरा पैदा हो गया है. जंगलों में केवल फ्लाई ऐश ही नहीं फेंका जा रहा है बल्कि वन भूमि पर अवैध खनन का धंधा भी जोरों पर है. खनन माफ़िया ने घातक विस्फोटकों के जरिए वन क्षेत्र को दहला कर रख दिया है. इस अवैध खनन ने वन्य जीवों के अस्तित्व पर ख़तरा पैदा कर दिया है. मिर्जापुर, सोनभद्र के जंगलों में काले हिरन, मोर और अन्य वन्य जीव जंतुओं की बहुतायत हुआ करती थी लेकिन अब ऐसा नहीं है. अब यहां केवल विस्फोटकों का शोर और धूल के बादल ही हैं.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बिल्ली-मारकुंडी क्षेत्र में निलंबित सूक्ष्म कणों (एसपीएस) 169 से 2757 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर मापी है. वहीं आरएसपीएम की मात्रा 95 से 660 माइक्रो ग्राम प्रति क्यूबिक मीटर मापी है. मानक के मुताबिक़ एसपीएम और आरएसपीएम का हवा में मानक स्तर क्रमश: दो सौ व सौ माइक्रो ग्राम प्रति घन मीटर होना चाहिए. खनन वाले इलाक़ों में सल्फर डाई ऑक्साइड की मात्रा पांच से 31 और नाइट्रोजन ऑक्साइड की मात्रा 14 से 48 माइक्रो ग्राम प्रति क्यूबिक मीटर है. प्रदूषण के इस ज़हर की चपेट में आकर मजदूर और स्थानीय निवासी अनेक घातक बीमारियों के शिकार हो रहे हैं. खनन माफियाओं के अत्याचार, स्थानीय आदिवासियों के संसाधनों पर क़ब्ज़ा और उनके हितों की अनदेखी का सामाजिक ताने-बाने पर भी काफ़ी विपरीत असर पड़ा है. नक्सलवाद इसी की देन है. नक्सली संगठनों ने आदिवासियों, मजदूरों के साथ हो रहे अन्याय को अपना हथियार बनाया. पहले मिर्जापुर, सोनभद्र व चंदौली को अपनी चपेट में लिया और आज दर्जन भर से अधिक ज़िले नक्सलवाद से ग्रसित हैं. बच्चे भुखमरी का शिकार हैं. उन्हें दो वक्त का भोजन नसीब नहीं हो पाता है. स्कूल और पढ़ाई दूर की कौड़ी है. हालात अगर अभी भी न सुधारे गए तो जल, जंगल, ज़मीन और जन सबकुछ ख़त्म हो जाएगा.

feedback@chauthiduniya.com

पर्यावरणीय मानकों को ताक पर रखकर होने वाले औद्योगिकीकरण से सोनभद्र की जनता धीरे धीरे मौत की ओर बढ़ रही है. हालात पर शीघ्र ही काबू न पाया गया तो आने वाली नस्लें विकलांग पैदा हो सकती हैं. संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपनी रिपोर्ट में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के उस तथ्य का भी उल्लेख किया जिसमें तापीय परियोजनाओं से होने वाले मर्करी के कुल उत्सर्जन की 17 फ़ीसदी मात्रा के लिए ज़िले में स्थापित बिजलीघरों को जिम्मेदार माना गया है. एक फ्रांसीसी कंपनी के अध्ययन में कहा गया है कि सोनभद्र-सिंगरौली क्षेत्र में स्थापित बिजलीघर प्रत्येक वर्ष 720 किलोग्राम पारे का उत्सर्जन कर रहे हैं.

चौथी दुनिया
बिहार झारखंड

दिल्ली, 20 दिसंबर-26 दिसंबर 2010
www.chauthiduniya.com

फोटो-प्रभात पाण्डेय

अपने हुए पराए

यादवों का गुस्सा इस बात से भी था कि लालू केवल वोट के लिए उनका इस्तेमाल करते रहे, पर जब कुछ देने की बारी आई तो अपने घर से बाहर नहीं निकल पाए. इस बार तेजस्वी यादव को चुनाव प्रचार में उतार कर लालू प्रसाद ने एक और आत्मघाती कदम उठा लिया.

सरोज सिंह

बिहार के जनादेश ने लालू यादव को लेकर कुछ बातों को बिल्कुल साफ़ कर दिया. पहला यह कि समर्थक उनसे दूर हो चुके हैं, बावजूद इसके उन्हें यकीन नहीं हो रहा है कि उनके पैरों के नीचे की जमीन सरक चुकी है. जिस माय यानी मुस्लिम-यादव समीकरण को लेकर उन्होंने 15 सालों तक बिहार पर राज किया, वह समीकरण पूरी तरह दरक चुका है. दूसरी बात यह कि सूबे की जनता के ज़ेहन में लालू यादव की जो मजाकिया राजनेता की छवि है, उसे वह नहीं बदल पाए. छवि के मामले में नीतीश कुमार उन पर बहुत भारी निकले. इन सबके अलावा जो एक गंभीर बात साफ़ हुई, वह यह कि जेपी आंदोलन की कोख से निकले लालू प्रसाद राजनीति की ज़मीनी सच्चाइयों को महसूस नहीं कर पाए और अनाप-शनाप फ़ैसले कर अपना और अपनी पार्टी का सत्यानाश कर लिया.

जनादेश 2010 ने यह साफ़ कर दिया कि जिन यादवों ने कभी लालू प्रसाद में नेता से कहीं आगे जाकर भगवान की छवि देखी थी, उन्होंने कई कारणों से इनसे दूरी बना ली. सोनपुर एवं राघोपुर से राबड़ी देवी का बड़े अंतर से हारना यह बताता है कि यादवों के बीच लालू प्रसाद की पकड़ काफी ढीली पड़ गई. राघोपुर में लगभग सवा लाख यादव वोटर हैं और तमाम तिकड़म करने के बावजूद जदयू के एक साधारण कार्यकर्ता सतीश कुमार ने राबड़ी देवी को धूल चटा दी. इसी तरह सोनपुर में लगभग 80 हजार यादव वोटर होने के बावजूद भाजपा के विनय सिंह ने राबड़ी देवी को हरा दिया. राबड़ी देवी का दोनों जगहों से हारना यह साबित करता है कि कहीं न कहीं यादव मतदाताओं के दिलों में लालू यादव के प्रति नाराजगी थी, जो जनादेश में झलक गई. अगर राघोपुर एवं सोनपुर से अलग हटकर बात करें तो बिहार के बहुत सारे यादव बाहुल्य इलाक़ों में भी लालू यादव के उम्मीदवार चुनाव हार गए. गया के अतरी में राजद की कुंती देवी 90 हज़ार यादव मतदाताओं के बावजूद चुनाव हार गईं. यहां से जदयू के कृष्ण नंदन यादव चुनाव जीत गए. इसी तरह शेरघाटी में 60 हज़ार यादव मतदाता भी लालू के ख़ास शकील अहमद को विधानसभा नहीं पहुंचा पाए. यहां भी जदयू के विनोद यादव चुनाव जीत गए. महुआ में 70 हज़ार, महनार में 65 हज़ार, हाजीपुर में 80 हज़ार, मोहुद्दीनगर में एक लाख, झाझा में 75 हज़ार, ओबरा में 60 हज़ार, मसौढ़ी में 70 हज़ार, दानापुर में 90 हज़ार, राजापाकर में लगभग एक लाख, नवादा में 95 हज़ार, गोविंदपुर में एक लाख, गायघाट में 60 हज़ार और बरुराज में 75 हज़ार यादव मतदाता भी लालू एवं पासवान के उम्मीदवारों को विधानसभा नहीं पहुंचा सके.

इस तरह के और भी कई चुनाव क्षेत्र हैं, जहां यादवों का पूरा साथ लालू यादव को नहीं मिला. दरअसल लालू यादव अपने प्रति यादवों की नाराज़गी की इसी कमज़ोर कड़ी को नहीं समझ पाए. यही वजह रही कि विधानसभा चुनाव में जीतकर सरकार बनाने की बुनियाद ही ढह गई. लालू प्रसाद ने 61 यादवों को अपना उम्मीदवार बनाया था, पर इनमें 11 ही जीत पाए. जबकि एनडीए के 27 यादव प्रत्याशी विधानसभा पहुंच गए. जातीय समीकरण समझने वाले विश्लेषकों का मानना है कि कोई भी एक जाति किसी एक नेता के साथ ज़्यादा दिनों तक तभी रह सकती है, जब तक अन्य जातियों का साथ भी उसे मिलता रहे. लालू यादव के साथ दिक्कत यह हो गई कि अन्य जातियों के साथ-साथ मुसलमान भी उनसे कट गए. इस कारण यादवों का भी पूरा साथ इस चुनाव में लालू प्रसाद को नहीं मिल पाया. इसके अलावा उनका रेलमंत्री का कार्यकाल भी यादवों को उनसे दूर ले गया. जिन कार्यकर्ताओं को लालू नाम से बुलाते थे, उनका नाम भी वह भूल गए. उनके दरबार में चाटुकारों की भरमार हो गई. अच्छे एवं जनाधार वाले लोगों ने लालू का साथ धीरे-धीरे छोड़ दिया. बिहार की सत्ता मिलने के बाद पहले तो उन्होंने खुद को सरकार का मुखिया समझा, फिर ख़ुद को सरकार समझने लगे और एक दौर ऐसा भी आया, जब लालू ख़ुद को ही बिहार समझने लगे. यादवों का एक तबका तो सत्ता की मलाई खाता रहा, लेकिन ज़्यादातर यादवों को सामाजिक न्याय के नाम पर केवल भाषण ही मिला. राशन के संकट के कारण उनका लालू के प्रति मोह ख़त्म होता गया और जब लालू गांव-देहात में रहने वाले ऐसे यादवों का नाम भी भूलने लगे तो पानी सिर से ऊपर चला गया. लालू इस गुमान में रहे कि यादव तो हर हाल में उनका साथ देंगे ही देंगे, पर 2010 आते-आते बात बिल्कुल बिगड़ चुकी थी. दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने सोशल इंजीनियरिंग का जो ताना-बाना बुना, उसमें कोयरी-कुर्मी को छोड़कर कई नई पिछड़ी जातियां भी उनके साथ होती चली गईं. यहां तक कि यादवों के दरवाजे भी नीतीश कुमार के लिए खुल गए. यही वजह रही कि नीतीश कुमार के यादव उम्मीदवारों को इस बिरादरी ने हाथोंहाथ लिया. यादवों का गुस्सा इस बात से भी था कि लालू केवल वोट के लिए उनका इस्तेमाल करते रहे, पर जब कुछ देने की बारी आई तो अपने घर से बाहर नहीं निकल पाए. इस बार तेजस्वी यादव को चुनाव प्रचार में उतार कर लालू प्रसाद ने एक और आत्मघाती कदम उठा लिया. गांव-देहात में बैठे यादवों के साथ-साथ प्रखंड एवं ज़िला मुख्यालयों में राजनीति करने वाले यादव नेताओं को लगा कि लालू यादव ने अपनी ग़लतियों से सबक न सीखने की कसम ही खा ली है और परिवार से बाहर झांकने की कोशिश नहीं कर रहे हैं. ऐसे में यादवों का एक बड़ा तबका लालू से दूर चला गया. लालू ने ख़ुद को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दूसरी जातियों को खुद से दूर कर लिया और यादवों ने खुद को लालू के साथ अकेला पाकर कदम वापस खींच लिए. पासवान के साथ उनके गठबंधन को भी लोगों ने पसंद नहीं किया.

हाल यह हो गया कि अपने गृह ज़िले गोपालगंज में भी लालू राजद का खाता तक नहीं खुलवा पाए. प्रभुनाथ सिंह के साथ बेमेल का साथ भी यादवों को पसंद नहीं आया. प्रभुनाथ सिंह ने अपनी पूरी राजनीति ही यादवों के ख़िलाफ़ की और अचानक यादव वोट पाने के लिए हाथ पसारने लगे तो एक बड़ा अजीब सा माहौल बन गया. यही वजह रही कि सारण में भी लालू को कामयाबी नहीं मिल पाई. कहा जाए तो लालू ग़लती पर ग़लती करते चले गए और नतीजे में यादवों से दूर होते गए. दानापुर से रंजन यादव के ख़िलाफ़ चुनाव हारने के बाद से ही अगर वह संभल जाते तो उन्हें आज यह दिन नहीं देखना पड़ता. जदयू ने रंजन यादव सरीखे यादव नेताओं को तवज्जो देकर इस बिरादरी को नीतीश के करीब ला दिया. सतीश कुमार जैसे युवा यादव नेताओं का उभरना इसी का परिणाम है. लालू ने आज भले ही ज़मीन छोड़ दी हो, पर वह ज़मीन के नेता रहे हैं, इसलिए उन्हें संभलने में ज़्यादा वक़्त नहीं लगेगा, पर शर्त यह है कि उन्हें अपनी सभी ग़लतियों से सबक लेना होगा. उन्हें 1990 का लालू बनना होगा, जिसके मुंह से ग़रीबों की सच्ची आवाज़ निकलती थी और जिसके सीने में ग़रीबों का दर्द था. दबे-कुचलों के लिए संघर्ष करने वाले लालू यादव को फिर से पैदा होना होगा. अगर यह हो पाया तो लालू की वापसी संभव है, वरना बिहार की जनता अब पीछे मुड़कर देखने वाली नहीं है.

feedback@chauthiduniya.com

विधानसभा चुनाव में जातिवार प्रतिनिधित्व

जाति	1990	1995	2000	2005	2010
यादव	63	86	64	54	39
कोइरी	12	13	12	16	21
कुर्मी	18	27	22	22	19
बनिया	18	18	12	16	13
ब्राह्मण	27	09	08	10	16
भूमिहार	34	18	19	23	26
राजपूत	41	22	26	23	31
कायस्थ	03	07	03	03	03
अति पिछड़ा वर्ग	06	16	11	19	17

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा व्यवस्था के नाम पर वहां अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र तो हैं, लेकिन इसमें प्रतिनियुक्त चिकित्सक कई स्वास्थ्य केंद्रों के प्रभार में हैं.

मगध प्रमंडल के 26 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव के पूर्व पार्टी टिकट बंटने के बाद ही विद्रोह की स्थिति पैदा हो गई थी.

एक नज़र इधर भी

फूलों की खेती ने बदली किस्मत

गया जिले के मानपुर प्रखंड के खजांपुर पंचायत के विभिन्न गावों में फूलों की खेती ने वहां के किसानों की तकदीर बदल दी. कभी यहां के किसान विभिन्न फ़सलों की खेती करने के बाद भी परेशान रहा करते थे लेकिन कुछ लोगों की सलाह पर जब फूलों की खेती शुरू की तो सारा मामला ही बदल गया. गया और बोधगया जैसे धार्मिक पर्यटन स्थल होने के कारण यहां प्रतिदिन फूलों की काफी खपत होती है. पहले यहां के फूल व्यवसायी कलकत्ता तथा अन्य स्थानों से फूलों की ख़रीद करते थे. आज गया जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में फूलों की खेती खूब हो रही है. इससे यहां के किसानों को अच्छी आमदनी भी हो रही है तथा फूल व्यवसायी भी दूर से फूल मंगाने की परेशानी से बच रहे हैं.

अवैध लकड़ी का व्यवसाय

बीड कार्ड रेल खंड के मानपुर तथा गया रेलवे स्टेशन के बीच प्रतिदिन विभिन्न ट्रेनों से जंगल से काटकर लाई गई अवैध लकड़ियों को उतारा जाता है. इसमें रेल लाईन को भी बाधित कर दिया जाता है. संयोग से कभी कोई ट्रेन इस लाइन पर आ जाये तो किसी दुर्घटना से इंकार नहीं किया जा सकता है. स्टेशनों व रेलवे ट्रैक की सुरक्षा में लगे आरपीएफ के लोग भी इसे रोकने में असफल हो रहे हैं. जब कोई घटना होगी तो रेलवे प्रशासन और सुरक्षा बलों की नींद टूटेगी.

एन.एच.82 बदहाल है

राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 82 गया को बुद्धिष्ट सर्किट से जोड़ती है. बिहार शरीफ से मानपुर होते हुए बोधगया तक जाने वाली इस सड़क की हालत ख़राब होगई है. मानपुर बस पड़ाव के पास इस राष्ट्रीय उच्चपथ पर गड्ढे के कारण वाहनों के आने-जाने में काफी परेशानी होती है. कई बार यहां पर वाहन दुर्घटना ग्रस्त हो चुके हैं. फिर भी इस की मरम्मत नहीं की जा सकी है. *-अजय कुमार सिंह*

पति के विधायक बनने से मुखिया जी उत्साहित

पहले मुखिया फिर पंचायत शिक्षक और अब हसनपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक निर्वाचित हुए राजकुमार राय के गृह पंचायत बेलसंडी की अब अलग पहचान बन जायेगी. कारण कि बेलसंडी पंचायत के मुखिया पद पर अभी विधायक जी की पत्नी पुष्पलता देवी क़ाबिज़ हैं. मुखिया के पति जब विधायक हो तो इस पंचायत का अंजाम क्या होगा कहना तो लाज़िमी है. पति के विधायक बनने से उत्साहित पुष्पलता देवी कहती हैं कि पूरे विधानसभा क्षेत्र के साथ-साथ बेलसंडी पंचायत का भी समुचित विकास होगा. सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ निश्चित तौर पर समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों को मिलेगा. अपने किये हुए कार्यों से संतुष्ट होकर वे कहती हैं कि पहले की तरह ही जनता का सहयोग अगामी पंचायत चुनाव में भी मिलेगा. *-दिनेश कुमार*

3.10 मिलियन टन स्वर्ण का अनुमान

खान मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) ने झारखण्ड में स्वर्ण, कोयला, लौह-अयस्क, ऐंटाइट और दुर्लभ धातुओं जैसे खनिजों की उपलब्धता का अनुमान लगाने के लिए प्रदेश में सर्वेक्षण किया. इन सर्वेक्षणों के दौरान, जीओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (जीएसआई) ने रांची जिले में कुल 3.10 मिलियन टन स्वर्ण के संसाधन होने का अनुमान लगाया है. केंद्रीय खान और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री विजय कृष्ण हांडिक ने राज्य सभा में सांसद परिमल नाथवाणी के एक प्रश्न के उत्तर में यह बताया कि नाथवाणी ने झारखंड में प्रदेश के खनिज पदार्थों की उपलब्धता का अनुमान लगाने के लिए कराये गये नये सर्वेक्षण का ब्यौरा मांगा था. अभी इस पर शोधकार्य जारी है.

छोटू सिंह ढोल पीटकर भ्रष्टाचार मिटाएंगे

जदयू नेता छोटू सिंह ने घोषणा की है कि वह पूरे बिहार में घूम-घूम कर भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ अभियान छेड़ेंगे. कहते हैं कि नीतीश कुमार का सपना है कि राज्य में भ्रष्टाचार ख़त्म हो. उनके सपनों को पूरा करने के लिए वह लोगों से ढोल बजाकर अपील करेंगे कि वे भ्रष्टाचारियों का साथ न दें. भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए पुलिस प्रशासन को सही जानकारी दें. छोटू सिंह मानते हैं कि अगर भ्रष्टाचार की बीमारी बिहार से समाप्त हो गई तो यह राज्य देश का नंबर एक राज्य बन जाएगा.

पूरा महनार जगमग होगा: अच्युतानंद

महनार से निर्वाचित भाजपा विधायक डॉ. अच्युतानंद न्याय के साथ विकास के अभियान के साथ-साथ अल्पसंख्यक कल्याण की भी कवायद में जुट गए हैं. अच्युतानंद ने विधानसभा के इस सत्र में कब्रिस्तानों की शीघ्र घेराबंदी करवाने की आवाज़ विधानसभा में बुलंद की है. उन्होंने कहा कि क्षेत्र के मदरसों व उर्दू विद्यालयों के भवन पेयजल समेत अन्य सुविधाओं पर भी उन्हें काफी चिंता है और इसके समाधान के लिए वह प्रयासरत हैं. महनार विधानसभा क्षेत्र में व्याप्त बिजली की समस्या पर उन्होंने कहा कि जंदाहा में ग्रिड स्टेशन का निर्माण हो रहा है तथा शीघ्र ही ऐसा समय आयेगा, जब यहां भी दिल्ली-मुंबई की तरह बिजली रहेगी.

डीलरों का धरना

विभिन्न मांगों को लेकर जिला जन वितरण प्रणाली विक्रेता एसोसिएशन ने खगड़िया जिला समाहरणालय के समक्ष धरना दिया. संघ के अध्यक्ष रामप्रताप पासवान के नेतृत्व में आयोजित इस धरना कार्यक्रम में संघ के सभी छह मांगों पर व्यापक चर्चा की गई. मौके पर संघ के महामंत्री राजेश कुमार सिंह, नरेश कुमार सुमन, ईश्वर प्रसाद साह, रूदल यादव, हरे राम सिंह, जवाहर प्रसाद सिंह, प्रताप मेहता आदि उपस्थित थे. *-दिलीप कुमार*

गंदगी में हो रहे ऑपरेशन

खगड़िया सदर अस्पताल में इन दिनों बंध्याकरण कराने वाली की भीड़ उमड़ पड़ी है. लेकिन साफ़-सफ़ाई तथा अन्य व्यवस्था बेहतर न रहने के कारण महिलाओं तथा उनके परिजनों में नाराज़गी व्याप्त है. आशा कार्यकर्ताओं की मनमानी इतनी चरम पर है कि प्रायः बंध्याकरण कराने आई महिलाओं के साथ-साथ उनके परिजनों से नोंक-झोंक हो जाती है.

हम बनाएंगे विश्वास का भवन: दामोदर

दामोदर रावत यानी नीतीश मंत्रिमंडल का ऐसा चेहरा, जिसने अपने काम से नीतीश कुमार और सूबे की जनता का भरोसा जीता. हर किसी से दिल खोलकर मिलने वाले दामोदर रावत पिछड़े जमुई ज़िले के झाझा विधानसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं. सादगी ऐसी कि भवन निर्माण मंत्री बनने के बावजूद किसी बड़े बंगले में जाने के बजाए अपने पुराने आवास में ही रहने का फ़ैसला किया. जनादेश के संदेश से चार्ज दामोदर रावत पूरे सूबे में ख़ूबसूरत भवनों का निर्माण करना चाहते हैं. ताकि लोगों को न सिर्फ आशियाना मिले बल्कि उनके दिल को सुकून भी मिले. तब समय पर काम व गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं. इन दो सूत्रों पर मंत्री जी अपने टास्क को अंजाम देने में जुट गए हैं. प्रस्तुत है उनसे बातचीत के ख़ास अंश-

जनादेश से लगता है कि सूबे में एक ख़ामोश सामाजिक क्रांति हुई है. विपक्ष इसे क्यों महसूस नहीं कर पाया?

देखिए, नीतीश कुमार ने अपने कामों से ऐसे लोगों का भरोसा जीता जिन्हें आज तक दूसरे दलों ने ठगने का काम किया था. महादलितों के लिए जो कल्याणकारी काम किए गए, उससे उन लोगों को लगा कि नीतीश कुमार ही उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ सकते हैं. महिलाओं को आरक्षण व लड़कियों को साइकिल आदि ऐसी अनेक योजनाएं ज़मीन पर उतरीं, जो आज़ादी के बाद से केवल भाषणों में ही झलकती थीं. सूबे की जनता को लगा कि नीतीश कुमार सिर्फ कहते नहीं बल्कि करके भी दिखाते हैं. इसका पूरा मेहनताना लोगों ने दिया और विपक्ष देखता रह गया. कांग्रेस, राजद व लोजपा के नेताओं ने लोगों को सिर्फ सपने दिखाए, पर नीतीश सरकार ने लोगों के सपनों को साकार किया.

पिछली सरकार में भी आप मंत्री थे और इस बार फिर आपको भवन निर्माण विभाग की ही ज़िम्मेदारी दी गई है. इसे कितना बड़ा काम मानते हैं.

यह जनता का काम है. कोई छोटा या बड़ा नहीं होता. पिछले कार्यकाल में भी मैंने ऐसी बहुत सारी योजनाओं को ज़मीन पर उतारा था. बाद में केंद्र सरकार ने भी उनका अनुसरण किया. उदाहरण के तौर पर निराश्रता पेंशन योजना व लक्ष्मीबाई योजना का नाम लिया जा सकता है. समाज के सबसे निचले पायदान पर रहने वाले लोगों का कल्याण हो, बस इसी मक़सद से पिछले कार्यकाल में लगा रहा और मुझे ख़ुशी है कि जनता ने मेरे काम को पसंद किया. जहां तक नई ज़िम्मेदारी का सवाल है तो मैं काम को बोझ की तरह नहीं लेता, बल्कि इसे नेता का आदेश और जनता का क़र्ज़ समझ कर हर चुनौती को यथाशक्ति पूरा करने का प्रयास करता हूं. नए विभाग में भी पूरी कोशिश करूंगा कि अपने नेता नीतीश कुमार व जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरूं.

पदभार ग्रहण करने के बाद से ही आप लगातार विभाग की समीक्षा कर रहे हैं. प्राथमिकताएं क्या हैं?

समय पर काम और गुणवत्ता का पूरा ख्याल, यही मेरा और मेरे विभाग का मूलमंत्र है. काम को लटकाने वाली संस्कृति नहीं चलेगी. समय पर काम पूरा होगा तो लागत में इज़ाफ़ा नहीं होगा. इसके साथ ही साथ विभाग के सारे लोगों को कह दिया गया है कि गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा. मैं ख़ुद ज़िलों में जाकर कामों की समीक्षा करूंगा, ताकि सही तस्वीर सामने आ सके. काम न करने वाले और गलत काम करने वाले अधिकारी व कर्मचारी दंडित होंगे. समय पर अच्छा काम करने वाले अधिकारी व कर्मचारी पुरस्कार पाएंगे. मक़सद केवल इतना है कि जनता ने जो काम सौंपा है वह हर हाल में पूरा हो और अच्छी तरीक़े से पूरा हो.

पिछले दिनों नक्सलियों ने आपको मारने की साज़िश रची थी. इससे कहीं आप का काम तो प्रभावित नहीं होगा?

आप जानते ही हैं कि मैंने शुरू से ही समाज के सबसे निचले तबके के लिए काम किया है. दबे कुचलों की सेवा तथा उनके जीवन स्तर में सुधार हमारा संकल्प रहा है. इसलिए नक्सलियों से डरने की कोई बात नहीं है. सूबे में विकास का महापर्व शुरू हो चुका है. हर किसी की ज़िम्मेदारी है कि वह एक विकसित बिहार के लिए इस महापर्व में शामिल हो.

आप विपक्ष की राजनीति भी कर चुके हैं और अब सरकार में शामिल हैं, अब तक के राजनीतिक सफ़र से आप कितना संतुष्ट हैं.

जनता की सेवा के लिए राजनीति में आए हैं तो संतुष्ट होने का सवाल कहां पैदा होता है. जब तक समाज के सबसे निचले तबके के आदमी के घरों में विकास का दीपक नहीं जल जाता तब तक संतुष्टि नहीं मिलेगी. अभी तो दिन रात काम करके जनता की कसौटी पर खरा उतरने का समय है. ग़रीबों के लिए लगातार काम करते रहना है. जनता का आशीर्वाद मिलता है तो लगता है दिन सफल हो गया.

अपने ज़िले के लिए आपने क्या सोचा है, किसी ख़ास रोडमैप पर काम कर रहे हैं?

ज़िले की बात नहीं है, हम तो पूरे बिहार के बारे में सोच रहे हैं. हां इतना ज़रूर है कि जिस जमुई ज़िले से मैं चुनकर आता हूं, वह काफ़ी पिछड़ा है और वहां का जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरा ख़ास दायित्व बनता है कि वहां के लिए कुछ ख़ास हो. ज़िले में सिंचाई व्यवस्था को सुधारने करने की ज़रूरत है. रोज़गार के अवसर बढ़ाने पर विचार होगा. इसके अलावा बीड़ी मज़दूरों का जीवन स्तर बेहतर हो सके, इस दिशा में भी ठोस क़दम उठाए जाएंगे. सिमुलतला में बेहतरीन स्कूल भवन के निर्माण को मैंने अपने सपनों के प्रोजेक्ट के रूप में लिया है. मुझे पूरा यक़ीन है कि यह स्कूल बिहार की एक ख़ास पहचान बनेगा.

सरोज सिंह
feedback@chauthiduniya.com

रोसड़ा प्रखंड
पंचायत चुनाव की बिसातें बिछने लगीं

संजीव कुमार सिंह

वर्ष 2011 के अप्रैल-मई महीने में होने वाले चुनाव को लेकर पंचायत स्तर पर पंचायत जनप्रतिनिधियों के कार्यकलापों की समीक्षा के दौरान चौथी दुनिया ने ज़िले की सभी 381 पंचायतों के पांच वर्षों का लेखा-जोखा क्रमवार प्रस्तुत करने की योजना बनाई है. प्रस्तुत है पहली कड़ी. इस कड़ी में रोसड़ा प्रखंड के ठाहर बसढ़िया पंचायत में विकास योजनाओं की समीक्षा एवं मुख्य समस्याओं पर पर ध्यान दिया गया है. नई सरकार का गठन होने के साथ ही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की बिसातें बिछने लगी हैं. विभिन्न पदों के संभावित प्रत्याशी जनता की नब्ज टटोलते देखे जा रहे हैं. वर्तमान जनप्रतिनिधि पुनः सत्तासीन होने के लिए अपनी रणनीति में जुटे दिख रहे हैं. जनता भी जनप्रतिनिधियों के कार्यों का जायज़ा ले रही है.

रोसड़ा प्रखंड का ठाहर बसढ़िया पंचायती राज के इन दस वर्षों में भी आदर्श पंचायत का दर्जा प्राप्त नहीं कर सका है. आज भी इस पंचायत में कई समस्याएं मुंह बाए खड़ी हैं. हालांकि पंचायत के निर्वाचित जनप्रतिनिधि अधिकांश समस्याओं को हल करने का दावा करते हैं, लेकिन आज भी कई समस्याएं मसलन सड़क, बिजली, तटबंध, स्वास्थ्य, बालिका शिक्षा, पेयजल आदि की समस्या आज भी बरकरार हैं. वर्ष 2004 की बाढ़ में ध्वस्त रोसड़ा-हथौड़ी सड़क ठाहर के समीप दो सौ मीटर में आज भी गड्ढे में तब्दील हैं. इसी बाढ़ में ठाहर गांव के समीप टूटे बागमती के तटबंध आज भी खुले पड़े हैं. सड़कें पूरी तरह जर्जर हैं. ठाहर बसढ़िया पंचायत में शामिल कमलपुर, ठाहर, मुसहरी, कैलू टोल, बलुआहा, बरैठा, गायघाट, वैद्यनाथपुर एवं लक्ष्मीपुर गांव की तकरीबन 8800 की आबादी बिजली की समस्या से आज भी जूझ रही है. बालिकाओं की शिक्षा के लिए पंचायत में कोई विशेष व्यवस्था नहीं है. पेयजल की स्थिति संपूर्ण पंचायत में ही दम तोड़ती दिख रही है. स्वास्थ्य एवं चिकित्सा व्यवस्था के नाम पर अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र तो हैं लेकिन इसमें प्रतिनियुक्त चिकित्सक कई स्वास्थ्य केंद्र के प्रभार में हैं.

सरकार की विभिन्न महत्वाकांक्षी योजनाओं को पंचायत में शत प्रतिशत उतारने का दावा करते हुए पंचायत के मुखिया राजेंद्र शर्मा की मानें तो पारिवारिक सर्वेक्षण सूची के 2167 परिवारों में से 1083 बीपीएल परिवारों को प्रतिमाह खाद्यान्न एवं केरोसिन उपलब्ध होता रहा है. इसके साथ ही वृद्ध लोगों के लिए इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन के तहत तकरीबन 225 लोगों को प्रतिमाह 200 रुपये की राशि एवं लक्ष्मीबाई पेंशन योजना के तहत विधवा महिलाओं को भी 200 रुपए प्रतिमाह दिये जा रहे हैं. इस योजना के तहत 25 विकलांगों को भी पेंशन दिए जाने की स्वीकृति हुई है. इस पंचवर्षीय कार्यकाल में तकरीबन 300 बीपीएल परिवारों को इंदिरा आवास योजना की राशि दी गई है जबकि 1400 लोगों को जॉब कार्ड उपलब्ध कराया गया है.

सौंदर्यीकरण योजना के तहत 36 सोलर लाइट पंचायत के विभिन्न चौक-चौराहों एवं गलियों में लगाये गए हैं. ग़रीब तबके के टोले में तीन सामुदायिक भवन ठाहर, बहुआहा एव कैलू टोल में निर्माणाधीन हैं. 450 लोगों का स्वास्थ्य बीमा कराया गया है. कन्या विवाह योजना के तहत 103 कन्याओं को 5000 की राशि दी गई है, जबकि कबीर अन्त्येष्ठि योजना के तहत 34 लोगों को 1500 रुपए की राशि प्रदान की गई है. वर्ष 2007 की आपदा में पंचायत के 2167 परिवारों को 1 क्विंटल खाद्यान्न एवं 200 रुपये की राशि दी जा चुकी है. शिक्षा के क्षेत्र में गायघाट प्राथमिक विद्यालय को उत्क्रमित कर मध्य विद्यालय का दर्जा दिलवाया गया है जबकि कमलपुर एवं कैलू टोल में दो नवसृजित विद्यालय खोले गये हैं. इन विद्यालयों के लिए 8 शिक्षकों की बहाली भी की गई है. पारिवारिक सूची से वंचित 96 परिवारों का नाम जोड़ा गया है. आदर्श पंचायत का दर्जा दिलाने का प्रयास जारी है.

पंचायत चुनाव के दौरान कुल 6 पदों के लिए चुनाव होने हैं जिसमें ज़िला पार्षद, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच, मुखिया, वार्ड सदस्य एवं वार्ड पंच का चुनाव होना है. ठाहर बसढ़िया पंचायत की कुल दस हज़ार आबादी में 4400 वोटर कुल 30 पदों पर अपने प्रतिनिधि का चुनाव करेंगे, जिसमें मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य एवं ज़िला पार्षद के अलावा वार्ड सदस्य एवं पंच के 13-13 पद शामिल हैं.

feedback@chauthiduniya.com

विधानसभा चुनाव परिणाम असर डालेंगे

समस्तीपुर पंचायत चुनाव

विकास कुमार

आगामी अप्रैल-मई में होनेवाले पंचायत चुनाव के मौजूदा प्रतिनिधियों पर ज़्यादा असर दिख रहा है. ज़िले के 381 पंचायतों, 20 प्रखंडों तथा 51 ज़िला परिषद क्षेत्रों में विधानसभाई चुनाव परिणाम की गहमागहमी दिखने लगी है. इस बार विधानसभाई चुनाव में खड़े ज़िले के 217 प्रत्याशियों में से पंचायती राज व्यवस्था से जुड़े कई प्रतिनिधियों एवं उनके परिजन चुनावी संग्राम में कूदे और कईयों को सफलता भी मिली. ज़िले के सफल विधायकों में से हसनपुर विधानसभा क्षेत्र के जदयू विधायक राजकुमार राय जो बिथान प्रखंड के बेलसंडी पंचायत के पूर्व मुखिया रह चुके हैं और वर्तमान में उनकी पत्नी पुष्पलता देवी बेलसंडी पंचायत की मुखिया पद पर आसीन हैं. इसी तरह नवगठित उजियारपुर क्षेत्र के पूर्व प्रखंड प्रमुख दुर्गा प्रसाद सिंह ने राजद प्रत्याशी के रूप में जीत हासिल की है. नवगठित मोरबा क्षेत्र में भी ज़िला परिषद चुनाव लड़े वैद्यनाथ सहनी ने जदयू प्रत्याशी के रूप में सफलता पाई है. महिला सशक्तिकरण अभियान के अन्तर्गत ज़िला परिषद अध्यक्षा मंजू हजारी ने भाजपा प्रत्याशी के रूप में रोसड़ा (सु.) विधानसभा क्षेत्र में राजद के दिग्गज पूर्व सांसद एवं प्रदेश अध्यक्ष पीतांबर पासवान को पराजित कर ज़िले में पहली बार भाजपा की जीत का खाता खुलवाया है. इसी तरह वामपंथियों के गढ़ विभूतिपुर विधानसभा क्षेत्र में जदयू प्रत्याशी एवं मुखिया रामबालक सिंह कुशवाहा ने उक्त क्षेत्र से लगातार कई बार से जीत रहे सीपीएम विधायक रामदेव वर्मा को शिकस्त देकर राज्य के एकमात्र सीपीएम विधायक का पत्ता साफ़ कर दिया है. कई बार से जदयू प्रत्याशी रामबालक सिंह एवं रामदेव वर्मा के बीच चुनावी संघर्ष चल रहा था जो इसबार नीतीश सरकार के काम और विकास के नारे पर जाकर सफल हो पाया है और क्षेत्र के लोग विकास के लिए विजेता विधायक की ओर मुखातिब हो गए हैं. इस बार के विधानसभाई चुनाव में ग़ैर स्वंयसेवी संस्थान एवं सहकारिता आन्दोलन से जुड़े दुर्गा प्रसाद सिंह एवं मोहिउद्दीनगर के भाजपा प्रत्याशी राणा गंगेश्वर प्रसाद सिंह की कामयाबी के बाद सामाजिक एवं सहकारी संगठनों में भी सरगर्मी बढ़ गई है और आनेवाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में कूदने के लिए अभी से ही कमर कस रहे हैं. केंद्र प्रायोजित योजनाएं मनरेगा, इंदिरा आवास योजना, वृद्धावस्था पेंशन समेत अन्य योजनाओं में जिन्होंने पंचायत के अंदर लूट-खसोट की है. ऐसे में मौजूदा पंचायत प्रतिनिधियों के चेहरे पर हवाईयां उड़नी शुरू हो गईं हैं. इसके पूर्व भी ज़िला परिषद के पूर्व अध्यक्ष स्व. चुल्हाई राम एवं प्रो. शील कुमार राय विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं और इस बार जिला परिषद की मौजूदा अध्यक्षा मंजू हजारी के भाजपा विधायक बन जाने से ज़िले में पंचायती राज व्यवस्था की लहर चल रही है. ज़िले के कई क्षेत्रों में पंचायती राज ज़िला परिषद प्रतिनिधि के विधानसभाई चुनाव में कूद जाने से इस क्षेत्र का चुनाव परिणाम प्रभावित होने की चर्चा हो रही है. वारिसनगर विधानसभा क्षेत्र में ज़िला पार्षद वसीम रजा एवं बी.के. सिंह समेत कई दिग्गज चुनाव मैदान में थे, जो ख़ुद तो डूबे ही साथ ही राजद प्रत्याशी पूर्व मंत्री गजेंद्र प्रसाद सिंह एवं कांग्रेस प्रत्याशी विजय कुमार तूफान को भी ले डूबे.

राजकुमार राय, मंजू हजारी, राम बालक सिंह

नगर परिषद समस्तीपुर की पूर्व मुख्य पार्षद एवं कांग्रेस की प्रत्याशी अनीता राम को कल्याणपुर (सु.) क्षेत्र में जेपी आंदोलन के योद्धा एवं जदयू प्रत्याशी रामसेवक हजारी से भले ही पराजित होना पड़ा, लेकिन ज़िले की विधानसभाई राजनीति में 13,000 से अधिक मत पाकर उन्होंने अपनी साख बनाई है. इसी तरह समस्तीपुर नगर परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष त्रिभुवन साह ने समस्तीपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनावी संग्राम में कूदकर वैश्य समाज से कांग्रेस प्रत्याशी डॉ. तरुण कुमार की नैया डुबो दी, वहीं नीतीश लहर के बावजूद सरकार के पूर्व विधि, सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री रामनाथ ठाकुर की नैया भी बीच मंझधार में फंसकर रह गई और राजद के युवा नेता एवं प्रांतीय महासचिव अख्तरूल इसलाम साहिन ने चुनावी बाजी मारकर ज़िले से लेकर राज्य तक राजग सरकार की बोलती बंद कर दी. ज़िले के विधानसभाई चुनाव में राजग गठबंधन की ओर से जदयू ने छह सीट एवं भाजपा ने पहली बार दो सीटों पर कामयाबी हासिल कर आने वाले पंचायती राज चुनाव में राजग सरकार की अलख जगा दी है और कल तक जो लालू-रामविलास और कांग्रेस की चर्चा कर रहे थे वे भी अब नीतीश-मोदी का गुणगान करते दिख रहे हैं.

feedback@chauthiduniya.com

गठबंधन में दरार

नवल किशोर सिंह

मुंडा सरकार के गठन के बाद झारखंड में एनडीए के अंदर घटक दलों की एकजुटता में दरार पड़नी शुरू हो गयी है. जमशेदपुर लोकसभा सीट पर दावेदारी को लेकर झामुमो और भाजपा आमने-सामने है. अभी इस सीट पर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव व सूबे के मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा का क़ब्ज़ा है. लेकिन मुख्यमंत्री बने रहने के लिए उन्हें छह माह के अंदर विधायक बनने की औपचारिकता पूरी करनी होगी और लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफ़ा देना होगा. छह माह में करीब तीन माह गुज़र चुके हैं. उनके लिये विधायक मंगल सिंह सोय ने खरसावां विधानसभा सीट खाली कर दी है. अर्जुन मुंडा सांसद बनने के पहले इसी सीट से विधायक थे. मंगल सिंह सोय उन्हीं की कृपा से चुनाव लड़े और विधायक बने थे. जमशेदपुर संसदीय सीट को झामुमो अपनी पारंपरिक सीट मानती है. इस सीट पर लंबे समय से उसका कब्जा रहा है.

मुंडा के पहले झामुमो के सुनील महतो जमशेदपुर के सांसद थे. उग्रवादियों ने उनकी हत्या कर दी. जिससे वह सीट खाली हो गई थी. उपचुनाव में स्व. महतो की विधवा सुमन महतो झामुमो की उम्मीदवार थीं. वह जीती भी. इस वक्त भाजपा प्रत्याशी दिनेश कुमार साड़ंगी चुनाव हार गए थे. लेकिन आम चुनाव में भाजपा की ओर से अर्जुन मुंडा मैदान में उतरे. सुमन महतो उनका मुकाबला नहीं कर सकीं. दूसरी बार सहानुभूति मतों को बटोर पाने में वह विफल रहीं. अर्जुन मुंडा भारी मतों से विजयी हुए. उस वक़्त झामुमो यूपीए में था. अब जब झामुमो एनडीए में है और झारखंड में भाजपा की अगुवाई वाली सरकार में शामिल हैं और अर्जुन मुंडा को जमशेदपुर सीट खाली करनी है तो वह चाहते हैं कि इस सीट पर होने वाले उपचुनाव में एनडीए की ओर से साझा प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने का मौका झामुमो को दिया जाए. यह झामुमो की सीट रही है. उधर भाजपा उस पर अपना दावा मानती है. अर्जुन मुंडा चाहते हैं कि इस सीट पर भाजपा की ओर से मंगल सिंह सोय को उम्मीदवार बनाया जाए. ताकि खरसावां सीट छोड़ने के घाटे की भरपाई की जा सके.

फ़िलहाल झामुमो अपने दावे पर अड़ा हुआ है और अर्जुन मुंडा सोय को दिए वचन के कारण पीछे हटने की स्थिति में नहीं हैं. झारखंड की राजनीति की जानकारी रखने वाले लोग जानते हैं कि झामुमो जब जिद पकड़ लेता है तो किसी हालत में पीछे नहीं हटता भले ही कितना भी नुकसान उठाना पड़े.

हालांकि अभी अर्जुन मुंडा ने सांसद पद से इस्तीफ़ा दिया नहीं है. उन पर दबाव डाला जा रहा है कि लोकसभा से इस्तीफ़ा देने के बाद विधानसभा चुनाव लड़ें. यह उनकी विवशता नहीं है, लेकिन दावेदारी को लेकर भाजपा- झामुमो के बीच की रस्साकशी तेज़ हो जाएगी. जमशेदपुर सीट को लेकर भाजपा और झामुमो के बीच जो तकरार शुरू हुई है, वह गठबंधन की सेहत के लिए भी नुकसानदेह सिद्ध हो सकती है. झामुमो के अड़ियल रवैये के कारण ही पिछली बार उसकी साझा सरकार नहीं बन सकी थी और राष्ट्रपति शासन लागू हो गया था. झामुमो अपने राजनीतिक नफ़ा-नुकसान की कभी चिंता नहीं करता. इसलिये इस मसले पर भाजपा को ही समझौता करना पड़ सकता है, क्योंकि झामुमो उसके समकक्ष हैसियत रखते हुए सत्ता में शामिल है. बहरहाल आनेवाले दिनों में यह मामला क्या रंग लेता है यह देखना दिलचस्प होगा.

feedback@chauthiduniya.com

चुनाव के बाद का पोस्टमार्टम

चुनाव परिणाम आने के साथ ही कांग्रेसियों में गुस्सा फूटा और उन्होंने हार का ठीकरा महबूब अली कैसर, मुकुल वासनिक, अशोक राम तथा मगध प्रमंडल में टिकट बंटवारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले तत्कालीन विधायक अवधेश कुमार सिंह के सिर फोड़ डाला.

सुनील सौरभ

मगध

बिहार विधानसभा चुनाव परिणामों ने कांग्रेस को सबसे अधिक प्रभावित किया. 1990 से लेकर 2005 तक राजद का साथ देना कांग्रेस के लिये आत्मघाती साबित हुआ. लोकसभा की तर्ज पर इस बार विधानसभा चुनाव में एकला चलो की नीति के साथ लड़ने के बाद भी कांग्रेस को असफलता ही हासिल हुई. इसे सबसे अधिक फ़ज़ीहत ग़ैर-कांग्रेसी और नए प्रत्याशी उतारने के कारण भी झेलनी पड़ी. मगध प्रमंडल के 26 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव पूर्व ही पार्टी टिकट बंटने के बाद ही विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो गई थी. लेकिन प्रतिबद्ध कांग्रेसियों ने पार्टी के सवाल पर चुनाव भर चुप रहना ही उचित समझा. चुनाव परिणाम सामने आए, कांग्रेसियों में उबाल आ गया और वे फूट पड़े. मगध प्रमंडल के वरिष्ठ कांग्रेसियों ने प्रदेश अध्यक्ष महबूब अली कैसर, प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक, विधायक दल के नेता अशोक राम तथा मगध प्रमंडल में टिकट बंटवारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले तत्कालीन विधायक अवधेश कुमार सिंह पर हार का ठीकरा फोड़ डाला. मगध प्रमंडल के 26 विधानसभा क्षेत्रों में अधिकांश पर कांग्रेस प्रत्याशियों की ज़मानत तक ज़ब्त हो गई.

जे के पालित, चिरागुद्दीन रहमानी, अवधेश सिंह

मात्र तीन विधानसभा क्षेत्र, वारिसलीगंज की प्रत्याशी अरुणा देवी 36953, हिसुआ की प्रत्याशी नीतू सिंह 28820 और वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी अवधेश कुमार सिंह 21127 मत लाकर अपनी ज़मानत बचा पाए. उपरोक्त प्रत्याशियों सहित छह प्रत्याशी ही दस हज़ार के अधिक मत प्राप्त कर पाए.

कांग्रेस के बाकी प्रत्याशियों को मिले मतों के बारे में उल्लेखनीय कुछ भी नहीं है. मगध प्रमंडल में कांग्रेस की इस दुर्गति के लिए वहां के कांग्रेसियों ने प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों को ज़िम्मेवार ठहराया है. कांग्रेसियों का कहना है कि सबसे बड़ी लापरवाही टिकट चयन में की गई तथा टिकट बेचे गए. कई ऐसे प्रत्याशियों को टिकट दिया गया जो हाल ही में कांग्रेस में आए थे. यदि पार्टी के ज़मीनी नेताओं और कार्यकर्ताओं को टिकट दिया गया होता तो कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर होता. पूर्व विधायक जय कुमार पालित ने कहा है कि पार्टी की बिहार में विधानसभा चुनाव में शर्मनाक हार के लिए स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन बी के हरि प्रसाद व ऑस्कर फर्नांडीज के साथ-साथ प्रदेश अध्यक्ष चौधरी महबूब अली कैसर और कांग्रेस विधायक दल के नेता अशोक कुमार को पदमुक्त करने की मांग करते हुए कहा है की चुनाव लड़ने के लिए प्रत्येक कांग्रेस प्रत्याशी को 25 से 35 लाख तक की राशि दी गई . इस राशि में से इन लोगों ने चुनाव में कितना ख़र्च किया, इसकी जांच होनी चाहिए और शेष राशि की वसूली कर पार्टी फंड में जमा किया जाना चाहिए. पूर्व सांसद एवं मंत्री रंजीत सिंह, पूर्व विधायक मो. खान अली तथा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य राधेश्याम सिंह ने पार्टी प्रत्याशी तय करने के पीछे रहे कारणों की जांच करने की मांग की है.

पार्टी के पूर्व मंत्री, सांसद व पूर्व विधायकों के सुझाव को नज़र अंदाज़ किया गया, जिसके कारण केंद्रीय चयन समिति के समक्ष सही बात नहीं जा सकी और ग़लत व्यक्तियों को टिकट दिया गया. वहीं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे नागेन्द्र ने जय कुमार पालित, पूर्व सांसद राजेश सिंह तथा गया ज़िला अध्यक्ष चिरागुद्दीन रहमानी को पार्टी विरोधी कार्य करने के आरोप में छह सालों के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया है. इस कार्रवाई से मगध प्रमंडल के पांच ज़िलों के कांग्रेसियों में गुस्सा बढ़ गया है. एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोपों का सिलसिला जारी है.

feedback@chauthiduniya.com

एक नज़र इधर भी

अधूरा है गंगा पर पुल का सपना

खगड़िया-मुंगेर के बीच गंगा नदी पर निर्माणाधीन पुल के निर्माण में हो रहे विलंब के कारण लोगों में नाराज़गी है. स्थानीय लोगों का कहना है कि वर्षों से निर्माण कार्य की मंद गति से जहां लोग परेशान हैं वहीं अवैध नाव परिचालन करने वाले चांदी काटने में व्यस्त हैं. अगर जल्द ही पुल का निर्माण करा दिया जाए तो लोगों के लिए मुंगेर आना-जाना आसान हो जाएगा. *-सूर्य नारायण भारती*

जाम से परेशान जनता

खगड़िया शहर में जाम की समस्या विकराल रूप धारण करती जा रही है. ट्रेफिक व्यवस्था दुरूस्त न होने के कारण अन्य जगहों पर जाम की समस्या तो बनी रहती है. रेलवे के पूर्वी केबिन पर लगातार जाम की वजह से लोगों को एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचने में घंटों लग जाते हैं. स्थानीय लोगों ने पूर्व केबिन पर उपरगामी पुल निर्माण कराने के साथ-साथ शहर के अन्य जगहों पर यातायात नियम बहाल रखने के लिए ट्रेफिक पुलिस की तैनाती की मांग की है. *-मो. इरफान*

नहीं मिलता पावर सब-स्टेशन का लाभ

मांझी पावर सब स्टेशन का शिलान्यास पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के प्रयासों से विगत 4 साल पूर्व किया गया था. इस विद्युत पावर सब-स्टेशन का विधिवत उद्घाटन नहीं हो सका है. मांझी में कुछ घरों में बल्ब तो लटका दिये गए हैं लेकिन विद्युत की आपूर्ति नाम मात्र की जाती है. पुराने खंभे और जर्जर तारों के फैले जाल के नीचे लोग मजबूरी से गुज़रते हैं. मांझी पावर सब स्टेशन के नजदीक पीसीओ चलाने वाले एक दुकानदार विद्यार्थी ने बताया कि विगत 15.07.2010 को विद्युत आपूर्ति के लिए मांझी बंद किया गया था, लेकिन ज़िले के वरीय पदाधिकारियों के आश्वासन के अलावा कुछ भी नहीं मिला. उल्टे बंद का नेतृत्व करने वाले बृज किशोर पांडेय उर्फ़ बुल्लू बाबा के साथ अन्य 5 व्यक्तियों पर प्राथमिकी भी दर्ज करा दी गई. *-धनंजय पांडेय*

नकली खाद-बीज की बिक्री से किसान हताश

रबी फसल की बोआई शुरू हो गयी है. इसके साथ ही क्षेत्र के प्रमुख बाज़ारों में असली और नकली खाद-बीजों की बिक्री जारी है. किसानों के समक्ष समस्या यह है कि वह नकली खाद की पहचान कैसे करें? कृषि विभाग के अधिकारियों के उदासीन रवैये के कारण प्रतिवर्ष किसान खाद व्यवसायियों के हाथों ठगे जा रहे हैं. सही व उपयुक्त खाद-बीज न मिलने पर किसानों की बोई गई फसलों की उत्पादकता प्रभावित होती है. इतना ख़र्च और मेहनत के बावजूद किसानों को निराशा हाथ लगती है. उर्वरकों की जानकारी देने की जवाबदेही किसान सलाहकार एवं कृषि विशेषज्ञों की है. इनकी लापरवाही का ख़ामियाज़ा किसानों को भुगतान पड़ रहा है. *-ललन प्रसाद*

नक्सली क्षेत्र की तस्वीर बदली

कभी लड़कियों का नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्कूल जाना मुश्किल माना जाता था. लेकिन अब बदली परिस्थितियों ने ग्रामीण क्षेत्रों के हालात भी बदल दिए हैं. गांव की लड़कियां साइकिल से दूर-दराज के स्कूलों मे भी जा रही हैं . गया ज़िले के गुरारु प्रखंड के मथुरापुर-गुरारु की वीरान सड़कों पर साइकिल से लड़कियां पढ़ने के लिए किसी भी स्कूल में जाने से नहीं हिचकिचातीं. बदले परिवेश मे ग्रामीण क्षेत्रों में आए इस बदलाव से लड़कियों और उनके अभिभावकों का आत्मविश्वास बढ़ा है . *- सुदर्शन कुमार*

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

Postal Regn. No. DL/ND-11/6139/2009-11, RNI No. DELHIN/2009/30467

कई नामी कंपनियों के रेपर को कोलकाता में तैयार करके पश्चिम बंगाल एवं बिहार के सीमांचल के इलाक़ों में मकई बीज से भरकर बाजारों में उतारा जाता है.

सारण

चीनी मिलों पर टिकी हैं उम्मीदें

जियेन्द्र कुमार

सारण प्रमंडल के पश्चिमी हिस्से सीवान व गोपालगंज को पूर्व में गन्नाचल के नाम से जाना जाता था. अंग्रेजों के ज़माने में यहां छह चीनी मिलें स्थापित की गई थीं. ऐसी ही एक मिल है जो सारण के मढ़ौरा में स्थित है. एक दौर था जब सारण सुगर मिल को एक अलग रुतबा हासिल था. इन क्षेत्रों के किसानों के लिए नकदी फ़सल गन्ना थी. किसानों की बेटी की शादी से लेकर बच्चे की पढ़ाई, सब कुछ इसी फ़सल पर निर्भर था. चीनी मिलों के बंद हो जाने से किसानों के लिए गन्ना की खेती सरदर्द बनने लगी. आज हालत यह है कि गन्ना की फ़सल से किसानों का मोहभंग हो गया है. जो चीनी मिलें चालू हालत में हैं, वे गन्ना किसानों की गाढ़ी कमाई के पैसे समय पर देने में आनाकानी करती हैं. इसलिए किसानों ने ईख की खेती करना लगभग छोड़ ही दिया है. आज चीनी मिलें भयंकर आर्थिक संकट से गुज़र रही हैं. विगत वित्तीय वर्ष में बिहार सरकार ने गोपालगंज के किसानों के लिए पहली बार 5 करोड़ 44 लाख रुपये का पैकेज दिया. इसमें 90 लाख रुपये ख़र्च न होने से वापस करने पड़े. सारण के मढ़ौरा क्षेत्र में भी पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूढ़ी के प्रयासों से उन्नत गन्ना उत्पादन के निमित ज़ोर–शोर से गन्ने की खेती किसानों ने की थी लेकिन मढ़ौरा चीनी मिल के चालू न हो पाने के कारण किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया. आंकड़ों पर ग़ौर किया जाए तो 1.28 अरब 52 हज़ार रुपये का पैकेज गन्ना को बढ़ावा के लिए सरकार ने दिया लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ.आज भी गोपालगंज क्षेत्र में किसान चीनी मिलों की मनमानी के कारण परेशान हैं. ज़िले में संचालित चीनी मिलों में सासामुसा, सिधवलिया व गोपालगंज की चीनी मिलों के प्रबंधन नीति से यहां का कृषक समुदाय त्रस्त है. गन्ना की कम तौल और समय पर चालान का भुगतान मिलने से उनका इस फसल के प्रति मोहभंग कर रहा है. इसके बदले आज यहां के किसानों ने अपने खेतों में औषधीय फसलें लगानी शुरू कर दी हैं. कुछ किसान धान, गेहूं और मक्का की फ़सल लगाकर गन्ना की भरपाई कर रहे हैं. बिहार सरकार के तत्कालीन गन्ना विकास राज्यमंत्री गौतम सिंह के प्रयासों से इस क्षेत्र के किसानों को गन्ना की खेती के तरफ मोड़ने के उद्देश्य से नवंबर 2009 में 5.43 करोड़ 15 हज़ार का पैकेज दिया गया. प्रत्येक गांव के छ: किसानों को गन्ना की फ़सल लगाने के लिए अनुदान दिया गया. अनुदानित बीज पर जिन किसानें ने गन्ना लगाया, उनकी फ़सल का उत्पादन भरपूर हुआ लेकिन चीनी मिलों की मनमानी के कारण किसान आज भी गन्ने की खेती करने में संकोच कर रहे है. क्योंकि फ़सल भले ही कितनी अच्छी हो अगर किसान को उसकी कीमत न मिले तो क्या फ़ायदा? वहीं सीवान ज़िले के पंचरूखी व सीवान स्थित एसकेजी सुगर मिल के दशकों पूर्व बंद हो जाने से इस क्षेत्र के किसानों के समक्ष कृषि क्षेत्र में रोज़गार का संकट कायम हो गया है. आर्थिक बदहाली के कारण किसानों की हज़ारों एकड़ उपजाऊ भूमि जोत–आबाद के अभाव में दिनों–दिन बंजर होती जा रही है. भोजपुरी किसान विकास मोर्चा के संयोजक देव कुमार का कहना है कि दशकों पूर्व जब सीवान ज़िले की पचरूखी चीनी मिल चालू हालत में थी, उस समय छपरा के पश्चिमी हिस्से से लेकर सीवान ज़िले के अधिसंख्य भू–भाग में गन्ने की खेती होती थी. लेकिन चीनी मिल के बंद हो जाने से इन क्षेत्रों की उपजाऊ ज़मीन बर्बाद होती जा रही है. यहां के किसानों की हालत कमज़ोर होती जा रही है. कृषि क्षेत्र में रोज़गार का संकट और पारिवारिक समस्याओं के चलते कृषक परिवार के युवा काम की तलाश में अन्य प्रदेशों में पलायन करने को मजबूर हैं. इनका कहना है कि बिहार में नीतीश सरकार ने पिछले पांच वर्षों में सड़क, क़ानून व्यवस्था पर तो काम किया लेकिन कृषि की हालत में सुधार पर समुचित ध्यान नहीं दिया है. सरकार द्वारा चलाये जा रहे बागवानी मिशन कार्यक्रम में किसानों को लाभ मिलना टेढ़ी खीर साबित हो रहा है. वहीं इसका लाभ किसानों के बदले बिचौलिए उठा रहे हैं. इस पूरे खेल में अधिकारियों की भी मिली–भगत रहती है. कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए खाद व बीज के दामों में हो रही अप्रत्याशित बृद्धि को रोकने की दिशा में ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है. यह बात शत–प्रतिशत सत्य है कि बिहार में कृषि के विकास से ही रोज़गार के संकट दूर हो सकते हैं. अगर उन्हें अपने ही राज्य में रोज़गार मिल जाए तो यहां के लोग सुदूर प्रदेशों में काम की तलाश में पलायन करने की समस्या से निजात पा सकते हैं.

अब सारण के किसान अपने खेतों मे भूलकर भी गन्ने की फसल नहीं लगाते. लेकिन पहले ऐसा नहीं था. इनकी यह स्थिति पहले बेहतर थी. एक समय था जब ज़िले के मढ़ौरा, तरैया, मकेर, परसा, दरियापुर, अमनौर, गड़खा व मशरक आदि क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर हज़ारों हेक्टेयर भूमि में गन्ने की खेती की जाती थी. गन्ना इस इलाके के लाइफ लाईन के रूप में जाना जाता था. सरकारी निष्क्रियता व स्थानीय जनप्रतिनिधियों के मनमानी वाले रवैये के कारण सुगर मिलें बंद हुई हैं. और यहीं से इस क्षेत्र के हज़ारों किसानों के परिवारों की ज़िंदगी तबाह हो गई. राज्य में दूसरी बार नीतीश सरकार के सत्ता में आने के बाद मुख्यमंत्री ने अपनी प्राथमिकताओं में बंद चीनी मिलों को पुन: चालू करने की मंशा ज़ाहिर की है. इससे किसानों में एक नई आशा की किरण जगी है. ऐसा लगने लगा है कि इससे कृषि क्षेत्र में रोज़गार के अवसर पैदा होंगे तथा पलायन रोकने में कामयाबी मिलेगी. पर अभी तो यह सब उम्मीदें भर हैं.

feedbabk@bhauthiduniya.bom

मकई के असली-नकली बीज के चक्कर में पिसते किसान

नीरज कुमार सिंह

अच्छी पैदावार के लिए खेतों में पसीना बहाने वाले किसान इस बार मकई की बीज की ख़रीद को लेकर माथापच्ची कर रहे हैं. दरअसरल नकली बीजों का काला कारोबार करने वालों ने विगत वर्ष किसानों को असली बीज के पैकेट में मक्के के नकली बीज बेंचे, जिससे पैदावार सही नहीं हुई. बैंक व महाजनों से ब्याज पर पैसा लेकर किसानों ने मक्का इस ख्याल से लगाया था कि अच्छी पैदावार होने पर क़र्ज़ अदा हो जाएगा और गृहस्थी की अन्य ज़रूरतें भी पूरी हो जाएंगी, लेकिन उनका सपना पूरा नहीं हो सका. हालांकि इससे पहले भी किसान कई बार ठगी का शिकार हो चुके हैं.

मालूम हो कि सीमांचल के पूर्णिया किशनगंज, अररिया, कटिहार ज़िलों में विगत लगभग पांच वर्षों से मक्के की खेती ने काफ़ी ज़ोर पकड़ा है. इससे किसानों की आर्थिक स्थिति भी सुधरी है. यही वजह है पड़ोसी बंग्लादेश, पश्चिम बंगाल के कोलकाता, सिल्लीगुड़ी एवं पूर्वोत्तर के राज्यों में मक्के की अत्यधिक मांग व पूर्णिया के गुलाबबाग में अनाज की मंडियां हैं. पूर्णिया पूर्व प्रखंड स्थित दमका गांव के किसान मो. ज़हीर का कहना है कि पहले लोग मक्के की फ़सल होने के बाद कुछ अच्छे दानों के बीज के लिए रख लेते थे, बुआई के समय इसी घरेलू बीज का उपयोग किया जाता था, लेकिन पैदावार अच्छी नहीं होती थी. इसी बीच सिजेंटा 62–40, पायोनियर 30 भी 92, प्रोएग्रो, कारगिल 900 एम जैसे मक्के के उपयोग से अच्छी पैदावार होने से किसानों का इनके प्रति विश्वास बढ़ा. इसा का फायदा नकली बीज कंपनियों ने उठाया. गरुआ प्रखंड के किसान मो. मुस्ताक का कहना है कि हमें नामी कंपनी के बीज दगा दे जाते हैं. जबकि एक अधिकृत बीज बिक्रेता का कहना है कि कोई भी कंपनी नहीं चाहती है कि बाजार में उसकी साख पर बट्टा लगे. अनाधिकृत बिक्रेता नकली बीज के कारोबार करने वालों के साथ हो जाते हैं. जानकारी के अनुसार कई नामी कंपनियों के रेपर को कोलकाता में तैयार करके पश्चिम बंगाल एवं बिहार के सीमांचल के इलाक़ों में मकई बीज से भरकर बाजारों में उतारा जाता है. बीज विक्रेता अगर चाहें तो किसानों को बीज का पक्का बिल व असली बीज देकर इस कारोबार से बचा सकते हैं. आज कई नामी कंपनियों के के मिलते–जुलते नामों वाले मक्के के बीज बाजार में हैं.जैसे सिजेंटा 62–40 की तरह श्रीजेंटा व नुजिवीड 6607 की तरह 6707. इससे किसान भ्रमित हो जाते हैं. पूर्णिया ज़िला कृषि पदाधिकारी चंद्रशेखर सिंह का कहना है कि सरकारी बीज की तुलना में किसान कंपनियों के बीज पर अधिक भरोसा करते हैं. वहीं सरकारी बीज समय पर उपलब्ध नहीं हो पाता है, जबकि कुछ विशेष कंपनियों को ही बाज़ार में बीज बिक्री की अनुमति दी गई है. नकली बीजों का धंधा करने वाले दुकानदारों के विरुद्ध समय–समय पर कार्रवाई की जाती है. अगर कहीं शिकायत मिलती है तो आरोपी दुकानदारों के ख़िलाफ़ क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी. साथ ही किसानों को भी चाहिए कि वे अधिकृत बीज विक्रेताओं से ही बीज की ख़रीददारी करके केश–मेमो व पक्का बिल लें.

feedbabk@bhauthiduniya.bom

YOU'RE INVITED
10% Discount Diamond Jewellery (M.R.P.)
100% Discount Hallmark Gold Jewellery (Making Charges)
INVITES YOU FOR A
Exhibition CUM Sale
OF Diamond AND
Gold
JEWELLERY
Prop. : Sanjeet Soni
Exclusive Show room
D'damas
Celebrate Always
-: Venue :-
VINOD SONY JEWELLERY
Damrulal Durga Ashtan, Deo Market, Mungeriganj, Begusarai
Mob : 9031113944, 9835258815, Ph : 06243-240664
Who ever will bring this advertisement cutting will get a definite gift of 10-25% with the purchase of the jewellery
Very soon we will be coming up with Silver and gold wholes Jewellery